

प्रस्तावना

2.1 उद्योग के निर्माण उप-क्षेत्र में सतत सुधार और सेवा क्षेत्र में अधिक तेजी, उप-क्षेत्रों के निर्माण द्वारा पोषित; “वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपत्ति और व्यवसाय सेवाएं”; “व्यापार, होटलों, परिवहन और संप्रेषण”; और “समुदाय, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं”, भारतीय अर्थव्यवस्था की जारी विकास वृद्धि संवेग की प्रभावशाली विशेषताएं हैं। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) की वृद्धि में 2004-05 में कुछ नरमी आने के बावजूद, उभरते एशिया में, भारत तीव्रतम उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से था। अनुकूल निवेश वातावरण द्वारा प्रोत्साहित, अनुकूल कंपनी परिणामों, बढ़ते हुए विनिर्माण निर्यात, घरेलू माँग में वृद्धि और उदारीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आइ) व्यवस्था से औद्योगिक विकास फैला। यह, निवेशों में तेजी को रेखांकित करते हुए गैर खाद्य ऋण में सुदृढ़ सुधार, बढ़े हुए उत्पादन और पूंजी बाजारों द्वारा पुष्ट पूंजीगत माल के आयात द्वारा पूर्ण किया गया। व्यापार विश्वास सूचकांक उत्साही थे। वित्तीय 2005-06 में दक्षिण-पश्चिमी मानसून की देरी के बावजूद, गैर खाद्य ऋण में उछाल, अपेक्षित निवेश क्रियाओं में गति और सेवा क्षेत्रों में मजबूती आगामी वित्तीय वर्ष के लिए समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण के उत्साह की पुष्टि करते हैं। रिजर्व बैंक ने, वार्षिक नीति वक्तव्य (अक्टूबर 2005) की मध्यावधि समीक्षा में, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के वृद्धि अनुमानों को अप्रैल 2005 में लगभग 7.0 प्रतिशत से 7.0-7.5 प्रतिशत तक और जनवरी 2006 में वार्षिक नीति वक्तव्य की तीसरी तिमाही समीक्षा में 7.5-8.0 प्रतिशत तक, कृषि संबंधी उत्पादन में सुधार के मूल्यांकन के अलावा औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में जारी उछाल के आधार पर, संशोधित कर दिया। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी एस ओ) द्वारा जारी किए गए अग्रिम अनुमानों ने 2005-06 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 8.1 प्रतिशत (1999-2000 मूल्य) आंकी है जो कि रिजर्व बैंक के अनुमानों के अनुरूप है। यह वृद्धि, कृषि क्षेत्र में तेजी उद्योग द्वारा दर्ज सुदृढ़ विकास और सेवा क्षेत्रों के प्रभावी कार्यनिष्पादन से समर्थित है।

2.2 कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तीव्र वृद्धि से मुद्रास्फीतीय दबाव ने, रिजर्व बैंक द्वारा, अपेक्षित विकास संवेग को कायम रखते हुए, एक प्रगतिशील जवाबी नीति का प्रतिपादन आवश्यक बना दिया। यद्यपि मुद्रास्फीति बहुत नियंत्रित रही, अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में जारी अनिश्चितता के कारण सावधानी

उचित है विशेषतः चूंकि तेल कीमतों की अंतरराष्ट्रीय वृद्धि का घरेलू अर्थव्यवस्था में प्रचलन/पास-थू अभी तक अधूरा है।

2.3 राजकोषीय वर्ष में वित्तीय बाजार स्थिर और व्यवस्थित रहे। माल एवं परोक्ष निर्यात सुदृढ़ रहे जबकि आयात विस्तार (तेल और पूंजीगत माल का आयात) उत्पादकता स्तरों और निर्यात विकास बढ़ा रहा है। 2001-02 से पहले तीन वर्षों में अधिशेष में रहने के बाद 2004-05 के दौरान चालू खाते ने घाटा दर्ज किया। शुद्ध परोक्ष अर्जन में उछाल चालू खाते की अधिशेष स्थिति को उक्त अवधि के दौरान रेखांकित करता है। फिर भी भुगतान संतुलन की स्थिति सतर्क निगरानी को जरूरी बनाता है। पूंजी अंतर्वाह की एक सकारात्मक विशेषता गैर-ऋण अंतर्वाह है; ऋण प्रवाह मध्यम दर्जे का रहा।

2.4 इस विहंगम रूपरेखा में, यह अध्याय, अब तक 2005-06 में समष्टि आर्थिक गतिविधियों का एक लेखा प्रस्तुत करता है। खंड I वास्तविक क्षेत्र की गतिविधियों पर प्रकाश डालता है। खंड II केन्द्रीय और राज्य सरकार के अर्थ प्रबंध की झाँकी प्रस्तुत करता है। खंड III मौद्रिक एवं ऋण गतिविधियों पर, मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों के साथ, ध्यान केंद्रित करता है। खंड IV वित्तीय बाजारों की गतिविधियों पर चर्चा करता है। खंड V बाह्य क्षेत्र और खंड VI समापन टिप्पणियों को रेखांकित करता है।

I. वास्तविक क्षेत्र

राष्ट्रीय आय

2.5 भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2004-05 के दौरान एक सुदृढ़ वृद्धि कार्यनिष्पादन को प्रदर्शित किया। 2003-04 में 8.5 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2004-05 (1999-00 कीमतें) के दौरान वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.5 प्रतिशत थी। “कृषि और सहायक गतिविधियों” से उत्पन्न वास्तविक जीडीपी की वृद्धि, 2004-05 के दौरान पिछले वर्ष के 10.0 प्रतिशत से 0.7 प्रतिशत तक तेजी से घटी। यह असमान और अपूर्ण दक्षिण-पश्चिम मानसून के अलावा 2003-04 के ऊंचे विकास के आधार प्रभाव के कारण हुआ (सारणी 2.1 और चार्ट II.1)। “कृषि और सहायक गतिविधियों” में वृद्धि हास को कुछ हद तक उद्योग और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों की मजबूती द्वारा सहारा मिला। तदनुसार, उद्योग से उत्पन्न वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4 प्रतिशत तक बढ़ी क्योंकि 2004-05 के दौरान, विनिर्माण क्षेत्र की अगुआई में, औद्योगिक वसूली विस्तरित और मजबूत हुई। विनिर्माण उप क्षेत्र में उछाल, अनुकूल घरेलू निवेश

सारणी 2.1 : वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद
(आधार वर्ष : 1999-2000)

(प्रतिशत)

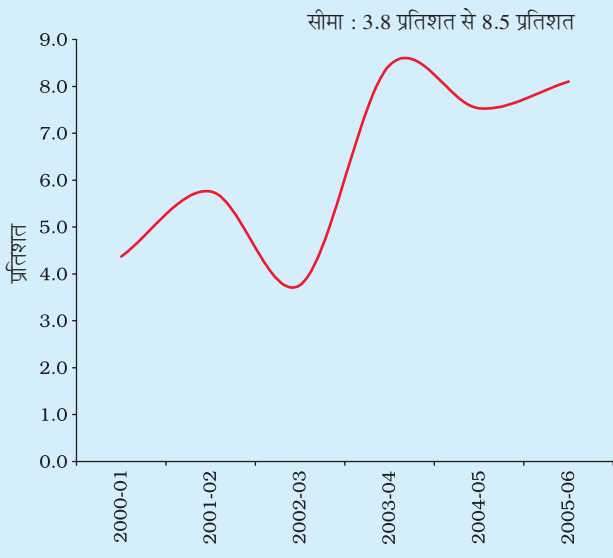
क्षेत्र	2001-02	2002-03	2003-04 अं. अनु.	2004-05 शी.अनु.	2005-06 अग्रि.अनु.
1	2	3	4	5	6
विकास दर					
1. कृषि और सहायक गतिविधियाँ	6.2	-6.9	10.0	0.7	2.3
1.1 कृषि	6.5	-7.8	10.7	(1.1) 0.7	..
2. उद्योग	2.4	6.8	6.6	7.4	8.0
2.1 विनिर्माण	2.5	6.8	7.1	(8.3) 8.1	9.4
2.2 खनन और उत्खनन	1.8	8.7	5.3	(8.9) 5.8	1.0
2.3 विद्युत, गैस और जल आपूर्ति	1.7	4.8	4.8	(5.3) 4.3	5.4
3. सेवाएं	6.8	7.3	8.5	10.2	10.1
3.1 व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट	9.6	6.7	10.2	(8.6) 8.1	11.1\$
3.2 परिवहन, भंडारण और संप्रेषण	8.3	13.7	15.2	(11.3) \$ 14.8	..
3.3 वित्तपोषण, बीमा, वास्तविक संपत्ति और व्यापार सेवाएं	7.3	8.0	4.5	9.2	9.5
3.4 निर्माण	4.0	7.7	10.9	(7.1) 12.5	12.1
3.5 समुदाय, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	3.9	3.8	5.4	(5.7) 9.2	7.9
4. सकल देशी उत्पाद लागत पर	5.8	3.8	8.5	7.5	8.1
				(6.0) (6.9)	
क्षेत्र संबंधी संघटना					
1. कृषि और सहायक गतिविधियाँ	24.4	21.9	22.2	20.8	19.7
2. उद्योग	19.3	19.9	19.5	19.5	19.5
3. सेवाएं	56.3	58.3	58.3	59.7	60.9
4. कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
ज्ञापन : वास्तविक जीडीपी घटक लागत पर (करोड़ रूपए)	19,78,055	20,52,586	22,26,041	23,93,671	25,86,587
.. नहीं उपलब्ध.	अं. अनु. : अनंतिम अनुमान.	शी.अनु. : शीघ्र अनुमान.	अग्रि.अनु. : अग्रिम अनुमान.		
\$ 'व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट' और 'परिवहन, भंडारण और संप्रेषण' शामिल हैं। 2004-05 में 1999-00 कीमतों पर विकास दर 10.6 प्रतिशत थी।					
सूचना : सी एस ओ द्वारा जून 2005 में जारी किए गए संशोधित अनुमानों के अनुसार (1993-94 कीमतों पर) कोषक में दिए गए आँकड़े विकास के प्रतिशत हैं।					
स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन					

वातावरण, विश्व उत्पादन में सुधार, एक उदारीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आइ) व्यवस्था और बढ़ते हुए विनिर्माण निर्यात द्वारा प्रेरित हुआ। अपने सभी उप क्षेत्रों के सुदृढ़ विकास कार्यनिष्पादन से समर्थित, सेवा क्षेत्र ने वृद्धि प्रक्रिया को स्थिर रखा और प्रभावी विकास को दर्ज किया।

2.6 राजकोषीय वर्ष 2005-06 एक उत्साहजनक वातावरण में शुरू हुआ। भारतीय मौसमविज्ञान विभाग (आइ एम डी) ने वर्ष 2005 के लिए दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी वर्षा का पूर्वानुमान सामान्य किया था (दीर्घावधि औसत [एल पी ए] 98 प्रतिशत +/- 4 प्रतिशत मॉडल त्रुटि के साथ)। औद्योगिक विकास निष्पादन में उछाल और कृषि उत्पादन में उन्नति के आकलन के साथ, जीडीपी विकास को समर्थन देने में सेवा

क्षेत्र की क्षमता, की पृष्ठभूमि में भारतीय अर्थव्यवस्था 2005-06 में एक मजबूत विकास निष्पादन के लिए तैयार है। इस कारण रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2005 में, वर्ष 2005-06 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में, जीडीपी विकास का पूर्वानुमान 7.0-7.5 प्रतिशत से, जनवरी 2006 में वार्षिक नीति वक्तव्य की तीसरी तिमाही समीक्षा में, अप्रैल 2005 में अपने प्रारंभिक अनुमान लगभग 7.0 प्रतिशत के बदले 7.5-8.0 प्रतिशत कर दिया। अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी वास्तविक जी डी पी विकास दरों का, इस परास (रेंज) के निकट पूर्वानुमान किया (सारणी 2.2)। 7 फरवरी 2006 को सीएसओ द्वारा प्रकाशित अग्रिम आकलनों के अनुसार, 2005-06 के लिए वास्तविक जीडीपी विकास दर का पूर्वानुमान 8.1 प्रतिशत है (आधार

चार्ट II.1 : कारक लागत पर जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर (1999-2000 की कीमतों पर)



सारणी 2.2 : वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में विकास, 2005-06 : भारत के लिए पूर्वानुमान \$

(प्रतिशत)

एजेंसी	प्रारंभिक	संशोधित / नवीनतम	अनुमान का महीना
1	2	3	4
एशियाई विकास बैंक	6.9	6.9	सितंबर 2005
निगरानी केंद्र	6.6	7.8	मध्य-फरवरी 2006
भारतीय अर्थव्यवस्था			
भारतीय उद्योग संघटन	7.2	8.0 से ऊपर	फरवरी 2006 की समालपन
ऋण साखदर सूचना	7.0	7.0	सितंबर 2005 की समालपन
राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद	7.2	7.8	प्रारंभिक फरवरी 2006
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	6.7	7.1	सितंबर 2005
रिजर्व बैंक	लगभग 7.0	7.5-8.0	जनवरी 2006*

जापन :

परास	6.6-7.2	6.9-8.0
------	---------	---------

\$ जीडीपी का पूर्वानुमान आधार वर्ष 1993-94 पर आधारित है, सिवाय सीएमआई के और सीआईआई के नवीनतम पूर्वानुमानों के जो आधार वर्ष 1999-2000 पर आधारित हैं।
* वर्ष 2005-06 के लिए, वार्षिक नीति की तीसरी तिमाही समीक्षा।

वर्ष : 1999-2000) जो कि रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विकास अनुमानों के निकट है। क्षेत्रवार स्तर पर, कृषि संबंधी और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास त्वरित हुए, परवर्ती अपने दो उप-क्षेत्रों, अर्थात्, विनिर्माण और “विद्युत, गैस और जल आपूर्ति”, के विकास में सुधार को दर्शाता है। तथापि, 2005-06 में सेवाओं में वृद्धि, 2004-05 की बनिस्बत, थोड़ी कम रही। यह, “समुदाय, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं”, “व्यापार, होटलों, परिवहन और संप्रेषण” और निर्माण के उप-क्षेत्रों में अवत्वरण, उप-क्षेत्र “वित्तपोषण, बीमा, वास्तविक संपत्ति और कारोबार सेवाएं” के विकास दर में सुधार के बावजूद, के कारण हुआ (सारणी 2.1)। वास्तविक जीडीपी के त्रैमासिक विकास दरों के नवीनतम उपलब्ध आंकड़े (1999-2000 कीमतों पर) दर्शाते हैं कि वास्तविक

जीडीपी विकास की दरें, 2005-06 के पहले तीन तिमाहियों में, पिछले वर्ष की अनुरूप तिमाहियों की तुलना में, उच्चतर हैं। 2005-06 की तीसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी विकास दरों में वृद्धि, 2004-05 की अनुरूप तिमाही के मुकाबले, कृषि संबंधी क्षेत्र के विकास में एक तीव्र समुत्थान द्वारा प्रेरित थी। 2005-06 की तीसरी तिमाही के दौरान उद्योग और सेवा क्षेत्रों ने अपनी विकास दरों में मंदी दर्ज की (सारणी 2.3)।

2.7 इस दर से बढ़ता भारत, एशिया की उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, एक तीव्रगति से विकसित अर्थव्यवस्था, बना रहेगा (सारणी 2.4)।

सारणी 2.3 : सकल घरेलू उत्पाद की त्रैमासिक विकास दरें (1999-2000 कीमतों पर)

(प्रतिशत)

उद्योग	2004-05			2005-06		
	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही
1	2	3	4	5	6	7
1. कृषि और सहायक गतिविधियाँ	3.5	-0.2	-1.2	1.4	2.4	3.4
2. उद्योग	6.6	8.0	8.1	9.9	6.7	7.1
2.1 विनिर्माण	6.6	8.3	9.2	11.3	8.6	8.4
2.2 खनन और उत्खनन	8.2	6.0	5.7	3.7	-1.9	0.6
2.3 विद्युत, गैस और जल आपूर्ति	4.9	7.9	3.1	6.9	2.2	4.4
3. सेवाएं	10.1	8.4	10.7	10.0	10.0	9.7
3.1 व्यापार, होटल, परिवहन और संप्रेषण	10.6	11.2	9.7	11.7	11.2	10.3
3.2 वित्तपोषण, बीमा, वास्तविक संपत्ति और कारोबार सेवाएं	8.8	7.5	9.7	8.7	9.8	9.1
3.3 निर्माण	9.9	7.9	22.0	12.4	12.3	11.5
3.4 समुदाय, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	10.7	4.8	8.5	7.0	7.3	8.1
4. घटक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद	7.9	6.7	7.0	8.1	8.0	7.6

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

सारणी 2.4 : उत्पादन विकास : क्षेत्र-पार तुलना

(प्रतिशत)

देश	औसत 1997-2005	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विश्व	3.8	4.2	2.8	3.7	4.7	2.4	3.0	4.0	5.1	4.3
उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ	2.7	3.5	2.6	3.5	3.9	1.2	1.5	1.9	3.3	2.5
अन्य उभरते बाजार और विकासशील देश	5.2	5.2	3.0	4.0	5.8	4.1	4.8	6.5	7.3	6.4
अर्जेंटीना	2.0	8.1	3.8	-3.4	-0.8	-4.4	-10.9	8.8	9.0	7.5
बांग्लादेश	5.4	5.3	5.0	5.4	5.6	4.8	4.8	5.8	5.8	5.7
ब्राजील	2.3	3.3	0.1	0.8	4.4	1.3	1.9	0.5	4.9	3.3
चिली	3.9	6.6	3.2	-0.8	4.5	3.4	2.2	3.7	6.1	5.9
चीन	8.4	8.8	7.8	7.1	8.0	7.5	8.3	9.5	9.5	9.0
भारत	5.9	5.0	5.8	6.7	5.4	3.9	4.7	7.4	7.3	7.1@
इंडोनेशिया	2.3	4.5	-13.1	0.8	4.9	3.8	4.4	4.9	5.1	5.8
मलेशिया	4.2	7.3	-7.4	6.1	8.9	0.3	4.4	5.4	7.1	5.5
मैक्सिको	3.5	6.7	4.9	3.9	6.6	-0.2	0.8	1.4	4.4	3.0
पाकिस्तान	4.3	1.8	3.1	4.0	3.0	2.5	4.1	5.7	7.1	7.4
फ़िलीपीन्स	3.8	5.2	-0.6	3.4	4.4	1.8	4.4	4.5	6.0	4.7
श्री लंका	4.5	6.4	4.7	4.3	6.0	-1.5	4.0	6.0	5.4	5.3
थाइलैंड	2.4	-1.4	-10.5	4.4	4.8	2.2	5.3	6.9	6.1	3.5

अ : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अनुमान।

@ जैसा कि वर्ष 2005-06 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की तीसरी तिमाही समीक्षा में निर्दिष्ट किया गया, भारतीय रिज़र्व बैंक का वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए अनुमान 7.5-8.0 प्रतिशत है।

स्रोत : विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, सितंबर 2005।

बचत और निवेश

2.8 सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उच्चतर सकारात्मक बचत दर दर्ज करने और निजी कंपनी क्षेत्र के बचत दर में सुधारों के कारण, सकल घरेलू बचत (जीडीएस) की दर में, चालू बाजार मूल्यों पर

जीडीपी के अनुपात में, भरपूर वृद्धि हुई, 2002-03 में 26.5 प्रतिशत से 2003-04 में 28.9 प्रतिशत और 2004-05 में 29.1 प्रतिशत तक (सारणी 2.5 और चार्ट II.2)। 29.1 प्रतिशत जीडीएस की दर उच्चतम प्राप्त दर थी। घरेलू क्षेत्र 2004-05 में, अपने 22.0

**सारणी 2.5 : सकल घरेलू बचत और निवेश
(आधार वर्ष : 1999-2000)**

(चालू बाजार कीमतों पर जीडीपी का प्रतिशत)

परिवर्ती	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 अनं.अनु.	2004-05 शी.अनु.
1	2	3	4	5	6	7
1. सकल घरेलू बचत (जीडीएस) (1.1+1.2+1.3)	24.9	23.5	23.6	26.5	28.9	29.1
1.1 घरेलू बचत	21.3	21.2	22.0	23.1	23.5	22.0
a) वित्तीय आस्तियाँ	10.5	10.2	10.8	10.3	11.5	10.3
b) शारीरिक आस्तियाँ	10.7	11.0	11.2	12.7	11.4	11.7
1.2 निजी कंपनी क्षेत्र	4.5	4.1	3.6	4.1	4.4	4.8
1.3 सार्वजनिक क्षेत्र	-0.9	-1.8	-2.0	-0.7	4.1	2.2
2. सकल घरेलू पूंजी निर्माण (जीडीसीएफ) #	26.0	24.2	23.0	25.3	27.2	30.1
3. बचत-निवेश शेष (1-2)	-1.1	-0.6	0.6	1.2	1.6	-1.0
4. सकल पूंजी निर्माण (4.1+4.2+4.3+4.4)	26.1	24.3	24.3	25.3	26.3	28.5
4.1 घरेलू क्षेत्र	10.7	11.0	11.2	12.7	12.0	11.7
4.2 निजी कंपनी क्षेत्र	7.2	5.7	5.6	5.8	6.8	8.2
4.3 सार्वजनिक क्षेत्र	7.5	6.9	6.9	6.2	6.5	7.2
4.4 बहुमूल्य @	0.8	0.7	0.6	0.6	5.6	0.9

अनं. अनु. : अर्न्तम अनुमान.

शी.अनु. : शीघ्र अनुमान.

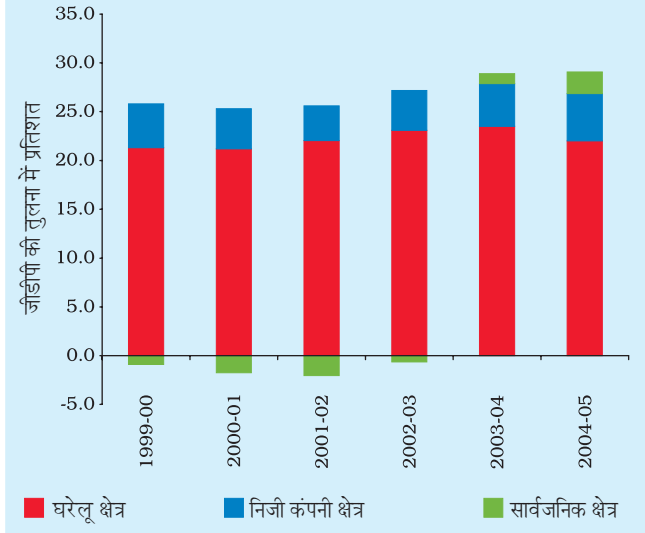
वृद्धियों और चूक के लिए समायोजित। @ कलाकृतियों और पुरातन वस्तुओं को छोड़कर मूल्यवान वस्तुओं के अभिग्रहण पर किए गए खर्च को बहुमूल्य प्रतिपादित करता है।

टिप्पणी : 1) कोष्ठक में दिए गए आँकड़े, सीएसओ द्वारा जनवरी 2005 में जारी किए गए शीघ्र अनुमानों से संबंधित हैं (आधार वर्ष : 1993-94)।

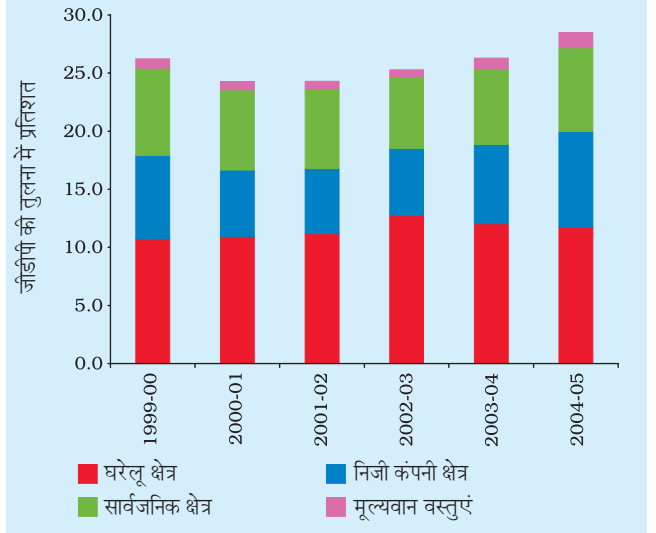
2) आँकड़ों का योग, पूर्ण करने के कारण, संभवतः जोड़ के बराबर न हो।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन.

चार्ट II.2: संस्थागत स्रोतों द्वारा बचत
(आधार वर्ष: 1999-2000)



चार्ट II.3: संस्थागत स्रोतों द्वारा सकल पूंजी निर्माण
(आधार वर्ष: 1999-2000)



प्रतिशत बचत दर से, जीडीएस का प्रमुख अंशदाता कायम रहा। 1999-00 से, घरेलू क्षेत्र की बचत दर, स्थूल आस्तियों के रूप में, वित्तीय आस्तियों के दर से अधिक रही। 2002-03 से निजी निगमों की बचत लगातार बढ़ रही है जो कि लाभों की महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अच्छे कार्यनिष्पादन के कारण 2003-04 में 1.0 प्रतिशत से बढ़कर, सार्वजनिक क्षेत्र ने भी 2004-05 में 2.2 प्रतिशत के सकारात्मक बचत दर को दर्ज किया।

2.9 सकल पूंजी निर्माण (जीएसएफ) की दर ने, सार्वजनिक और निजी कंपनी निवेशों में सुधार के कारण 2004-05 में, 2003-04

की अपेक्षा, उल्लेखनीय रूप से सुधार दर्ज किया। निवेश दर में वृद्धि, बचत दर की वृद्धि से भी अधिक थी। इसका परिणाम, 2004-05 में समग्र बचत-निवेश शेष में 1.0 प्रतिशत घाटे में, 2003-04 में 1.6 प्रतिशत अधिशेष की तुलना में, हुआ। (सारणी 2.6 और चार्ट II.3)

2.10 उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों द्वारा बताए गए उत्तम कार्यनिष्पादन, हाल की ऊंची विकास दर के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। वास्तव में, चीन और अन्य उभरते एशियाई देशों की तुलना में जहाँ उच्च विकास विनिर्माण क्षेत्र द्वारा मार्गदर्शित है, सेवा क्षेत्र हाल के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास प्रेरक के रूप में उभरा है। भारत में विनिर्माण

सारणी 2.6 : बचत-निवेश जमाशेष
(आधार वर्ष : 1999-2000)

(चालू बाजार कीमतों पर जीडीपी का प्रतिशत)

मद	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 अं. अनु.	2004-05 शी. अनु.
1	2	3	4	5	6	7
बचत-निवेश जमाशेष (जीडीपी-जीडीसीएफ)	-1.1	-0.6	0.6	1.2	1.6	-1.0
निजी क्षेत्र *	7.8	8.6	8.8	8.6	9.0	6.9
सार्वजनिक क्षेत्र *	-8.3	-8.7	-8.9	-6.8	-5.5	-5.0
चालू खाता जमाशेष	-1.0	-0.6	0.7	1.3	2.3	-0.8
ज्ञापन :						
बहुमूल्य@	0.8	0.7	0.6	0.6	0.9	1.3

* निजी और सार्वजनिक निवेश सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) को बताते हैं; वृटियों और चूक समायोजित नहीं हैं।

@ सकल पूंजी निर्माण में शामिल किए गए बहुमूल्य के अधिग्रहण पर किए गए खर्च को बहुमूल्य प्रतिपादित करता है।

जीडीएस : सकल घरेलू बचत, जीडीसीएफ : सकल घरेलू पूंजी निर्माण

अं. अनु. : अर्न्तम अनुमान, शी. अनु. : शीघ्र अनुमान.

टिप्पणी : सीएसओ और रिजर्व बैंक आंकड़ों से व्युत्पन्न वृटियों और चूक के कारण घटक जोड़ के बराबर नहीं हैं।

ने, उद्योग के अंदर, पिछले तीन वर्षों में प्रभावी कार्यनिष्पादन दर्ज किया। और इसके अतिरिक्त, 2004-05 के दौरान प्राप्त 29.1 जीडीएस की दर, जो कि 1950 से अबतक उच्चतम स्तर पर है, अत्यंत प्रोत्साहक है। 2004-05 के दौरान 28.5 प्रतिशत पर निवेश दर भी उल्लेखनीय है। तथापि, बचत और निवेश दरों को, ऊंची विकास गति को बरकरार रखने के लिए, ऐसे ऊंचे स्तरों पर बनाए रखना, एक चिंता का क्षेत्र है।

कृषि

2.11 2004-05 में प्राप्त बाधाओं के बाद, भारतीय कृषि 2005-06 में एक अनुकूल परिवर्तन के लिए तैयार है। वर्षा गतिविधि, यद्यपि मौसम की प्रारंभिक अवधि में मंद रही, बाद में आर्द्रता की मात्रा में सुधार के फलस्वरूप पुनर्जीवित हुई, जो कि खरीफ उत्पादन के लिए शुभ है। दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2005-06 के दौरान खाद्यान्न का कुल उत्पादन 209.3 मिलियन टन आँका गया जो कि, पिछले वर्ष के 204.6 मिलियन टन की तुलना में, 2.3 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है। कृषि मंत्रालय ने, फसलों की उपज बढ़ाने के लिए एक फसल-विशिष्ट कार्यनीति, जैसे अवस्थिति विशिष्ट अति-उपजाऊ प्रकार के प्रमाणित/दर्जेदार बीजों की समय से और पर्याप्त उपलब्धता, अंतर फसल को बढ़ावा, जल बचत पद्धतियों का प्रोत्साहन, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग और रोग प्रबंध प्रणाली, बनाई।

2.12 आइएमडी द्वारा 2005 के लिए सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून का पूर्वानुमान करने की पृष्ठभूमि में, मानसून का प्रारंभ देर से हुआ। यद्यपि शुरू में वर्षा गतिविधि धीमी थी, वह बाद में पुनर्जीवित हुई। मानसून की कालिक प्रगति अनियमित थी लेकिन उसका आकाशीय विस्तार संतोषजनक रहा। मानसून पुनर्जीवन के परिणामस्वरूप मिट्टी के साथ जलाशयों की आर्द्रता-मात्रा का आपूरण हुआ।

2.13 2005 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा का आकाशीय वितरण, 36 में से 32 मौसमी उप-विभागों में अधिक/सामान्य वर्षा और सिर्फ 4 में अपूर्ण / कम वर्षा दर्ज करते हुए, संतोषजनक रहा (सारणी 2.7 और चार्ट II. 4)। मानसून की अस्थायी प्रगति, जून के पहले तीन सप्ताहों में, संपूर्ण अगस्त और सितंबर 2005 के पहले सप्ताह के दौरान, एक बड़े वृष्टि-अभाव से अंकित रही। तथापि, जून के अंतिम सप्ताह, अधिकांश जुलाई और सितंबर 2005 के दूसरे और तीसरे सप्ताह में, देश में अधिक वर्षा गतिविधि होने से, मानसून की परिस्थितियों में स्पष्ट सुधार हुआ। दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु (जून 1 से सितंबर 30, 2005) के दौरान, संचयी क्षेत्र-भारित वर्षा, आइडीएम की

सारणी 2.7 : संचयी वर्षा

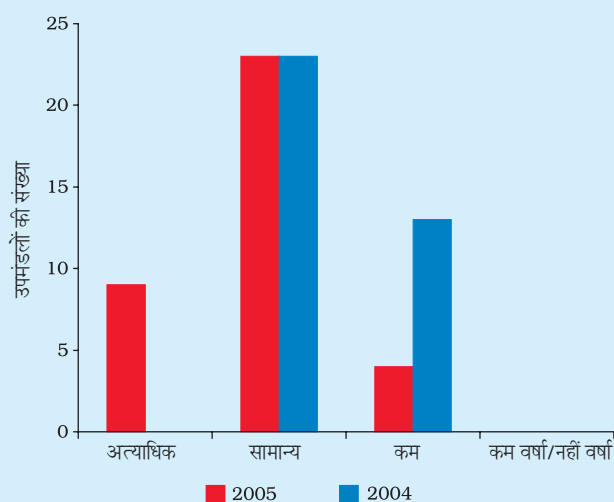
श्रेणी	उप विभागों की संख्या					
	दक्षिण-पश्चिम मानसून			उत्तर-पूर्व मानसून		
	2005	2004	2003	2005	2004	2003
	(जून 1 से सितंबर 30)			(अक्टूबर 1 से दिसंबर 31)		
1	2	3	4	5	6	7
आधिक्य	9	0	7	11	8	9
सामान्य	23	23	26	6	10	9
अपूर्ण	4	13	3	5	17	6
कम वर्षा/ नहीं वर्षा	0	0	0	14	1	12

स्रोत : भारतीय मौसमविज्ञान विभाग (आइ एम डी)।

भविष्यवाणी के साथ, दीर्घावधि औसत (एलपीए) से 1 प्रतिशत नीचे रही।

2.14 जून महीने के दौरान वर्षा दीर्घावधि औसत (एलपीए) से 12 प्रतिशत नीचे थी। तथापि, जुलाई के दौरान, जो कि बुआई प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, अधिक वर्षा हुई, अर्थात् एलपीए से 14 प्रतिशत ऊपर, जिसने बुआई प्रक्रियाओं को सहायक पृष्ठभूमि प्रदान की। एलपीए से नीचे 28 प्रतिशत की बड़ी अपूर्णता के साथ अगस्त में मानसून फिर से मंद था। सितंबर में वर्षा एलपीए से 17 प्रतिशत ऊपर थी जिसने देर से बोई गई फसलों को नमी की कमी से राहत दी। चार क्षेत्रों में से, दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा, मध्य भारत, उत्तर-पश्चिम भारत और दक्षिण प्रायद्वीप के ऊपर क्रमशः एलपीए की 110 प्रतिशत, 90 प्रतिशत और 112 प्रतिशत थी, जबकि उत्तर-

चार्ट II.4: दक्षिण-पश्चिम मानसून-संचित वर्षा (जून से सितंबर)



स्रोत: भारतीय मौसम विभाग

सारणी 2.8 : फसल-वार लक्ष्य / उपलब्धियाँ

(मिलियन टन)

फसल	2003-04		2004-05		2005-06	
	ल	उ	ल	अअ\$	ल	अअ@
	1	2	3	4	5	6
चावल	93	88.3	93.5	85.3	87.8	87.9
गेहूँ	76	72.1	79.5	72	75.5	73.1
मोटे अनाज	34	38.1	36.8	33.9	36.5	34.0
दालें	16	14.9	15.3	13.4	15.2	14.4
कुल खाद्यान्न	220	213.5	225.1	204.6	215.0	209.3
तिलहन	24.7	25.3	24.7	26.1	26.6	26.4
गन्ना	320	237.3	270	232.3	237.5	266.9
कपास*	15	13.9	15	17	16.5	16.5
जूट और मेस्ता**	12	11.2	11.8	10.5	11.3	10.7

ल : लक्ष्य। उ : उपलब्धि।
 अअ\$: चौथा अग्रिम अनुमान।
 अअ@ : दूसरा अग्रिम अनुमान।
 * मिलियन गट्टों में, प्रत्येक 170 किलोग्राम का।
 ** मिलियन गट्टों में, प्रत्येक 180 किलोग्राम का।
 स्रोत : कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

पूर्व भारत के ऊपर वह 20 प्रतिशत से अपूर्ण थी। उप-विभागों के स्तर पर, केवल एक उप-विभाग-झारखंड ने साधारण सूखे की स्थिति को दर्ज किया।¹ उत्तर-पूर्व मानसून (अक्टूबर 1 से दिसंबर 31, 2005) की प्रगति, एलपीए से ऊपर 10 प्रतिशत संचयी वर्षा से, पिछले वर्ष की अनुरूपी अवधि के दौरान एलपीए से नीचे 11 प्रतिशत

के विपरीत, संतोषजनक थी। 36 मौसमी उप-विभागों में से, संचयी वर्षा, 17 उप-विभागों में (पिछले वर्ष 18) अधिक/सामान्य और 19 उप-विभागों में (पिछले वर्ष 18) अपूर्ण/कम वर्षा/वर्षा नहीं, थी। 2005-06 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 215 मिलियन टन है (सारणी 2.8)।

खरीफ 2005

2.15 वर्ष 2004 के दौरान, खरीफ खाद्यान्नों के उत्पादन ने प्रतिकूल मानसून परिस्थितियों के कारण, पिछले वर्ष की अपेक्षा 12 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की। कृषि मंत्रालय द्वारा फरवरी 22, 2006 को प्रकाशित दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, खरीफ 2005 के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन, पिछले वर्ष की अपेक्षा 4.7 प्रतिशत वृद्धि को अंकित करते हुए, 108.2 मिलियन टन से अधिक अनुमानित किया गया। उच्चतर उत्पादन संभवतः चावल, अनाज और दालों के उत्पादन में वृद्धि के योगदान द्वारा है। वाणिज्यिक फसलों में, यद्यपि गन्ना, तिलहन, जूट और मेस्ता के उत्पादन उच्चतर होने की आशा है, कपास का उत्पादन, पिछले वर्ष प्राप्त स्तर से, संभवतः कुछ गिरावट बताएगा (सारणी 2.9)।

रबी 2005-06

2.16 दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, रबी खाद्यान्नों कुल उत्पादन 101.2 मिलियन टन आँका गया है, जो कि पिछले वर्ष में प्राप्त स्तर के लगभग करीब है। यद्यपि गेहूँ, दालों और मोटे

सारणी 2.9 : मौसमवार कृषि संबंधी उत्पादन

(मिलियन टन)

फसलें	खरीफ			रबी		
	2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06
	उ	अअ\$	अअ@	उ	अअ\$	अअ@
1	2	3	4	5	6	7
चावल	78.34	71.67	75.98	9.94	13.64	11.88
गेहूँ				72.11	72.00	73.06
मोटे अनाज	32.37	26.7	26.70	5.75	7.22	7.30
दालें	6.16	4.95	5.47	8.78	8.43	8.93
कुल खाद्यान्न	116.88	103.32	108.15	96.58	101.29	101.17
तिलहन	16.77	14.94	15.99	8.52	11.17	10.39
गन्ना	237.31	232.32	266.88
कपास*	13.87	17.00	16.45
जूट और मेस्ता**	11.23	10.49	10.65

.. नहीं उपलब्ध। * मिलियन गट्टों में, प्रत्येक 170 किलोग्राम का। ** मिलियन गट्टों में, प्रत्येक 180 किलोग्राम का।
 उ : उपलब्धि। अअ\$: चौथा अग्रिम अनुमान। अअ@ : दूसरा अग्रिम अनुमान।
 स्रोत : कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

¹ आइएमडी के अनुसार सामान्य स्थिति से सूखे की स्थिति को प्रतिशत में व्यक्त किया गया है और तदनुसार सूखे की स्थिति को भयंकर (50 प्रतिशत से अधिक), मंद (26-50 प्रतिशत) तथा अल्प (25 प्रतिशत तक) सूखे की श्रेणियों में बांटा गया है।

अनाजों का उत्पादन उच्चतर होने की आशा है, पिछले वर्ष की तुलना में, संभवतः चावल का उत्पादन निम्नतर रहेगा। 2005-06 में कृषि मंत्रालय ने, रबी फसलों की उपज बढ़ाने के लिए, एक फसल-विशिष्ट कार्यनीति बनाई। कार्यनीति में शृंखलाबद्ध उपायों को शामिल किया गया जैसे, अवस्थिति विशिष्ट अति-उपजाऊ प्रकार के प्रमाणित/दर्जेदार बीजों की समय से और पर्याप्त उपलब्धता (विशेषरूप से दड़म गेहूँ के मामले में), समय से बुआई पर जोर, अंतर फसल को बढ़ावा और जल बचत उपकरणों को प्रोत्साहन, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग, जमीन सुधारकों का प्रचार, बीज बोआई शून्य जोताई को प्रोत्साहन, बीज के साथ उर्वरक बोआई, उघड़ बोआई और उभरी क्यारी रोपक, एकीकृत अपतृण, कीट और रोग प्रबंध प्रणाली का संवर्द्धन, दर्जेदार रोपण सामग्री को सुनिश्चित करना और समयपूर्व परिपक्व किस्मों के अंतर्गत गन्नों के मामले में क्षेत्र बढ़ाना।

2.17 कृषि और सहयोग विभाग ने भी, शुष्क-भूमि पर खेती करने की समस्याओं को संबोधित करने के लिए, एक नई योजना की, “शुष्क-भूमि वर्षा-पोषित खेती प्रणाली की निरंतरता को बढ़ाने” के लिए, व्यवस्था की है। इस योजना के अंतर्गत प्रमुख जोर क्षेत्र हैं, कटाई, जल संरक्षण और उसका दक्ष उपयोग, मिट्टी आर्द्रता संरक्षण पर जोर, जैविक खादों का प्रयोग, सुधारी हुई शुष्क-भूमि खेती करने की प्रौद्योगिकी का वैकल्पिक प्रयोग और व्यवहार। अनाज केंद्रित फसल प्रणाली से विविधता को ज्यादा लाभदायक ऊंचे मूल्य और कम जल उपभोगी फसलें जैसे तिलहन, दालें, पुष्पात्पदन, औषधीय और सुरभित पौधों पर भी महत्व दिया गया। 2006-07 के लिए केंद्रीय बजट में, राष्ट्रीय उद्यानकृषि मिशन के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए के आबंटन का, आदर्श अग्रस्थ मंडियों को देश के विभिन्न हिस्सों में, सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल का प्रयोग करके, स्थापित करने का प्रस्ताव है। कृषि और सहयोग विभाग ने, मई 2005 में केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित, “सुधारों के विस्तार के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता” योजना, दसवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु, प्रौद्योगिकी प्रसार को सरल बनाने के लिए जो किकृषक संचालित एवं कृषक केंद्रित है, शुरू की।

खाद्यान्न, प्रापण, निकास और स्टॉक

2.18 2005-06 के दौरान (फरवरी 28, 2006 तक) लगभग 40 मिलियन टन खाद्यान्नों (चावल और गेहूँ) का प्रापण, पिछले वर्ष की अनुरूपित अवधि में प्राप्त से थोड़ा निम्नतर था। 2005-06 (अप्रैल 1 से दिसंबर 31, 2005) के दौरान चावल और गेहूँ की निकासी वैसे ही थी कि जैसे पिछले वर्ष की तुलनीय अवधि में।

तथापि, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी पी डी एस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओ डबल्यू एस) के अंतर्गत चावल और गेहूँ की निकासी उच्चतर थी। इसके विपरीत, खुला-बाजार बिक्री (ओ एम एस) के अंतर्गत निकासी में तीव्र गिरावट थी।

2.19 भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) और अन्य सरकारी एजेंसियों के पास खाद्यान्नों का कुल स्टॉक, जनवरी 1, 2006 को पिछले वर्ष की अनुरूपी अवधि में 21.7 मिलियन टन की तुलना में 11.2 प्रतिशत से गिरकर लगभग 19.3 मिलियन टन हुआ। (सारणी 2.10)

2.20 संतोषजनक दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व मानसून ऋतुओं के साथ बेहतर जलाशय स्थिति कृषि संबंधी उत्पादन के लिए शुभ संकेत है और कुल खाद्यान्न उत्पादन एक वर्ष पहले की बनिस्बत उच्चतर अपेक्षित है। जनवरी 1, 2006 को खाद्यान्न का स्टॉक, एक वर्ष पहले की अपेक्षा निम्नतर स्तर पर था।

उद्योग

2.21 वर्ष 2003-04 से अबतक औद्योगिक क्षेत्र का मजबूत कार्यनिष्पादन चालू वर्ष के दौरान, माँग के प्रवाह के कारण और समर्थ हुआ। औद्योगिक क्षेत्र की विकास गति को विनिर्माण उप-क्षेत्र से समर्थन मिला। यद्यपि वर्ष के दौरान, मूलभूत, पूंजीगत और उपभोक्ता माल क्षेत्र ने त्वरित वृद्धि दर्ज की, मध्यवर्ती माल क्षेत्र की कार्यनिष्पादन प्रोत्साहित नहीं रही। बढ़ता हुआ आयात घरेलू उद्योगों के कार्यनिष्पादन पर संभवतः अतिक्रमण करे क्योंकि बहुत से उद्योगों को अभी तक अर्थव्यवस्थाओं के मानदंड को प्राप्त करना है और वैश्वीकृत बाजार में उभरती स्पर्धा का सामना करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता को पाना है।

2.22 औद्योगिक पुनरुत्थान, जो अप्रैल 2002 में शुरू हुआ था, बाद के वर्षों में मजबूत हुआ (चार्ट II.5)। औद्योगिक विकास में सुधार, 2005-06 के दौरान अब तक (अप्रैल-दिसंबर) जारी रहा, मुख्यतः विनिर्माण उप-क्षेत्र द्वारा, बाहरी और घरेलू माँग में विस्तार, क्षमता परिवर्द्धन, वित्त की सहज में उपलब्धता और बढ़े हुए पूंजीगत माल के आयात के कारण, अवप्रेरित रहा। दूसरी ओर, खनन क्षेत्र ने वर्ष के दौरान, जुलाई 2005 से नकारात्मक कार्यनिष्पादन के कारण, मंद विकास दर्ज किया (सारणी 2.11)। 2005-06 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइ आइ पी) ने 7.8 प्रतिशत वृद्धि को दर्ज किया।

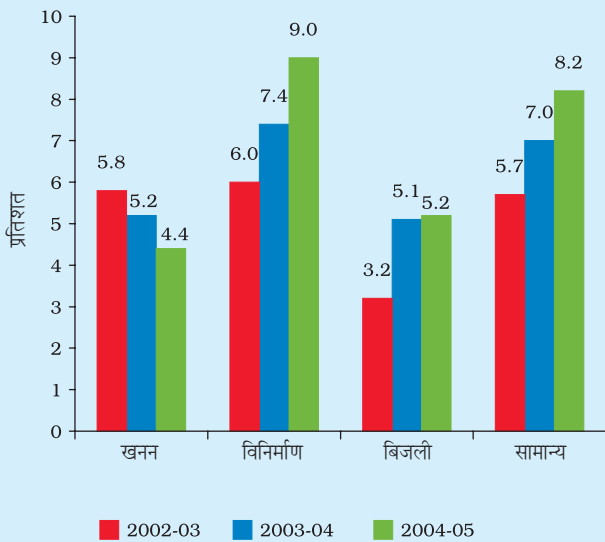
2.23 विनिर्माण उप-क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन में लगातार प्रमुख विकास चालक रहा। अप्रैल-दिसंबर 2005 के दौरान, द्वि-अंक स्तर विनिर्माण समूहों में, 17 में से 12 उद्योग समूहों ने सकारात्मक

सारणी 2.10 : खाद्य भंडार का प्रबंध

(मिलियन टन)

वर्ष / माह	खाद्यान्न का प्रारंभिक स्टॉक	खाद्यान्न का प्रापण	खाद्यानों का निकास				अंतिम स्टॉक	अतिरिक्त भंडार स्टॉक मानक \$
			पीडीएस	ओडबल्यूएस	ओएमएस-घरेलू	निर्यात		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2004								
अप्रैल	20.6	15.7	2.0	0.5	0.0	0.3	32.4	15.8
मई	32.4	3.0	2.3	0.6	0.0	0.1	32.3	
जून	32.3	1.4	2.3	1.0	0.0	0.1	30.6	
जुलाई	30.6	0.5	2.4	1.0	0.0	0.1	27.2	24.3
अगस्त	27.2	0.5	2.4	1.0	0.0	0.1	23.0	
सितंबर	23.0	0.2	2.5	1.0	0.0	0.1	20.3	
अक्टूबर	20.3	7.4	2.4	0.8	0.0	0.0	23.7	18.1
नवंबर	23.7	1.9	2.4	0.6	0.0	0.0	21.8	
दिसंबर	21.8	3.2	2.6	0.7	0.0	0.0	21.7	
2005								
जनवरी	21.7	3.9	2.7	0.8	0.0	0.0	21.5	16.8
फरवरी	21.5	2.3	2.7	0.9	0.0	0.0	20.0	
मार्च	20.0	1.7	2.7	1.7	0.0	0.0	18.0	
अप्रैल	18.0	14.0	2.4	1.0	0.0	0.0	28.5	16.2
मई	28.5	3.1	2.5	0.8	0.0	0.0	27.9	
जून	27.9	0.9	2.5	1.7	0.0	0.0	25.1	
जुलाई	25.1	0.4	2.8	0.8	0.1	0.0	21.4	26.9
अगस्त	21.4	0.9	2.6	0.8	0.1	0.0	18.4	
सितंबर	18.4	0.4	2.7	0.7	0.1	0.0	15.5	
अक्टूबर	15.5	7.6	2.2	0.5	0.0	0.0	19.8	16.2
नवंबर	19.8	2.7	1.8	0.5	0.1	0.0	19.0	
दिसंबर	19.0	3.4	2.3	0.7	0.2	0.0	19.3	
2006								
जनवरी	19.3	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	..	20.0
फरवरी	..	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	..	
जापन :								
2004-05 अप्रैल-दिसंबर		32.9	21.3	7.1	0.1	1.0		
2005-06 अप्रैल-दिसंबर		33.3	21.8	7.5	0.6	0.0		
.. नहीं उपलब्ध ।								
\$ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी में कायम रखे गए न्यूनतम अतिरिक्त भंडार स्टॉक मानकों को, मार्च 29, 2005 से, नई अतिरिक्त भंडार स्टॉक नीति के अंतर्गत, संशोधित किया गया।								
पीडीएस : सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ओडबल्यूएस : अन्य कल्याणकारी योजनाएँ। ओएमएस : खुला बाजार बिक्री।								
टिप्पणी : अंतिम स्टॉक आँकड़े, प्रारंभिक स्टॉक और प्रापण किए गए स्टॉक जोड़ने और निकासी को घटाने से प्राप्त आँकड़ों से भिन्न हो सकते हैं क्योंकि स्टॉकों में मोटे अनाज भी शामिल हैं।								
स्रोत : उपभोक्ता व्यवहार मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, भारत सरकार।								

चार्ट II.5: आइआइपी की क्षेत्रीय वृद्धि



वृद्धि दर्ज की। अन्य विनिर्माण उद्योगों ने, विभिन्न विनिर्माण क्षेत्र समूहों के बीच, 23.8 प्रतिशत उच्चतम वृद्धि दर्ज की, यद्यपि वस्त्र उत्पादों ने अप्रैल-दिसंबर 2005-06 के दौरान, विकास में 18.6 प्रतिशत का एक विशिष्ट त्वरण, पिछले वर्ष की अनुरूपी अवधि में 14.8 प्रतिशत की तुलना में दर्ज किया (सारणी 2.12)। मादक पेय, तंबाकू और संबंधित उत्पादों; आधारभूत धातु और मिश्रधातु; परिवहन उपकरण और कल पुर्जे; सूती कपड़े; तथा मशीनरी और उपकरणों ने भी उस अवधि के दौरान द्वि-अंकी विकास दर्ज किया।

2.24 प्रयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार, मध्यवर्ती माल क्षेत्र के सिवाय सभी क्षेत्रों ने, अप्रैल-दिसंबर 2005-06 के दौरान बेहतर विकास कार्यनिष्पादन, पिछले वर्ष के अनुरूपी अवधिकी तुलना में, दर्ज किया (सारणी 2.13)। फिनाइल, बेंजीन, उत्कृष्ट मिट्टी का तेल, रेल्वे माल, फेरो मैंगनीज, इत्यादि के नकारात्मक विकास के कारण आधारभूत माल ने मध्यम विकास दर्ज किया। उपभोज्य वस्तुओं ने,

सारणी 2.11: औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक-मासिक वृद्धि

(प्रतिशत)

माह / भार	सामान्य		विद्युत		खनन और उत्खनन		विनिर्माण	
	(100.00)		(10.17)		(10.47)		(79.36)	
	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अप्रैल	8.9	8.1	10.3	3.1	9.1	2.8	8.8	9.2
मई	6.8	10.8	3.1	10.5	5.3	5.2	7.5	11.3
जून	7.3	12.2	4.5	9.6	2.7	4.8	8.1	13.2
जुलाई	8.5	4.7	13.7	-0.9	4.2	-1.9	8.4	6.0
अगस्त	8.6	7.6	7.4	7.9	4.4	-2.5	9.1	8.5
सितंबर	9.8	7.2	7.7	-0.8	5.1	-1.9	10.5	8.9
अक्टूबर	10.6	9.1	3.5	7.7	6.2	-0.5	11.9	10.1
नवंबर	7.7	6.1	3.4	3.4	3.6	-0.6	8.6	7.0
दिसंबर	8.9	5.0	4.5	2.9	4.8	-1.8	9.8	5.9
जनवरी	7.5	..	2.4	..	2.6	..	8.6	..
फरवरी	5.9	..	-0.8	..	-1.6	..	7.4	..
मार्च	9.8	..	3.2	..	6.6	..	10.9	..
अप्रैल-दिसंबर	8.6	7.8	6.4	4.8	5.1	0.4	9.2	8.9

.. नहीं उपलब्ध।
स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

टिकाऊ और गैर टिकाऊ दोनों खंडों के मजबूत कार्यनिष्पादन द्वारा सहायता प्राप्त, विश्वासोत्पादक विकास प्रदर्शित किया। उपभोज्य गैर टिकाऊ वस्तुओं में विकास अधिकांशतः, 'मादक पेय, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद', वस्त्र उत्पाद, दूध पावडर, चाकलेट और चीनी मिष्ठान, चीनी, सल्फा दवाइयाँ, केश तेल, इत्यादि द्वारा प्रेरित हुआ। मध्यवर्ती माल क्षेत्र ने, कुछ सूती मदों, तैयार चमड़ों, कच्चे विस्कोस रेशों, जिलेटिन, कच्चे विस्कोस रेशों, तंतु-पाइपों और पेट्रोलियम उत्पादों, इत्यादि के अधिकांशतः नकारात्मक विकास के कारण, मंद कार्यनिष्पादन की पुष्टि की।

2.25 हाल की औद्योगिक उछाल की एक उल्लेखनीय विशेषता सुदृढ़ पूंजीगत माल क्षेत्र का द्वि-अंकी विकास है कि जिसने सबसे अधिक उत्प्लावक खंड के रूप में अपनी स्थिति दोबारा प्राप्त कर ली है। इस क्षेत्र ने अप्रैल-दिसंबर 2005-06 के दौरान 15.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो 2004-05 की उसी अवधि में दर्ज 13.8 प्रतिशत से अधिक थी। वस्त्र मशीनरी, जहाज निर्माण और मरम्मत, प्रयोगशाला और वैज्ञानिक उपकरण, इंजन, मशीन औजार, सामान संचालन के उपकरण, डम्पर, बॉयलर और बिजली वितरण ट्रांसफॉर्मर, इत्यादि के उच्चतर उत्पादन ने पूंजीगत माल क्षेत्र को सहारा दिया। पूंजीगत

सारणी 2.12 : विनिर्माण उद्योगों का विकास (2-अंक स्तर वर्गीकरण) - अप्रैल-दिसंबर 2005

20 प्रतिशत से ऊपर	10-20 प्रतिशत	0-10 प्रतिशत	नकारात्मक
1	2	3	4
1. अन्य विनिर्माण उद्योग (23.8)	1. वस्त्र उत्पाद (परिधान समेत) (18.6) 2. मादक पेय, तंबाकू और संबन्धित उत्पाद (16.4) 3. आधारभूत धातु और मिश्रधातु (15.0) 4. परिवहन उपकरण और कल पुर्जे (12.5) 5. मशीनरी और उपकरण परिवहन उपकरण के अलावा (10.5) 6. सूती वस्त्र (10.2)	1. रसायन और रासायनिक उत्पाद (9.7) 2. गैर धात्विक खनिज उत्पाद (9.4) 3. रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम और कोयला उत्पाद (3.8) 4. जूट और अन्य वनस्पति रेशे के कपड़े (2.7) 5. कागज और कागज उत्पाद (0.5)	1. ऊन, रेशम और मनुष्य-निर्मित रेशों के कपड़े (-0.1) 2. चमड़ा और चमड़ा और लोम उत्पाद (-1.5) 3. खाद्य उत्पाद (-2.2) 4. धातु उत्पाद और कल पुर्जे (-2.5) 5. लकड़ी और लकड़ी उत्पाद, फर्नीचर और जुड़नार (-3.7)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए अंक विकास दर के हैं।
स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

सारणी 2.13 : औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइ आइ पी) विकास के लिए क्षेत्रवार योगदान -प्रयोग-आधारित वर्गीकरण (अप्रैल-दिसंबर)

(प्रतिशत)

उद्योग समूह	आइ आइ पी में भार	विकास			तुलनात्मक योगदान		
		2003-04	2004-05	2005-06P	2003-04	2004-05	2005-06 अनं.
1	2	3	4	5	6	7	8
आधारभूत माल	35.57	4.6	6.0	6.0	22.7	22.1	23.8
पूँजीगत माल	9.26	10.1	13.8	15.7	14.2	15.2	20.1
मध्यवर्ती माल	26.51	6.5	6.9	2.2	27.9	22.8	7.9
उपभोज्य वस्तुएँ (क +ख)	28.66	7.8	11.4	12.2	35.2	39.9	48.1
क) उपभोज्य टिकाऊ वस्तुएँ	5.36	9.2	15.3	13.6	10.2	13.5	13.9
ख) उपभोज्य गैर-टिकाऊ वस्तुएँ	23.30	7.3	10.0	11.7	24.9	26.4	34.2
आइ आइ पी	100.00	6.6	8.6	7.8	100.0	100.0	100.0

अनं. : अनंतिम
स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन ।

माल क्षेत्र के विकास में गतिवृद्धि, उद्योगों में घटित क्षमता परिवर्द्धन का निर्देशक है। साथ-साथ, पूँजीगत माल आयातों में एक बड़ी वृद्धि हुई है। गैर बिजली मशीनरी और परिवहन उपकरण ने पूँजीगत माल आयातों की वृद्धि में बहुत योगदान किया। अन्य पूँजीगत माल, जैसे व्यावसायिक उपकरण, प्रकाशिक माल, बिजली मशीनरी, मशीन औजार और परियोजना माल, का आयात भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा।

बुनियादी ढांचा

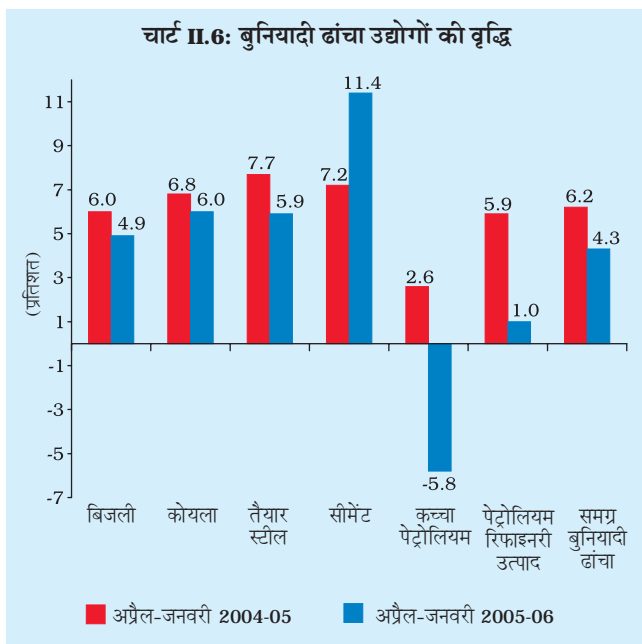
2.26 अप्रैल-जनवरी 2005-06 के दौरान, प्रमुख बुनियादी ढांचा उद्योगों का कुल विकास, पिछले वर्ष के अनुरूपी अवधि के दौरान 6.2 प्रतिशत की तुलना में, 4.3 प्रतिशत पर निम्नतर था (चार्ट II.6)। यह धीमापन प्रमुख रूप से कच्चे पेट्रोलियम में नकारात्मक वृद्धि

दर्ज करने, निम्नतर विकास/वृद्धि में पेट्रोलियम तेलशोधन कारखानों के उत्पादों में निम्नतर वृद्धि और सीमेंट के सिवाय अन्य बुनियादी ढांचा उद्योगों के विकास में अवतरण के कारण था। प्रमुख क्षेत्र समूहों में सीमेंट क्षेत्र ने, उस अवधि के दौरान, 11.4 प्रतिशत का त्वरित विकास दर्ज किया।

2.27 सुदृढ़ घरेलू माँग के बावजूद, देश से इस्पात निर्यात का धीमा होने के साथ निम्नतर आधार ने इस्पात उत्पादन में मध्यम दर्जे की वृद्धि में योगदान दिया। बढ़ती हुई घरेलू और बाह्य माँग ने सीमेंट क्षेत्र के सुदृढ़ विकास को सुविधाजनक बनाया। मानसून ऋतु के दौरान भारी वर्षा के कारण, कोल इंडिया लिमिटेड, टिस्को और इसको (आइ आइ एस सी ओ) खदानों में लक्ष्य से कम उत्पादन का परिणाम कोयला क्षेत्र में निम्नतर विकास में हुआ। जुलाई और सितंबर में बिजली उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि और थर्मल पावर संयंत्रों के पास कोयला और गैस की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण विद्युत क्षेत्र ने निम्नतर वृद्धि दर्ज की। जुलाई 27, 2005 को आग भड़कने से, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के मुंबई हाई तेल कुओं के तेल पर्यवेक्षण में विघटन होने के कारण कच्चे पेट्रोलियम ने उत्पादन में गिरावट दर्ज की। एक निजी क्षेत्र तेलशोधन कारखाने और दो सार्वजनिक क्षेत्र के तेलशोधक कारखानों के उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि का परिणाम पेट्रोलियम तेलशोधित उत्पादों में निम्नतर वृद्धि में हुआ।

सेवा क्षेत्र

2.28 सेवा क्षेत्र ने 2003-04 के दौरान प्राप्त संवेग को कायम रखा और 10.2 प्रतिशत की एक मजबूत वृद्धि 2004-05 के दौरान दर्ज की। 2004-05 के दौरान सेवा वृद्धि में त्वरण द्वारा चालित था जो “व्यापार, होटलों, परिवहन और संप्रेषण” द्वारा अनुगमनित रहा। वास्तव में, सेवा क्षेत्र में सभी उप-क्षेत्रों ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2005-06 के दौरान, सेवा क्षेत्रों में वृद्धि



उल्लेखनीय रही, यद्यपि 2004-05 की तुलना में 10.1 प्रतिशत के रूप में थोड़ी निम्नतर रही। निर्माण और “समुदाय सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं” उप-क्षेत्रों में अवत्वरण का परिणाम, “व्यापार, होटलों, परिवहन और संप्रेषण और वित्तपोषण, बीमा, वास्तविक संपत्ति और कारोबार सेवाएं” में सुधार होने बावजूद, सेवा क्षेत्र के मंद कार्यनिष्पादन में हुआ। इसके अतिरिक्त, सेवा क्षेत्र ने हाल में, कृषि अगाड़ी में अनिश्चितता के बावजूद, विकास प्रक्रिया को नियंत्रित रखा।

2.29 आवासीय सदनो की माँग में वृद्धि और विविध उद्योगों में क्षमता परिवर्द्धन के कारण देश में निर्माण गतिविधि ने जोर पकड़ा। व्यापार क्षेत्र ने सुदृढ़ द्वि-अंकी विकास दर्ज किया क्योंकि निर्यात और आयात दोनों प्रभावशाली रूप से, अप्रैल-दिसंबर 2005-06 के दौरान, क्रमशः 18.1 प्रतिशत और 27.3 प्रतिशत से बढ़े। निर्यात, मुख्यतः पेट्रोलियम उत्पादों, रत्न और आभूषण और परिवहन उपकरणों के कारण बढ़ा जबकि पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थ (पीओएल), स्वर्ण, लोहा और इस्पात और अन्य पण्य पदार्थों ने आयात बढ़ाया क्योंकि औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन, कारोबार और अवकाश दोनों, में वृद्धि ने होटल उद्योग के विकास में सहायता की। राजस्व आय बढ़ाता हुआ रेल्वे मालभाड़ा आवागमन, नागरिक विमानन और पत्तन आवागमन ने परिवहन क्षेत्र को सहारा दिया। मोबाइल फोन ग्राहकों के आधार में मजबूत वृद्धि और ब्रॉडबैंड संयोगों (कनेक्शनों) में लगातार वृद्धि ने संप्रेषण क्षेत्र के सुदृढ़ विकास को समर्थन दिया। बैंक जमाराशियों और गैर खाद्य ऋण में स्वस्थ विकास के साथ कारोबार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग में बढ़ोतरी-सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के निर्यात ने “वित्तपोषण, बीमा, वास्तविक संपत्ति और कारोबार सेवाएं” को बढ़ाया। “अन्य आर्थिक सेवाएं” पर राजस्व खर्च में वृद्धि, “रक्षा राजस्व खर्च”, केन्द्रीय सरकार की “सामाजिक सेवाएं” का योजना राजस्व खर्च और पेंशन भुगतानों के कारण “समुदाय सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं” ने विकास में तेजी बताया।

सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं-कारोबार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग

2.30 सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (आइ टी ई एस) और कारोबार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बी पी ओ) खंडों का योगदान सेवा क्षेत्रों के कायम विकास एक महत्वपूर्ण आयाम है। सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों का राष्ट्रीय एसोसिएशन (नैस्कॉम) के अनुसार, 2004-05 में आइ टी ई एस- बी पी ओ की आय उल्लेखनीय रूप से, 28.2 बिलियन अमरीकी डॉलर तक, बढ़ी, जो कि सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) की 4.1 प्रतिशत थी। इसे, प्रौद्योगिकीय उन्नति द्वारा समर्थित विदेशी और घरेलू उपभोक्ताओं की माँग में तेजी से वृद्धि के अतिरिक्त अग्रसक्रिय (प्रोपेक्टिव) नीति सुधारों, जैसे, अविनियमन,

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को खोलना और इस क्षेत्र के लिए उदार कर प्रोत्साहन का, प्रतीक माना जा सकता है। आइ टी ई एस- बी पी ओ बाजार ने, क्षेत्र में बढ़े विलयन और अभिग्रहण के साथ परिपक्वता और समेकन के संकेत को देखा, जिसने सेवा प्रदाता, जो सेवाओं के संपूर्ण स्पेक्ट्रम को संगठित ढंग से उपलब्ध करा सके, के लिए कंपनियों की खोज के उपयुक्त बनाया। राजस्व आय के अतिरिक्त, 2004-05 में आइ टी ई एस- बी पी ओ क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ा।

औद्योगिक दृष्टिकोण

2.31 उद्योग के कार्यनिष्पादन में चक्रीय सुधार, जो अप्रैल 2002 में शुरू हुआ था, को कायम रखा गया। उद्योगों में निवेश गतिविधि में वृद्धि को अंकित करते हुए, इसने समेकन को सहारा दिया। माँग परिस्थितियाँ भी अनुकूल रहीं। अंशदायी घटकों में, अनुकूल निवेश वातावरण, ऋण की पर्याप्त उपलब्धता, टोस कंपनी परिणाम, उन्नत घरेलू और बाह्य माँग, उद्योगों में क्षमता परिवर्द्धन और प्रतिस्पर्धात्मकता में निरंतर सुधार, शामिल हैं। पूंजीगत माल क्षेत्र ने प्रभावशाली द्वि-अंकी वृद्धि दर्ज की और क्षमता प्रसार के समर्थन से पूंजीगत मालों का आयात बढ़ा। वर्ष के दौरान उपभोक्ता माल खंड का बढ़ना, फुटकर ऋण की आसान उपलब्धता की मदद से, खपत माँग के तेजी को प्रतिबिंबित करता है। गैर खाद्य ऋण के मजबूत विस्तार, जो 2004-05 के दौरान 27.6 प्रतिशत से बढ़ा, की पृष्ठभूमि में, औद्योगिक क्षेत्र का दृष्टिकोण उत्साही है (सारणी 2.14)। इसके अतिरिक्त, 2005-06 (दिसंबर तक) के दौरान, गैर खाद्य ऋण, पिछले वर्ष के अनुरूपी अवधि के दौरान 18.2 प्रतिशत की तुलना में, 22.3 प्रतिशत से बढ़ा। 2005-06 के लिए अग्रिम अनुमानों ने (1999-00 कीमतों पर), विनिर्माण उप-क्षेत्र के 9.4 प्रतिशत सुदृढ़ विकास दर्ज करने के साथ और “विद्युत, गैस और जल आपूर्ति” के 5.4 प्रतिशत के अनुकरण में, उद्योग में विकास दर को 8.0 प्रतिशत पर रखा। उत्साहजनक औद्योगिक भावना से समर्थित आशाप्रद निवेश वातावरण और बढ़ते हुए कंपनी लाभों ने एक रिकार्ड तेजी बनाई जिसका परिणाम ऊँचे बाजार पूँजीकरण में हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की वृद्धि के लिए सरकार का वादा, बाधाओं को संबोधित और विकास संभावनाओं को प्रवर्तित करे, यह अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, चालू राजकोषीय वर्ष में रोडवेजों और विमानन परियोजनाओं में पर्याप्त मात्रा में प्रगति की आशा है। कुल मिलाकर, मजबूत माँग संयोजनों से उत्पन्न, निवेश में बढ़ोतरी, उपभोग और निर्यात द्वारा सुदृढ़, उद्योग अपनी निरंतर चलने वाली गति को कायम रखेगा ऐसी आशा है। फिर भी, कच्चे तेल की ऊँची कीमतें, कुछ अलौह धातुओं की कीमतों में तेजी, ब्याज दर का बढ़ना और प्रमुख क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में मंदी अधोमुखी खतरों को प्रस्तुत कर सकते हैं।

सारणी 2.14 : औद्योगिक क्षेत्र का कार्यनिष्पादन-चयनात्मक संकेतक

(विकास में प्रतिशत)

वर्ष	आइ आइ पी	विनिर्माण आइ आइ पी	पूँजीगत माल	उपभोक्ता माल	गैर खाद्य ऋण	पूँजीगत माल का आयात	विनिर्मित माल का आयात
1	2	3	4	5	6	7	8
1994-95	9.1	9.1	9.2	12.1	29.8	22.5	22.5
1995-96	13.0	14.1	5.3	12.8	22.5	44.1	16.4
1996-97	6.1	7.3	11.5	6.2	10.9	1.9	3.6
1997-98	6.7	6.7	5.8	5.5	15.1	3.4	7.9
1998-99	4.1	4.4	12.6	2.2	13.0	16.3	-2.8
1999-00	6.7	7.1	6.9	5.7	16.5	-8.2	15.2
2000-01	5.0	5.3	1.8	8.0	14.9	5.1	15.6
2001-02	2.7	2.9	-3.4	6.0	13.6	15.4	-2.8
2002-03	5.7	6.0	10.5	7.1	18.6	38.6	20.6
2003-04	7.0	7.4	13.6	7.1	18.4	28.6	14.4
2004-05	8.2	9.0	13.3	11.5	27.6	20.7	17.3
2004-05 #	8.6	9.2	13.8	11.4	18.2	31.4@	23.0@
2005-06 #	7.8	8.9	15.7	12.2	22.3	28.2@	14.3@

अप्रैल-दिसंबर अवधि से संबंधित। @ अप्रैल-नवंबर अवधि से संबंधित।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन और डी जी सी आइ & एस, भारत सरकार.

2.32 विभिन्न कारोबार प्रत्याशा सर्वेक्षण सुझाव देते हैं कि औद्योगिक गतिविधि संभवतः उत्साहजनक बनी रहेगी। रिजर्व बैंक के “औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण” ने, अक्टूबर-दिसंबर 2005 की तिमाही के लिए, कुल कारोबार स्थिति की प्रत्याशा का सुझाव 51.3 प्रतिशत के उच्चतर स्तर विश्वास पर, पिछली तिमाही के 45.5 प्रतिशत की तुलना में, दिया। अक्टूबर-दिसंबर 2005 की तिमाही के लिए, डन और ब्रैडस्ट्रीट का मिश्रित कारोबार आशावाद सूचकांक 7.1 प्रतिशत से सुधरा, जो स्वस्थ आर्थिक परिदृश्य को दर्शाता है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की) का कारोबार विश्वास सूचकांक सुधरा और पहली तिमाही के दौरान के 73.5 से, 2005-06 की दूसरी तिमाही में 75.2 तक बढ़ा। फिक्की के सर्वेक्षण ने प्रकट किया कि कंपनी घराने, मध्यम से दीर्घकालीन कारोबार दृष्टिकोण के बारे में उत्साही हैं। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन सी ए ई आर) कारोबार विश्वास सूचकांक (बी सी आइ) जुलाई-सितंबर 2005 के 146.0 से, धीरे-धीरे बढ़कर, अक्टूबर-दिसंबर 2005 के लिए 151.4 हुआ। यह उच्चतम स्तर है जिसे एन सी ए ई आर कारोबार विश्वास सूचकांक ने, नवंबर 1994 के बाद, प्राप्त किया।

2.33 2005-06 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान औद्योगिक क्षेत्र का कार्यनिष्पादन भलीभांति विविध था। विनिर्माण क्षेत्र के विकास की एक ध्यान देने योग्य विशेषता है कि यद्यपि 2004-05 के दौरान ऊँचे कार्यनिष्पादन करने वाले उद्योगों, जैसे, मशीनरी और उपकरण (भार 9.565) एवं रासायन और रासायनिक उत्पाद (भार 14.002), में चालू वर्ष के दौरान अबतक मंदी हुई, वस्त्र उत्पाद, मादक पेय, तंबाकू, आधारभूत धातु और मिश्रधातु उद्योगों, परिवहन उपकरण और कल पुर्जे, सूती कपड़े, गैर धातु खनिज उत्पादों, इत्यादि ने,

जिसने 2004-05 के दौरान निम्नतर अथवा नकारात्मक वृद्धि दर्ज की, चालू वर्ष में सुदृढ़ विकास प्राप्त किया और विनिर्माण क्षेत्र विकास में 50 प्रतिशत से अधिक योगदान किया। कुल निर्यात में विनिर्माण निर्यातों के हिस्से ने भी, जो लगभग 75 प्रतिशत थी, विनिर्माण क्षेत्र कार्यनिष्पादन में मदद की। परिणामस्वरूप, कंपनी क्षेत्र की लाभप्रदता में सुधार के कारण, औद्योगिक क्षेत्र में निवेश गतिविधि में वृद्धि और क्षमता परिवर्द्धन वर्तमान समय में शुरू हैं। पूँजीगत माल आयातों में तेजी ने भी औद्योगिक क्षेत्र के चल रहे विस्तार को सुसाध्य बनाया।

II. राजकोषीय स्थिति

केंद्रीय सरकार की वित्त-व्यवथाएँ

2.34 प्रभावी विकास कार्यनिष्पादन, मध्यम दर्जे की मुद्रास्फीति, सुदृढ़ और समुस्थानशील बाह्य क्षेत्र, के साथ सुदृढ़ गैर खाद्य बैंक ऋण निकास, की पृष्ठभूमि में 2006-07 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था। बढ़ी आय और खर्च नियंत्रण, मौद्रिक स्थायित्व और बाह्य ऋण के प्रबंध के जरिए, बजट राजकोषीय विवेक पर अपने “निरंतर जोर” को, सुदृढ़ समष्टि आर्थिक कार्यनिष्पादन का प्रमुख कारक मानता है। आय घाटे और राजकोषीय घाटे में प्रस्तावित कटौतियों द्वारा, बजट राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंध (एफ आर बी एम) नियमावली, 2004 में निर्दिष्ट राजकोषीय समेकन को पुनः आरंभ करने के लिए वचनबद्ध है।

2.35 बजट का प्रमुख जोर है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना और समाज के पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाना है। शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य और ग्रामीण रोजगार सम्मिलित सरकार के आठ अग्रणी कार्यक्रमों के लिए आबंटन में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। कृषि, रोजगार

प्रवर्तन करने, निवेश बढ़ाने और बुनियादी ढांचा संवर्धन पर अपना ध्यान केंद्रित करने को, बजट लगातार दोहराता है।

2.36 केंद्रीय बजट 2006-07, विकास गति को रोके बिना, कर/जीडीपी अनुपात को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देता है। प्रत्यक्ष कराधान के संबंध में कार्यनीति है, एक तरफ कर आधार का विस्तार करके एवं कर दरों को कम करके कर ढाँचे के विकार को कम किया जाए और दूसरी ओर कर प्रशासन की निपुणता में सुधार करना और स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए भय-निवारण स्तर को बढ़ाना। परोक्ष कर के बारे में कार्यनीति है, शुल्क सुधार प्रक्रिया को सीमा शुल्क के औसत आशियान स्तरों की ओर जारी रखना, उत्पाद शुल्क के लिए सेनवैट दर की ओर अभिसरण, सेवा कर के आधार को प्रशस्त करना और अप्रैल 1, 2010 तक संपूर्ण एकीकृत माल और सेवा कर की ओर चरणबद्ध बढ़ना। यद्यपि बजट, वैयक्तिक आय कर और कंपनी आय कर की दरों को नहीं बदलता, उसने, दूसरों के साथ-साथ, न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम ए टी), प्रतिभूतियाँ लेनदेन कर (एस टी टी) और सेवा कर की दरों को बढ़ा दिया।

संशोधित अनुमान 2005-06²

2.37 वर्ष 2005-06 के लिए संशोधित अनुमानों में मूल घाटा संकेतक, अर्थात् राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटा, जी डी पी से संबंधित, बजट में प्रावधान किए गए उनके स्तरों से निम्नतर रखा गया। इस संदर्भ में स्मरण रहे कि 2005-06 का बजट पेश करते समय, बारहवें वित्त आयोग (बारहवाँ वित्त आयोग (टी एफ सी)) के सुझावों को लागू करने के लिए अतिरिक्त संसाधन अपेक्षाओं हेतु, सरकार ने राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंध (एफ आर बी एम) नियमावली, 2004 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार, राजकोषीय सुधार में एक “विराम बटन” दबाया है। संशोधित अनुमानों में घाटा संकेतकों में, बजट में प्रावधान किए गए स्तरों से कटौती, मुख्यतः ब्याज भुगतानों, उपदानों, राज्यों को अनुदान और रक्षा व्यय के संबंध

में गैर योजना खर्चों में कमी के कारण था। गैर योजना खर्चों में कटौती के अतिरिक्त, बजट संबंधी प्राप्ति की तरह विनिवेश आगम की उपलब्धता (यद्यपि 2005-06 के लिए केंद्रीय बजट ने विनिवेश आगमों को बजट संबंधी प्राप्ति के रूप में समझने की प्रथा को बंद करने की कोशिश की है) और निम्नतर गैर रक्षा पूँजी लागत ने भी राजकोषीय घाटे को कम करने योग्य बनाया।

2.38 संशोधित अनुमानों में राजस्व घाटा 3.7 प्रतिशत से निम्नतर था और जी डी पी का 2.6 प्रतिशत बना जो कि बजट में प्रावधान किए गए 2.7 प्रतिशत स्तर के विपरीत था (सारणी 2.15)। राजस्व घाटे में गिरावट राजस्व खर्च में 6,217 करोड़ रुपए (1.4 प्रतिशत) तक की कमी के कारण थी जिसने राजस्व आय में 2,726 करोड़ रुपए (0.8 प्रतिशत) की कमी का प्रतिकरण किया। राजस्व घाटे में कमी के साथ विनिवेश आगम की उपलब्धता और पूँजी लागत में हास के परिणाम स्वरूप, बजट में प्रावधान किए गए स्तर (जी डी पी का 4.3 प्रतिशत) की अपेक्षा, एक निम्नतर सकल राजकोषीय घाटा (जी डी पी का 4.1 प्रतिशत) हुआ। 2005-06 के लिए संशोधित अनुमानों में, जी डी पी के 0.5 प्रतिशत पर प्राथमिक घाटा, बजट अनुमानों की अपेक्षा, 6.1 प्रतिशत से निम्नतर था। तथापि, जी डी पी के अनुसार, प्राथमिक घाटा बजट में प्रावधान किए गए 0.5 प्रतिशत के स्तर पर रहा (सारणी 2.15)।

2.39 वर्ष 2005-06 के लिए संशोधित अनुमानों में, राजस्व प्राप्तियाँ बजट में प्रावधान किए गए स्तर से थोड़ी, 0.8 प्रतिशत से, घटीं। राजस्व प्राप्तिियों में कमी, बजट में प्रावधान किए गए स्तर की अपेक्षा, निम्नतर कर-रहित आय के कारण थी। कर-रहित आय में कमी मुख्यतः बजट अनुमानों की अपेक्षा निम्नतर ब्याज प्राप्तिियों के कारण थी। 2005-06 के लिए संशोधित अनुमानों में सकल कर आय लगभग उसी स्तर पर रही जैसा कि बजट अनुमानों में था। संशोधित अनुमानों में, बजट में प्रावधान किए गए स्तर की अपेक्षा, निगम कर, वैयक्तिक आय कर और उत्पाद शुल्क का संग्रहण निम्नतर था जबकि सीमा शुल्क और सेवा कर द्वारा संग्रहण उल्लेखनीय रूप

सारणी 2. 15: केंद्र के घाटा संकेतक

(करोड़ रुपए)

मद	2004-05	2005-06 (बअ)	2005-06 (संअ)	2006-07 (बअ)	भिन्नता (प्रतिशत)	
					स्तंभ 4 का 3 पर	स्तंभ 5 का 4 पर
1	2	3	4	5	6	7
1. सकल राजकोषीय घाटा	1,25,202 (4.0)	1,51,144 (4.3)	1,46,175 (4.1)	1,48,686 (3.8)	-3.3	1.7
2. राजस्व घाटा	78,338 (2.5)	95,312 (2.7)	91,821 (2.6)	84,727 (2.1)	-3.7	-7.7
3. सकल प्राथमिक घाटा	-1,732 (-0.1)	17,199 (0.5)	16,143 (0.5)	8,863 (0.2)	-6.1	-45.1

बअ : बजट अनुमान । संअ : संशोधित अनुमान।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत हैं।

2 इस खंड में 2005-06 की सभी तुलनाएँ बजट अनुमानों से हैं जबतक अन्यथा न घोषित किया जाए।

से बजट में प्रावधान किए गए स्तर से अधिक था। नए करों में, 2005-06 में प्रतिभूतियाँ लेनदेन कर द्वारा 2, 389 करोड़ रुपए और बैंकिंग नकदी लेनदेन कर से 350 करोड़ रुपए की आय अनुमानित है। निवल कर आय [सकल कर आय कम राज्यों का केंद्रीय करों में हिस्सा और राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा आकस्मिकता कोष (एन सी सी एफ) को अंतर्गत राशि] ने, बजट में प्रावधान किए गए स्तर से ऊपर, 0.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी (सारणी 2.16)।

2.40 ऋणों की वसूली में गिरावट होने के बावजूद, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ, 2, 356 करोड़ रुपए की राशि को विनिवेश आगमों में शामिल करने करने कारण, बजट अनुमानों से उच्चतर थीं, यद्यपि 2005-06 के लिए केंद्रीय बजट ने विनिवेश आगमों को बजट संबंधी प्राप्ति के रूप में समझने की प्रथा को बंद करने की कोशिश की है (सारणी 2.16)।

2.41 2005-06 के लिए संशोधित अनुमानों में राजस्व खर्च बजट अनुमानों से 1.4 प्रतिशत निम्नतर था जबकि पूंजीगत खर्च थोड़ा सा उच्चतर था (सारणी 2.17)। ब्याज भुगतानों, राज्यों को अनुदान एवं उपदानों के कारण राजस्व खर्च निम्नतर था। पूंजीगत खर्च में, यद्यपि पूंजी लागत निम्नतर थी, ऋण और उधार बजट में प्रावधान किए गए स्तर से उच्चतर थे।

बजट अनुमान 2006-07³

2.42 2006-07 के लिए केंद्रीय बजट, राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध, 2004 में निर्धारित राजकोषीय सुधार को, पिछले वर्ष में “विराम” के बाद, शुरू करने का प्रस्ताव करता है। तदनुसार, प्रमुख घाटा संकेतकों, अर्थात्, सकल राजकोषीय घाटा (जी एफ डी), राजस्व घाटा (आर डी) और प्राथमिक घाटा (पी डी) का, जी डी पी के प्रतिशत के रूप में, बजट में निम्नतर प्रावधान, 2006-07 में, पिछले वर्ष के स्तरों 3.8 प्रतिशत, 2.1 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत की तुलना में, 2005-06 में क्रमशः 4.1 प्रतिशत, 2.6 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत, किया गया (सारणी 2.15)।

2.43 2005-06 में 13.9 प्रतिशत विकास के विपरीत, 2006-07 में राजस्व प्राप्तियों का, मुख्य रूप से कर आय में जारी रहे उच्च विकास के आधार पर, 15.8 प्रतिशत से बढ़ाने का बजट में प्रावधान किया गया है। सकल कर आय का 2006-07 में 19.5 प्रतिशत से बढ़ने का बजट में प्रावधान किया गया है, परिणामतः बजट में प्रावधान किए गए कर जीडीपी अनुपात में, 2005-06 के 10.5 प्रतिशत से, 11. 2 प्रतिशत तक सुधार हुआ। बजट में सकल कर आय में ऊंची वृद्धि का प्रावधान प्रमुख रूप से निगम कर, सीमा शुल्क और सेवा कर के अंतर्गत उत्साहजनक संग्रहण के आधार पर किया गया। तथापि,

सारणी 2.16 : केंद्र की प्राप्तियाँ

(करोड़ रुपए)

मद	2004-05	2005-06 (बअ)	2005-06 (संअ)	2006-07 (बअ)	भिन्नता (प्रतिशत)	
					स्तंभ 4 का 3 पर	स्तंभ 5 का 4 पर
1	2	3	4	5	6	7
कुल प्राप्तियाँ (1 + 2)	4,97,682	5,14,344	5,08,705	5,63,991	-1.1	10.9
1. राजस्व प्राप्तियाँ	3,06,013	3,51,200	3,48,474	4,03,465	-0.8	15.8
i. कर आय (निवल)	2,24,798	2,73,466	2,74,139	3,27,205	0.2	19.4
ii. कर-रहित आय	81,215	77,734	74,335	76,260	-4.4	2.6
2. पूंजीगत प्राप्तियाँ	1,91,669	1,63,144	1,60,231	1,60,526	-1.8	0.2
उसमें से :						
बाजार उधार	50,940	1,03,792	1,01,082	1,13,778	-2.6	12.6
ऋणों की वसूली	62,043	12,000	11,700	8,000	-2.5	-31.6
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में ईक्विटी विनिवेश	4,424	0	2,356	3,840	-	63.0
ज्ञापन मदें:						
सकल कर राजस्व	3,04,958	3,70,025	3,70,141	4,42,153	0.0	19.5
उसमें से :	<i>(9.8)</i>	<i>(10.5)</i>	<i>(10.5)</i>	<i>(11.2)</i>		
i. निगम कर	82,680	1,10,573	1,03,573	1,33,010	-6.3	28.4
ii. आय पर कर निगम कर के आलावा	49,259	66,239	63,500	73,409	-4.1	15.6
iii. सीमा शुल्क	57,611	53,182	64,215	77,066	20.7	20.0
iv. केंद्रीय उत्पाद शुल्क	99,125	1,21,533	1,12,000	1,19,000	-7.8	6.3
v. सेवा कर	14,200	17,500	23,000	34,500	31.4	50.0
vi. प्रतिभूतियाँ लेनदेन कर	590	-	2,389	3,500	-	46.5
vii. बैंकिंग नकदी लेनदेन कर	-	-	350	500	-	42.9
viii. कर की संघ शासित क्षेत्रों का कर (स्थानीय निकाय को समनुदेशन के बाद निवल)	819	733	849	903	15.8	6.4
ix. अन्य कर और शुल्क	1,264	265	3,004	4,265	1,033.6	42.0

बअ : बजट अनुमान. संअ : संशोधित अनुमान. - कुछ नहीं / नाम मात्र का.

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी)के प्रतिशत हैं।

3 इस खंड में, 2006-07 की सभी तुलनाएँ 2005-06 के लिए संशोधित अनुमानों से हैं, जबतक अन्यथा न घोषित किया जाए।

सारणी 2.17 : केंद्र की व्यय पद्धति

(करोड़ रुपए)

मद	2004-05	2005-06 (बअ)	2005-06 (संअ)	2006-07 (बअ)	प्रतिशत	
					स्तंभ 4 का 3 प	स्तंभ 5 का 4 पर
1	2	3	4	5	6	7
कुल व्यय (1+2)	4,97,682	5,14,344	5,08,705	5,63,991	-1.1	10.9
1. राजस्व व्यय	3,84,351	4,46,512	4,40,295	4,88,192	-1.4	10.9
ब्याज भुगतान	1,26,934	1,33,945	1,30,032	1,39,823	-2.9	7.5
उपदान	43,653	47,432	46,874	46,213	-1.2	-1.4
राज्यों को अनुदान	52,686	77,275	70,971	83,098	-8.2	17.1
रक्षा राजस्व	43,862	48,625	48,625	51,542	0.0	6.0
2. पूंजीगत व्यय	1,13,331*	67,832	68,410	75,799	0.9	10.8
ऋण और अग्रिम	28,910	5,652	11,417	8,861	102.0	-22.4
रक्षा पूंजी	31,994	34,375	33,075	37,458	-3.8	13.3
गैर रक्षा पूंजी लागत	19,752	27,805	23,918	29,480	-14.0	23.3

बअ : बजट अनुमान.

संअ: संशोधित अनुमान.

*राष्ट्रीय लघु बचत कोष को चुकाए गए 32, 675 करोड़ रुपए शामिल हैं।

बजट में उत्पाद शुल्क संग्रहण में, पूर्ववर्ती वर्ष में 13.0 प्रतिशत की अपेक्षा, 6.3 प्रतिशत के निम्नतर विकास को दर्शाने का प्रावधान किया गया है। बजट, गैर कर राजस्व में गिरावट को, 2006-07 में थोड़ी वृद्धि से, प्रमुख रूप से लाभांश और लाभ के अंतर्गत उन्नत संग्रहण के आधार पर, रोकने का प्रस्ताव करता है। 2006-07 में राज्य सरकारों से ऋण और उधार की वसूली में थोड़ी गिरावट अनुमानित है। बजट, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्रों (सी पी एस यू) में सरकारी ईक्विटी के आंशिक विनिवेश के कारण 3,840 करोड़ रुपए की अनुमानित प्राप्तियाँ दर्ज करता है परंतु इन प्राप्तियों को, 2006-07 में पूंजीगत लागतों के अंतर्गत, लेनदेन घाटे को तटस्थ बनाते हुए, राष्ट्रीय निवेश कोष (एन आइ एफ) के लिए अलग करता है (सारणी 2.16)।

2.44 राजस्व खर्च में नियंत्रण बजट अनुमानों का एक प्रमुख लक्षण है, विशेष रूप से गैर योजना घटकों में। 2006-07 में उपदानों पर खर्च में गिरावट का प्रावधान बजट में किया गया है जबकि ब्याज भुगतानों और रक्षा राजस्व खर्च का अपेक्षाकृत निम्नतर विकास दरों से बढ़ने का बजट में प्रावधान है। उपदानों में, खाद्य और पेट्रोलियम के सिवाय, सभी प्रमुख घटकों में, 2006-07 के दौरान, गिरावट का प्रावधान बजट में किया गया है। 2006-07 में, पूंजीगत खर्च 10.8 प्रतिशत से बढ़ने का, 2005-06 के 39.6 प्रतिशत गिरावट के विपरीत, प्रमुख रूप से रक्षा और गैर रक्षा पूंजीगत लागतों दोनों में वृद्धि के कारण, बजट में प्रावधान किया गया (सारणी 2.17)।

2.45 सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण नमूना संकेत देता है कि निवल बाजार उधार (बाजार स्थिरीकरण योजना [एम एस एस] के अंतर्गत बजट में प्रावधान किए गए शक्तिदायी आबंटन के सिवाय), 2006-07 में जी एफ डी का 76.5 प्रतिशत, पिछले वर्ष की 69.2 प्रतिशत की तुलना में, अर्थ-व्यवस्था करेगा। जमाराशियों और उधार जी एफ डी के उच्चतर हिस्से का वित्तपोषण करेंगे जबकि जी एफ डी के लिए, 2006-07 में, आरक्षित निधियों के हिस्से में गिरावट का बजट में प्रावधान किया गया है। बजट अनुमानों ने, नकदी शेष

जमाराशि के आहरण के लिए, पूर्ववर्ती वर्ष के जी एफ डी के 10.3 प्रतिशत की तुलना में, कोई प्रावधान नहीं किया। लघु बचतों के बदले प्रतिभूतियाँ, जिसने 2005-06 में जी डी पी का केवल 0.9 प्रतिशत वित्तपोषण किया, 2006-07 में 2.00 प्रतिशत वित्तपोषण करेंगी ऐसी अपेक्षा है (सारणी 2.18)।

सारणी 2.18 : सकल राजकोषीय घाटे की वित्तपोषण पद्धति

(करोड़ रुपए)

मद	2005-06 (संअ)	2006-07 (बअ)
1	2	3
सकल राजकोषीय घाटा	1,46,175	1,48,686
द्वारा वित्त पोषित		
बाजार उधार राशियाँ	1,01,082	1,13,778
	(69.2)	(76.5)
लघु बचतों के बदले प्रतिभूतियाँ	1,350	3,010
	(0.9)	(2.0)
बाह्य सहायता	7,515	8,324
	(5.1)	(5.6)
राज्य भविष्यनिधि कोष	5,500	6,000
	(3.8)	(4.0)
राष्ट्रीय लघु बचत निधि	-7,332	648
	-(5.0)	(0.4)
आरक्षित निधियाँ	3,526	1,725
	(2.4)	(1.2)
जमाराशि और अग्रिम	4,654	11,013
	(3.2)	(7.4)
डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधियाँ	1,215	1,265
	(0.8)	(0.9)
नकदी शेष जमाराशि का आहरण	15,037	0
	(10.3)	(0.0)
अन्य #	13,627	2,923
	(9.3)	(2.0)

बअ : बजट अनुमान।

संअ : संशोधित अनुमान।

बचत (कर युक्त) बंधपत्र 2003 और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जमाराशियों की योजना शामिल हैं।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े सकल राजकोषीय घाटे (जी एफ डी) के प्रतिशत हैं।

राज्य सरकार के वित्तसाधन

2.46 राज्य सरकारों के लिए विकासशील नीति वातावरण तीन महत्वपूर्ण गतिविधियों से बना है, अर्थात्, (i) राज्य-स्तर पर चल रहे राजकोषीय और संस्थागत सुधार, जो केंद्रीय सरकार और रिजर्व बैंक के उपक्रमों द्वारा सुविधाजनक और अनुपूरित हैं, (ii) केंद्र सरकार द्वारा बारहवें वित्त आयोग (टी एफ सी) के सिफारिशों की सामान्य स्वीकृति, जो 2005-06 के प्रारंभ से पांच-वर्ष की अवधि में राजकोषीय संघीय संबंधों का आधार बनाएगा, और (iii) अप्रैल 1, 2005 से बाईस राज्यों द्वारा मूल्य वर्द्धित कर (वैट) का कार्यान्वयन, जो कि कर सुधारों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 2005-06 में राज्य सरकारों के बजट में प्रावधान किए गए समेकित राजकोषीय स्थिति का परीक्षण, बारहवें वित्त आयोग (टी एफ सी) की सिफारिशों की पृष्ठभूमि में, किया जा सकेगा। 2004-05 (संशोधित अनुमान) के राजकोषीय परिदृश्य के विपरीत, 2005-06 के दौरान बड़े सुधारों का विचार है।

2.47 रिजर्व बैंक ने अपनी ओर से, जनवरी 2005 में, “राज्यस्तरीय मॉडेल राजकोषीय दायित्व विधिनिर्माण (एफ आर एल) का कार्यकारी समूह” के रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया और मार्च 2005 में प्रकाशित किया। रिपोर्ट एफ आर एल का एक ढांचा उपलब्ध कराता है और विविध मापदंडों के अनुसार विशिष्टता को हल करने के लिए राज्यों के विवेक पर छोड़ता है। सोलह राज्यों अर्थात्, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश ने अब तक एफ आर एल अधिनियम बनाया। मणिपुर ने 2005-06 में एफ आर एल विधेयक पेश किया है। मेघालय और उत्तरांचल ने भी अपने 2005-06 के बजट में एफ आर एल पेश करने का प्रस्ताव दिया है।

2.48 बारहवाँ वित्त आयोग (टी एफ सी) रिपोर्ट, जो कि मध्य-अवधि में राजकोषीय संघवाद की एक रूपरेखा है, ने एक उच्चतर राशि का अंतरण करने की सिफारिश की जिससे जी डी पी संबंधी अंतरण के परिमाण में गिरावट को उलटा किया जा सके और समस्तर असंतुलन (राज्यों के बीच) को सुधारते हुए न्यूनतम ऊर्ध्वधर अंतरण (केंद्र और राज्यों के बीच) को सुनिश्चित किया जा सके। 2005-06 से 2009-10 की कालावधि के लिए, केंद्र से राज्यों को कुल संसाधन अंतरण को (हिस्सेदारी योग्य कर आय और अनुदान शामिल करते हुए) 7,55,752 करोड़ रुपए पर रखा गया है, जो कि 2000-01 से 2004-05 की कालावधि के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए 4,34,905 करोड़ रुपए से लगभग 74 प्रतिशत उच्चतर है।

2.49 बारहवें वित्त आयोग (टी एफ सी) ने केंद्र और राज्यों के लिए, संस्थागत राजकोषीय ढांचे और विभिन्न राजकोषीय मापदंडों के लिए लक्ष्यों को स्थापित करने के माध्यम के जरिए, राजकोषीय समेकन की आवश्यकता पर जोर दिया है। बारहवें वित्त आयोग (टी एफ सी) की प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं, राज्यों को अनुदानों का बढ़ा हुआ अंतरण, राज्य-विशिष्ट अनुदान, राज्यों को केंद्रीय प्लान सहायता बंद करना, करों और उत्पाद शुल्कों में बढ़ा हुआ हिस्सा, ऋण राहत माध्यम के जरिए पुनर्संरचना और बट्टे-खाते में डालना और स्थानीय निकायों को अंतरण पर जोर। बारहवें वित्त आयोग (टी एफ सी) ने भी, ऋण राहत को उपलब्ध कराने के लिए, राज्यों द्वारा राजकोषीय विधान को अधिनियम बनाने को पूर्व-शर्त बना कर उसे प्रोत्साहित किया है। 2005-06 के दौरान अब तक 22 राज्यों में वैट लागू किया गया है। कराने के सोपानी प्रभाव का परिहार और स्वयं-मूल्यांकन प्रणाली के जरिए कर अनुपालन का संवर्द्धन करना, जो वैट के अंतर्भूत है, न केवल आर्थिक निपुणता को बढ़ाने में प्रेरक होगा परंतु, कालावधि में, राज्यों के अपने कर-राजस्व के विकास के दर में तेजी में भी सहायता करेगा। 2005-06 के लिए केंद्रीय बजट में राज्यों को क्षतिपूर्ति के रूप में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, राज्य-स्तरीय वैट लागू करने के कारण संभावित राजस्व में कमी के कारण, शामिल है। एक प्रमुख मुद्दा जिस पर 2005-06 के दौरान शक्ति-प्रदत्त समिति फिर से विचार करेगी वह है अंतर-राज्यीय अथवा केंद्रीय बिक्री कर (सी एस टी) को चरणबद्ध हटाना। इस स्रोत से राज्य लगभग 15,000 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व इकट्ठा करते हैं।

2.50 2005-06 के लिए राज्य बजटों ने, अवांछित व्यय में कटौती के जरिए, राजकोषीय समेकन पर जोर देना जारी रखा। कुछ राज्यों ने समाज के कुछ वर्गों को मुफ्त बिजली देने की नीति की समीक्षा करने का और बड़े पेंशन दायित्व को संबोधित करने के लिए “अंशदायी पेंशन निधियों” को लागू करने का प्रस्ताव किया है। चूककर्ता सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बकाया राशि को चुकाने की पहल के अलावा बिजली-क्षेत्र सुधारों को ऊंची प्राथमिकता भी राज्य बजटों में सुस्पष्ट है। कुछ राज्यों ने भी, दिसंबर 2004 के सुनामी विनाश से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास और कल्याण उपायों की पहल की है।

बजट अनुमान-2005-06⁴

2.51 2005-06 के लिए राज्य बजट राजकोषीय असंतुलनों के तीव्र सुधार का विचार करते हैं। सभी प्रमुख घाटा संकेतकों का, बजट में, पिछले वर्ष में उनके स्तर से बहुत निम्नतर प्रावधान किया गया है (सारणी 2.19)। राजस्व घाटे को और कम, पिछले वर्ष में उसके स्तर से लगभग आधा, किया जाएगा।

4 2005-06 बजट अनुमानों के लिए राज्यों की वित्त-व्यवस्था का विश्लेषण 29 राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित है, उसमें से एक खाते पर वोट है। सभी आंकड़ें अंतिम हैं।

सारणी 2.19: राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक

(करोड़ रुपए)

मद	1990-95	1995-00	2000-03	2003-04	2004-05	2004-05	2005-06	प्रतिशत भिन्नता	
	(औ)	(औ)	(औ)	(खातों)	बअ	संअ	बअ	स्तंभ 7 / 6	स्तंभ 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सकल राजकोषीय घाटा	(2.8)	(3.4)	(4.2)	1,23,070 (4.5)	1,14,647 (3.7)	1,23,635 (4.0)	1,10,070 (3.1)	7.8	-11.0
राजस्व घाटा	(0.7)	(1.6)	(2.5)	61,145 (2.2)	45,425 (1.5)	44,302 (1.4)	24,770 (0.7)	-2.5	-44.1
प्राथमिक घाटा	(1.1)	(1.4)	(1.5)	41,306 (1.5)	23,789 (0.8)	35,737 (1.1)	16,772 (0.5)	50.2	-53.1

औ : औसत। बअ : बजट अनुमान। संअ : संशोधित अनुमान।

टिप्पणी : (1) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जी डी पी के प्रतिशत हैं।

(2) 1990-91 से 1998-99 तक जीडीपी पुराने आधार (1993-94) पर है जबकि 1999-2000 से आगे वह नए आधार (1999-2000) पर है।

स्रोत : (1) राजकोषीय परिवर्तन के आंकड़ें राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से संकलित किए गए हैं।

(2) जीडीपी के लिए आंकड़ें केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) के वेबसाइट से प्राप्त किए गए हैं।

2.52 2005-06 के दौरान, राजस्व खाते में सुधार, प्रमुख रूप से गैर ब्याज राजस्व खर्च की वृद्धि को रोक कर लाया जाएगा। लगभग सभी राजस्व खर्च के अंतर्गत विकासात्मक मदों की विकास दरें संभवतः मंदी दर्ज करेंगे। गैर विकासात्मक राजस्व खर्च के अंदर, प्रशासनिक सेवाओं के विकास दर में तेजी अपेक्षित है जबकि ब्याज भुगतानों की वृद्धि-दर में

संभवतः मंदी होगी। 2005-06 के दौरान पूंजीगत लागत बढ़ाई जाएगी, यद्यपि, जीडीपी के अनुपात के रूप में वह पिछले वर्ष के स्तर पर रहेगा। कुल मिलाकर, 2005-06 के दौरान विकासात्मक व्यय का जीडीपी से अनुपात, गैर विकासात्मक व्यय का जीडीपी के अनुपात से, एक वृहत्तर गिरावट दर्ज करेगा (सारणी 2.20)।

सारणी 2.20 : राज्य सरकारों की व्यय पद्धति

(करोड़ रुपए)

मद	1990-95	1995-00	2000-03	2003-04	2004-05	2004-05	2005-06	प्रतिशत भिन्नता	
	(औ)	(औ)	(औ)	(खातों)	बअ	संअ	बअ	स्तंभ 7/6	स्तंभ 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल खर्च (1+2=3+4+5)	(16.0)	(15.3)	(16.7)	13,31,748 (48.2)	11,23,935 (36.2)	12,30,076 (39.4)	11,53,938 (32.7)	9.4	-6.2
1. राजस्व खर्च उसमें से ब्याज भुगतान	(12.8)	(12.6)	(13.8)	3,77,681 (13.7)	4,20,006 (13.5)	4,28,741 (13.7)	4,55,040 (12.9)	2.1	6.1
	(1.7)	(2.0)	(2.7)	81,763 (3.0)	90,858 (2.9)	87,899 (2.8)	93,298 (2.6)	-3.3	6.1
2. पूंजीगत व्यय उसमें से पूँजी लागत	(3.2)	(2.7)	(2.9)	9,54,068 (34.6)	7,03,929 (22.7)	8,01,335 (25.7)	6,98,898 (19.8)	13.8	-12.8
	(1.6)	(1.4)	(1.5)	52,426 (1.9)	60,828 (2.0)	68,231 (2.2)	76,764 (2.2)	12.2	12.5
3. विकासात्मक खर्च	(10.8)	(9.6)	(9.6)	2,80,099 (10.1)	2,89,223 (9.3)	3,16,172 (10.1)	3,25,672 (9.2)	9.3	3.0
4. गैर विकासात्मक खर्च	(4.3)	(4.9)	(6.0)	1,69,021 (6.1)	1,99,770 (6.4)	1,93,602 (6.2)	2,11,368 (6.0)	-3.1	9.2
5. अन्य*	(0.9)	(0.7)	(1.2)	8,82,627 (32.0)	6,34,942 (20.4)	7,20,303 (23.1)	6,16,898 (17.5)	13.4	-14.4

औ : औसत। बअ : बजट अनुमानों। संअ : संशोधित अनुमानों।

* स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति और आबंटन, सहायक अनुदान और योगदान, वित्त विभाग के पास रिजर्व, आंतरिक ऋण की अदायगी, केंद्र को ऋणों की चुकौती 2002-03 तक, शामिल हैं। 2003-04 से, अंतर-राज्यीय निपटान, आकस्मिकता कोष, लघु बचतें, भविष्य निधि कोष, इत्यादि, आरक्षित निधियाँ, जमाराशि और अग्रिम, उंचत और फुटकर, आकस्मिकता कोष को विनियोजन और प्रेषण भी शामिल हैं।

टिप्पणी : (1) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जी डी पी के प्रतिशत हैं।

(2) 2003-04 से शुरू, पूंजीगत खर्च में, सार्वजनिक खातों के अनुरूपी मद, जो कि अब तक निवल आधार पर पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत थे, शामिल हैं। आंकड़े, इसलिए, पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय नहीं हैं। कुल खर्च के तुलनीय आंकड़े, निवल आधार पर, वर्ष 2003-04 (खातों), 2004-05 (बअ), 2004-05 (संअ) और 2005-06 (बअ) के लिए क्रमशः 19.1 प्रतिशत, 17.9 प्रतिशत, 19.0 प्रतिशत और 16.4 प्रतिशत, हैं। पूंजीगत खर्च के तुलनीय आंकड़े, निवल आधार पर, वर्ष 2003-04 (खातों), 2004-05 (बअ), 2004-05 (संअ) और 2005-06 (बअ) के लिए क्रमशः 5.4 प्रतिशत, 4.3 प्रतिशत, 5.3 प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत, हैं।

(3) 1990-91 से 1998-99 तक जीडीपी पुराने आधार (1993-94) पर है जबकि 1999-2000 से आगे वह नए आधार (1999-2000) पर है।

स्रोत : (1) राजकोषीय परिवर्तन के आंकड़े राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से संकलित किए गए हैं।

(2) जीडीपी के लिए आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) की वेबसाइट से प्राप्त किए गए हैं।

2.53 प्राप्तियों के बारे में, राज्यों के अपने कर आय का जीडीपी से अनुपात और थोड़ी वृद्धि बताएगा (सारणी 2.21)। बाईस राज्य सरकारों द्वारा वैट का कार्यान्वयन, वर्ष के दौरान, राज्यों के अपने कर राजस्वों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। तथापि, 2005-06 में, मुख्यतः ब्याज प्राप्तियों में तीव्र गिरावट के कारण, राज्यों के अपने गैर कर राजस्व, जीडीपी के अनुपात के रूप में कम होंगे। केंद्र से चालू अंतरण का, जीडीपी के अनुपात के रूप में, बजट में, 2004-05 (संशोधित अनुमान) की अपेक्षा, 4.8 प्रतिशत पर थोड़ा उच्चतर प्रावधान किया गया है। केंद्रीय बजट 2005-06 के अनुसार, बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) के सुझावों का, वर्ष 2005-06 के लिए, केंद्र पर पूरा प्रभाव (और प्रतिबिंब के रूप में, राज्यों पर) 26, 000 करोड़ रुपए का होगा। संभवतः, उच्चतर कर अंतरण, बढ़े हुए अनुदानों के अलावा ऋण राहत योजनाओं के कारण राज्यों को लाभ होगा। बजट 2005-06 के अनुसार, सकल अंतरण में वृद्धि और राज्यों को अंतरण (कर

हिस्सा, अनुदान और ऋणों के जरिए), 2005-06 में, पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से अधिक, लगभग 17,000 करोड़ रुपए है।

2.54 सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) का वित्तपोषण दर्शाता है कि, राज्य सरकारों का लघु बचतों के हिस्से में वृद्धि का प्रावधान, 2005-06 के दौरान बजट में, 2004-05 की तुलना में बाजार उधार राशियों के हिस्से में गिरावट के विरुद्ध, किया गया है (सारणी 2.22)।

2.55 केंद्र से कर्ज, जिसने पूर्ववर्ती तीन वर्षों (2002-03 से 2004-05 तक) के दौरान निवल चुकौती दर्शाया, का राज्यों के उधार की आवश्यकताओं के एक बहुत बड़े अनुपात की वित्त-व्यवस्था करने का बजट में प्रावधान किया गया क्योंकि राज्यों ने, केंद्र सरकार का राज्य सरकारों को कर्ज की समाप्ति की सिफारिश का टीएफसी के सुझावों को, ध्यान में नहीं लिया। 2005-06 के दौरान, राज्य सरकारों के लिए बाजार कर्ज कार्यक्रम के अंतर्गत अनंतिम निवल आबंटन को 16,112

सारणी 2.21 : राज्य सरकारों की कुल प्राप्तियाँ

(करोड़ रुपए)

मद	1990-95 (औ)	1995-00 (औ)	2000-03 (औ)	2003-04 (खातों)	2004-05 बअ	2004-05 संअ	2005-06 बअ	प्रतिशत भिन्नता	
								स्तंभ 7 / 6	स्तंभ 8 / 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल प्रालप्तियाँ (1+2)				13,30,584 (48.2)	11,18,716 (36.0)	12,23,312 (39.2)	11,55,807 (32.7)	9.3	-5.5
1. कुल राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख)	(16.1)	(15.2)	(16.8)	3,16,536 (11.5)	3,74,581 (12.1)	3,84,438 (12.3)	4,30,270 (12.2)	2.6	11.9
(क) राज्यों का अपना राजस्व				1,98,109 (7.2)	2,35,217 (7.6)	2,36,596 (7.6)	2,61,795 (7.4)	0.6	10.7
राज्यों का अपना कर	(7.3)	(6.9)	(7.2)	1,59,921 (5.8)	1,85,605 (6.0)	1,87,415 (6.0)	2,15,243 (6.1)	1.0	14.8
राज्यों का अपना गैर कर	(5.4)	(5.3)	(5.7)	38,189 (1.4)	49,612 (1.6)	49,181 (1.6)	46,552 (1.3)	-0.9	-5.3
(ख) केंद्रीय अंतरण	(1.8)	(1.6)	(1.5)	1,18,426 (4.3)	1,39,364 (4.5)	1,47,843 (4.7)	1,68,475 (4.8)	6.1	14.0
हिस्सेदारी योग्य कर	(4.9)	(4.0)	(4.2)	67,079 (2.4)	77,952 (2.5)	80,755 (2.6)	90,003 (2.6)	3.6	11.5
केंद्रीय अनुदान	(2.6)	(2.4)	(2.3)	51,348 (1.9)	61,413 (2.0)	67,088 (2.1)	78,472 (2.2)	9.2	17.0
2. पूंजीगत प्राप्तियाँ (क+ख)	(2.3)	(1.6)	(1.9)	10,14,047 (36.7)	7,44,135 (24.0)	8,38,873 (26.9)	7,25,537 (20.6)	12.7	-13.5
(क) केंद्र से ऋण @	(4.0)	(4.2)	(5.5)	26,127 (0.9)	34,040 (1.1)	32,940 (1.1)	31,216 (0.9)	-3.2	-5.2
(ख) अन्य पूंजीगत प्राप्तियाँ	(1.2)	(1.0)	(1.0)	9,87,920 (35.8)	7,10,095 (22.9)	8,05,933 (25.8)	6,94,321 (19.7)	13.5	-13.8

औ : औसत। बअ : बजट अनुमान। संअ : संशोधित अनुमान।

@ लेखा प्रणाली में 1999-2000 प्रभाव से बदलाव के कारण, राज्यों का लघु बचतों में हिस्सा, जो पहले केंद्र से ऋण के अंतर्गत शामिल था, आंतरिक ऋणों में शामिल किया गया है और केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियों के रूप में दर्शाया गया है। तथापि, 1999-2000 से पहले के वर्षों के आंकड़े, जैसा कि इस सारणी में बताया गया है, तुलना के लिए, लघु बचतों के बदले ऋण को अलग करता है।

टिप्पणी : (1) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जी डी पी के प्रतिशत हैं।

(2) 2003-04 से पूंजीगत प्राप्तियों के आंकड़े सकल आधार पर हैं, इसलिए, पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों साथ तुलनीय नहीं हैं। कुल प्राप्तियों के तुलनीय आंकड़े, निवल आधार पर, वर्ष 2003-04 (खातों), 2004-05 (बअ), 2004-05 (संअ) और 2005-06 (बअ) के लिए क्रमशः 19.1 प्रतिशत, 17.8 प्रतिशत, 18.9 प्रतिशत और 16.5 प्रतिशत, हैं। पूंजीगत प्राप्तियों के तुलनीय आंकड़े, निवल आधार पर, वर्ष 2003-04 (खातों), 2004-05 (बअ), 2004-05 (संअ) और 2005-06 (बअ) के लिए क्रमशः 7.6 प्रतिशत, 5.7 प्रतिशत, 6.5 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत, हैं।

(3) 1990-91 से 1998-99 तक जीडीपी पुराने आधार (1993-94) पर है जबकि 1999-2000 से आगे वह नए आधार (1999-2000) पर है।

स्रोत : (1) राजकोषीय परिवर्तनता के आंकड़ें राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से संकलित किए गए हैं।

(2) जीडीपी के लिए आंकड़ें केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) के वेबसाइट से प्राप्त किए गए हैं।

सारणी 2.22 : राज्यों के जीएफडी का वियोजन और वित्तपोषण पद्धति

(प्रतिशत)

मद	1990-95 (औ)	1995-00 (औ)	2000-03 (औ)	2003-04 (खातों)	2004-05 बअ	2004-05 संअ	2005-06 बअ
1	2	3	4	5	6	7	8
वियोजन (1+2+3)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1. राजस्व घाटा	24.7	44.7	58.5	49.7	39.6	35.8	22.5
2. पूंजीगत लागत	55.3	43.2	34.7	42.6	53.1	55.2	69.7
3. निवल दिए हुए ऋण	20.0	12.1	6.8	7.7	7.3	9.0	7.8
वित्तपोषण (1से11 तक)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1. बाजार उधार राशियाँ	16.0	16.1	19.9	38.4	24.0	26.4	14.6
2. केंद्र से ऋण	49.0	40.6	6.6	11.5	13.8	4.7	15.8
3. एनएसएसएफ को जारी किए गए प्रतिभूतियों के बदले ऋण	-	28.9*	41.6	16.9	34.1	43.4	47.8
4. एलआईसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से लिए गए कर्ज	1.8	2.8	5.5	3.4	4.6	2.3	7.3
5. राज्य भविष्य निधि कोष	14.3	13.4	9.2	5.8	9.1	7.8	7.2
6. आरक्षित निधियाँ	6.8	5.5	4.3	5.2	5.2	5.0	3.8
7. जमाराशियाँ और अग्रिम	9.8	9.8	4.6	-0.3	0.1	-1.0	-2.5
8. उचंचत और फुटकर	4.3	2.7	0.4	-4.4	-1.6	0.5	-1.3
9. प्रेषण	-1.4	-3.6	0.3	1.5	1.0	-0.8	1.5
10. कुल अधिशेष (+) / घाटा (-)	4.4	-2.6	1.2	-0.9	-4.6	-5.5	1.0
11. अन्य	-5.0	9.5	6.4	23.0	14.2	17.1	4.7

औ : औसत। बअ : बजट अनुमानों। संअ : संशोधित अनुमानों। - : नहीं लागू।

* 1999-2000 से संबंधित है क्योंकि उसे केवल उस वर्ष से ही लागू किया गया था। 1995-2000 (औ) के लिए मद्यों का जोड़ 100 नहीं होगा।

टिप्पणी : (1) कुल अधिशेष / घाटे का मेल 2003-04 से नकद राशि के जमाशेष की वृद्धि/ कमी से होगा। यह, नकद राशि निवेश खाते को अब “उचंचत और फुटकर” में शामिल करने के कारण हुआ जबकि अर्थोपाय अग्रिम / भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट “आंतरिक ऋण” के अंतर्गत शामिल है।

(2) ‘अन्य’ (मद संख्या 11) में फुटकर पूंजीगत प्राप्तियाँ, आकस्मिकता कोष, अंतर-राज्य निपटान, अर्थोपाय अग्रिम / भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट, इत्यादि शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

करोड़ रुपए पर रखा गया है। 6,274 करोड़ रुपए की चुकौतियों और 3,202 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज आबंटन को ध्यान में रखते हुए, सकल आबंटन 25,589 करोड़ रुपए होता है। राज्यों ने, 2005-06 के दौरान अब तक (फरवरी 28, 2006 तक) 19, 909 करोड़ रुपए की राशि उगाही है (सारणी 2.23)। बाजार ऋणों का भारित औसत व्याज दर, 2005-06 के दौरान अब तक (फरवरी 28, 2006 तक), पिछले वर्ष की अनुरूपी कालावधि के दौरान 6.44 प्रतिशत की तुलना में, 7.62 प्रतिशत तक मजबूत हुआ (चार्ट II. 7)।

2.56 राज्यों ने सामान्यतः टीएफसी की सिफारिशों को ध्यान में नहीं लिया। राज्यों की योजनाओं के लिए निवल केंद्रीय ऋणों की गणना करते हुए, जैसा कि 2005-06 के केंद्रीय बजट में सूचित किया गया है, और मानकर कि राज्य योजनाएँ बजट स्तर पर कायम रखी हैं, 2005-06 के दौरान बाजार ऋण, उच्चतर कर और अनुदानों के अंतरण के कारण जैसा कि केंद्रीय बजट में टीएफसी की सिफारिशों के कारण ध्यान दिया गया है और राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) से वृहत्तर प्राप्तियों के कारण, अनंतिम निवल आबंटन राशि से बहुत उच्चतर नहीं होगा।

2.57 वर्ष 2005-06 के दौरान अब तक (फरवरी 2006 की समाप्ति तक) राज्यों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एम ए) का साप्ताहिक औसत उपयोग और ओवरड्राफ्ट 481 करोड़ रुपए हुआ जो कि पिछले वर्ष की अनुरूपी कालावधि के 2,914 करोड़ रुपए से उल्लेखनीय रूप से निम्नतर था (चार्ट II.8)।

2.58 राज्यों की कुल नकदी स्थिति 14-दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों के निवेश में तेजी से प्रतिबिंबित होती है। 2005-06 के दौरान अब तक (फरवरी 2006 की समाप्ति तक) राज्यों द्वारा 14-दिवसीय खजाना बिलों में साप्ताहिक औसत निवेश 34, 045 करोड़ रुपए हुआ, जो पिछले वर्ष की अनुरूपी कालावधि के 9,945 करोड़ रुपए से बहुत ही उच्चतर थी (चार्ट II.9)। 2004-05 में संपूर्ण वर्ष के दौरान 13 राज्यों की तुलना में, 2005-06 के दौरान अब तक (फरवरी 28, 2006 तक) नौ राज्यों ने ओवरड्राफ्ट का सहारा लिया।

दृष्टिकोण

2.59 वर्ष 2005-06 महत्वपूर्ण है, न सिर्फ इसलिए कि वह बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) के निर्णय का पहला वर्ष है बल्कि इसलिए कि उसने दीर्घकाल से लंबित राज्य-स्तरीय वैट का कार्यान्वयन देखा, जो कर सुधारों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बारहवें वित्त आयोग (टी एफ सी) ने राज्यों को अंतरण और अंतरित करने में एक भारी वृद्धि की सिफारिश की है जो उनके बजटों पर दबाव को हल्का करने में सहायक होगा। इसके साथ, बारहवें वित्त आयोग (टी एफ सी) ने, ऋण राहत को उपलब्ध करने के लिए, राज्यों द्वारा राजकोषीय जवाबदेही विधिनिर्माण (एफ आर एल) को अधिनियम बनाने को पूर्व-शर्त बना कर उसे प्रोत्साहित किया है। इसके अतिरिक्त, बारहवें वित्त आयोग (टी एफ सी) की सिफारिश कि राज्यों को, अपनी वार्षिक योजनाओं की वित्त-व्यवस्था के लिए, बाजार में पैठ करने की जरूरत है (केंद्र के बजाय), संभवतः राजकोषीय अनुशासन उत्पन्न करेगा

सारणी 2.23 : 2005-06 के दौरान राज्य सरकारों की बाज़ार उधार राशियाँ
(फरवरी 28, 2006 को)

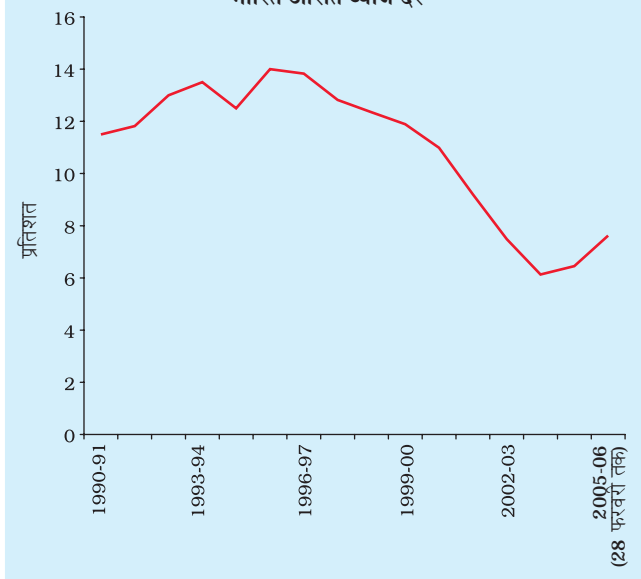
(करोड़ रुपए)

मद	तारीख	काट दर (%)	अवधि (वर्ष)	उगाही गई राशि
1	2	3	4	5
(क) तैयार निर्गम				
पहला भाग	मई 17-18, 2005	7.77	10	7,554
दूसरा भाग	सितंबर 13, 2005	7.53	10	2,931
तीसरा भाग	जनवरी 16, 2006	7.61	10	700
कुल (क)				11,185
(ख) नीलामियाँ				
i. पहली	अप्रैल 20, 2005	7.45	10	300
ii. दूसरी	जून 14, 2005	7.39	10	2,181
iii. दूसरी	जून 14, 2005	7.35	10	210
iv. तीसरी	अगस्त 4, 2005	7.32	10	250
v. चौथी	सितंबर 27, 2005	7.45	10	367
vi. चौथी	सितंबर 27, 2005	7.42	10	146
vii. चौथी	सितंबर 27, 2005	7.50	10	327
viii. पांचवीं	नवंबर 17, 2005	7.34	10	375
ix. छठी	दिसंबर 15, 2005	7.33	10	361
x. सातवीं	जनवरी 19, 2006	7.32	10	317
xi. सातवीं	जनवरी 19, 2006	7.33	10	166
xii. आठवीं	फरवरी 27, 2006	7.65	10	950
xiii. आठवीं	फरवरी 27, 2006	7.67	10	619
xiv. आठवीं	फरवरी 27, 2006	7.68	10	600
xv. आठवीं	फरवरी 27, 2006	7.70	10	628
xvi. आठवीं	फरवरी 27, 2006	7.75	10	328
xvii. आठवीं	फरवरी 27, 2006	7.85	10	599
कुल -ख(i से xvii तक)				8,724
कुल योग (क+ख)				19,909

और ज्यादा यथार्थपूर्ण राज्य योजना लागतों के सूत्रीकरण का मार्गदर्शन करेगा। आशा है कि ये उपाय राज्यों द्वारा राजकोषीय सुधारों के कार्यान्वयन को जल्दी पूरा करेंगे और इस तरह उन्हें वांछित दूरी तय करने में मदद

करेंगे कि जैसा बारहवें वित्त आयोग (टी एफ सी) की पुनर्संरचना योजना में विचार किया गया है। राज्यों को तदनुसार, लक्ष्य प्राप्ति के लिए, टोस और पारदर्शी कार्यनीतियों का सूत्रीकरण करना जरूरी होगा।

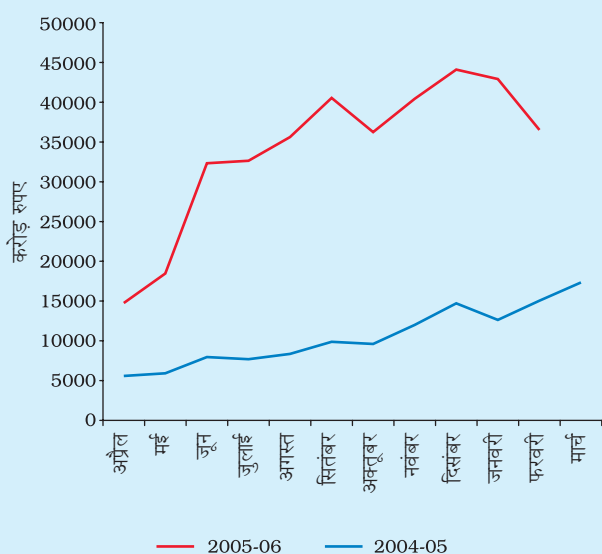
चार्ट II.7: राज्य सरकारों के बाज़ार उधारों पर
भारत औसत ब्याज दर



चार्ट II.8: राज्यों द्वारा डब्ल्यू एम ए और ओवर ड्राफ्ट का उपयोग
(साप्ताहिक औसत)



चार्ट II.9: राज्य सरकारों द्वारा मध्यवर्ती खजाना बिलों में निवेश (साप्ताहिक औसत)



2.60 इस पृष्ठभूमि में, 2005-06 के लिए राज्यों के बजट, पिछले वर्ष के स्तर से पर्याप्त मात्रा में राजकोषीय सुधार दर्शाते हैं। तथापि, उभरते राजकोषीय परिदृश्य के मूल्यांकन को, टीएफसी द्वारा सिफारिश किए गए और केंद्रीय बजट में बताए गए और वे जो राज्यों के बजट में दर्शाए गए, के बीच में अंतरण और अंतरित के आँकड़ों में अंतर का संभवतः संज्ञान लेना जरूरी है।

2.61 वर्ष 2005-06, बाईस राज्यों द्वारा, बिक्री कर की जगह, वैट अपनाने के कारण, विशिष्ट है। वैट के कार्यान्वयन में प्रारंभिक कठिनाइयों को प्रतिबिंबित करते हुए, कुछ राज्यों की राजस्व हानि की भारत सरकार द्वारा क्षतिपूर्ती की गई है। इसके अतिरिक्त, कई राज्यों ने एफआरएल अधिनियम बनाए जो टीएफ सी द्वारा प्रोत्साहित हैं। राजकोषीय सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की चेष्टा में,

राज्य सरकारों ने अपने बजटों में नीति पहल पर विचार किया है जिसमें, नए करों का प्रस्ताव और विद्यमान का संशोधन, खर्चों का यौक्तिकरण, संस्थागत सुधारों और परिभाषित योगदानों पर आधारित नई पेंशन योजना का प्रारंभ, शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, चालू राजकोषीय वर्ष में राज्य सरकारों के अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एम ए) पर आश्रय में पर्याप्त मात्रा में गिरावट दर्ज करने के साथ-साथ रिजर्व बैंक के पास, उनके अधिशेष नकदी जमाशेष तुलन संपत्ति में तीव्र वृद्धि, जो कि 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों में उनके निवेश से प्रतिबिंबित है, को देखा।

सार्वजनिक ऋण

2.62 केंद्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त बकाया देयताओं की गिरावट का, जी डी पी के अनुपात की तरह, मार्च 2005 के अंत में 82.1 प्रतिशत से मार्च 2006 के अंत में 80.7 प्रतिशत तक, बजट में प्रावधान है। बजट में प्रावधान किए गए ऋण-जीडीपी अनुपात में गिरावट प्रमुख रूप से राज्य स्तर पर विचार किए गए राजकोषीय समेकन के कारण है (सारणी 2.24)।

III. मौद्रिक और ऋण स्थिति

मौद्रिक परिस्थितियाँ

2.63 यह परिच्छेद, 2005-06 के दौरान मौद्रिक नीतियों का आकलन करता है और मौद्रिक गतिविधियों और ऋण समुच्चय को सम्मिलित करता है उसके बाद रिजर्व बैंक द्वारा चलनिधि प्रबंध परिचालनों पर ऊंचे ऋण विकास के माहौल में एवं इंडिया मिलेनियम डिपॉजिटर्स (आई एम डी) के विमोचन पर, मूल्य स्थिरता को सुनिश्चित करते हुए, चर्चा करता है। मुद्रास्फीति प्रबंध का भी, कच्चे तेल की कीमतों में व्यापक वृद्धि के संदर्भ में, परीक्षण किया है।

सारणी 2.24 : संयुक्त देय और ऋण-जीडीपी अनुपात

वर्ष (मार्च-अंत)	बकाया देय (करोड़ रुपए)			ऋण-जीडीपी अनुपात (प्रतिशत)		
	केंद्र	राज्यों	संयुक्त	केंद्र	राज्यों	संयुक्त
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	3,14,558	1,28,095	3,68,764	55.3	22.5	64.8
1995-96	6,06,232	2,50,813	7,28,132	51.0	21.1	61.3
2002-03	15,59,201	7,97,684	19,82,061	63.6	32.6	80.9
2003-04	17,36,678	9,22,263	22,50,837	62.9	33.4	81.5
2004-05 संअ	19,81,514	10,40,834	25,62,822	63.5	33.3	82.1
2005-06 बअ	22,31,886	11,52,530	28,47,587	63.2	32.7	80.7

संअ : संशोधित अनुमान।

बअ : बजट अनुमान।

टिप्पणी : 2002-03 से आगे के वर्षों के लिए जीडीपी से अनुपात, आधार वर्ष 1999-2000 के साथ, राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी की नई शृंखला पर आधारित है।

स्रोत : केंद्र सरकार का बजट दस्तावेज और "2005-06 के राज्य बजटों का एक अध्ययन", भारतीय रिजर्व बैंक, दिसंबर 2005।

2.64 अप्रैल 2005 में घोषित वार्षिक नीति वक्तव्य के रुझान के साथ, रिजर्व बैंक की वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा (अक्टूबर 2005) ने संकेत दिया कि वह सुनिश्चित करना जारी रखेगी कि प्रणाली में यथोचित चलनिधि बनी रहे कि जिससे, मूल्य स्थिरता के उद्देश्य के अनुकूल, सभी ऋण की प्रामाणिक जरूरतें पूरी हों, एक ब्याज दर माहौल को सुनिश्चित करे, जो समष्टि आर्थिक एवं मूल्य स्थायित्व के लिए सहायक हो और विकास संवेग को बनाए रखे और इसके अतिरिक्त, उभरती हुई परिस्थितियों की प्रतिक्रिया स्वरूप, मुद्रास्फीतीय प्रत्याशाओं को स्थिर रखने के दृष्टिकोण से, नपे तुले अविलंब तौर से उपायों पर विचार करे।

2.65 2005-06 (जनवरी 24, 2006) के लिए रिजर्व बैंक की वार्षिक नीति वक्तव्य की तीसरी तिमाही समीक्षा ने ध्यान दिया कि समष्टि आर्थिक गतिविधियों के सूचित मूल्यांकन पर आधारित, एक प्रगतिशील ढंग से विकास और मुद्रास्फीति पर दृष्टिकोण के साथ और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिकूल और अप्रत्याशित गतिविधियों के निर्गम को छोड़कर, वर्तमान समय पर मौद्रिक नीति का समग्र रुझान होगा :

- मुद्रास्फीतीय प्रत्याशाओं को स्थिर रखने के दृष्टिकोण से मूल्य स्थिरता पर जोर को बनाए रखना।

- समष्टि आर्थिक, कीमत और वित्तीय स्थायित्व के लिए एक अनुकूल ब्याज दर माहौल सुनिश्चित करते हुए, विकास संवेग को बनाए रखने के लिए निर्यात और अर्थव्यवस्था में निवेश की मांग को सहायता जारी रखना।
- गुणवत्ता पर उचित ढंग से जोर देते हुए, अर्थव्यवस्था की प्रामाणिक ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयुक्त चलनिधि उपलब्ध कराना।
- उत्पन्न हुई परिस्थितियों के उपयुक्त प्रतिक्रियाओं का विचार करना।

आरक्षित मुद्रा सर्वेक्षण

2.66 फरवरी 24, 2006 को 18.3 प्रतिशत पर आरक्षित मुद्रा का विस्तार, वर्ष-दर-वर्ष, एक वर्ष पहले के 15.3 प्रतिशत से उच्चतर था। वर्तमान राजकोषीय के अधिकांश हिस्से के लिए आरक्षित मुद्रा में उच्चतर विकास, अधिकांशतः चलनिधि समायोजन सुविधा (एल ए एफ) परिचालनों के माध्यम से चलनिधि के निवल अंतःक्षेप और बाजार स्थिरीकरण योजना (एम एस एस) को मुक्त करने के कारण संचलित था (सारणी 2.25)।

2.67 वर्ष 2005-06 के दौरान (फरवरी 24, 2006 तक), माल व्यापार के घाटे में सुस्पष्ट वृद्धि और घरेलू ऋण की मांग में बढ़त के कारण रिजर्व बैंक के बाजार परिचालनों ने प्रणाली में चलनिधि

सारणी 2.25 : आरक्षित मुद्रा के प्रमुख घटकों और स्रोतों में भिन्नता

(करोड़ रुपए)

मद	2004-05	2005-06 (फरवरी 24 तक)	2004-05				2005-06		
			ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आरक्षित मुद्रा	52,623	63,100	-6,812	-6,285	31,546	34,174	7,177	1,072	25,428
घटक									
1. संचलन में करेंसी	41,633	54,808	14,317	-4,166	16,467	15,015	19,877	-9,479	29,130
2. रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमा	9,631	9,615	-19,665	-2,874	14,769	17,401	-10,680	9,780	-2,967
3. रिजर्व बैंक के पास "अन्य" जमा	1,359	-1,323	-1,463	755	310	1,757	-2,021	771	-736
स्रोत									
1. रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण उसमें से : केन्द्र को	-62,882	51,593	-34,143	-6,179	184	-22,744	9,275	-25,251	19,879
2. बैंकों को और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-833	248	-2,985	-740	3,726	-835	1,155	-1,869	101
3. रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (एनएफईए)	1,28,377	12,985	57,525	-5,260	31,462	44,651	-14,595	24,823	23,741
4. जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	152	1,170	37	9	89	17	384	910	-124
5. रिजर्व बैंक की निवल मुद्रा देयता	12,191	2,895	27,245	-5,885	3,916	-13,085	-10,957	-2,460	18,169
ज्ञापन मद :									
1. निवल घरेलू आस्तियाँ	-75,754	50,116	-64,336	-1,025	84	-10,477	21,771	-23,751	1,687
2. एफ सी ए, पुनर्मूल्यन के लिए समायोजित	1,15,044	25,598	33,160	-3,413	29,858	55,440	5,034	23,665	11,998
3. प्राधिकृत व्यापारियों से निवल खरीद	91,105	-4,812	30,032	-9,789	22,771	48,091	-	17,027	-
4. एनएफईए/आरक्षित मुद्रा (प्रतिशत) (समाप्त अवधि)	125.3	113.3	126.1	126.7	124.9	125.3	120.5	125.3	123.7
5. एनएफईए/ मुद्रा (प्रतिशत)	166.2	147.8	158.8	159.2	160.7	166.2	154.0	164.4	158.4
एनएफईए : निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ।									
एफसीए : विदेशी मुद्रा आस्तियाँ।									
ध्यान दें : चौथी तिमाही के लिए (ति4) त्रैमासिक भिन्नता मार्च 31 पर आधारित है और अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार अन्य तिमाहियों के लिए।									

सारणी 2.26 : रिज़र्व बैंक के चलनिधि प्रबंध परिचालनों के चरण

(करोड़ रुपए)

मद	अप्रैल 1- जुलाई 22, 2005	जुलाई 23- अगस्त 12, 2005	अगस्त 13- अक्टूबर 28, 2005	अक्टूबर 29, 2005-फरवरी 24, 2006
1	2	3	4	5
क. चलनिधि के चालक (1+2+3)	-6,737	27,792	-15,127	-60,036
1. रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (पुनर्मूल्यान के लिए समायोजित)	6,412	19,348	5,193	-5,355
2. जनता के पास मुद्रा	-15,274	-1,529	-7,940	-29,490
3. अन्य (अवशिष्ट)	2,125	9,973	-12,380	-25,191
3.1 रिज़र्व बैंक के पास केंद्र की अधिशेष नकदी शेष जमाराशि	6,053	5,972	-7,421	-15,515
ख. चलनिधि का प्रबंध (4+5+6+7)	1,329	-24,567	16,187	71,349
4. चलनिधि समायोजन सुविधा (एल ए एफ) रेपो का चलनिधि प्रभाव	8,845	-26,565	16,210	33,555
5. खुला बाजार परिचालन का चलनिधि प्रभाव (निवल)*	0	0	0	0
6. बाजार स्थिरीकरण योजना का चलनिधि प्रभाव	-7,516	1,998	-23	37,794
7. नकदी आरक्षित अनुपात (सी आर आर) बदलाव के कारण प्रथम दौर चलनिधि प्रभाव	0	0	0	0
ग. बैंक भंडार # (क+ख)	-5,408	3,225	1,060	11,313

+ बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि प्रवाहित करने का संकेत देता है।

- बैंकिंग प्रणाली से चलनिधि के अवशोषण का संकेत देता है।

बैंकों के पास वॉल्ट नकदी और नकदी आरक्षित अनुपात (सी आर आर) बदलाव के कारण प्रथम दौर चलनिधि प्रभाव के लिए समायोजित, शामिल हैं।

* समेकित शोधन निधियाँ (सी एस एफ) और अन्य निवेश के लिए समायोजित।

उपलब्ध कराई (सारणी 2.26)। दिसंबर 2005 के दौरान, बैंकिंग प्रणाली ने कुछ चलनिधि दबावों का, इंडिया मिलेनियम डिपॉजिटों (आई एम डी) के विमोचन के संदर्भ में, सामना किया। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने रेपो परिचालनों के माध्यम से और बाजार स्थिरीकरण योजना (एम एस एस) को मुक्त करके चलनिधि को प्रवाहित किया।

2.68 केंद्र को निवल रिज़र्व बैंक ऋण, चलनिधि परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में अपने बाजार परिचालनों को दर्शाते हुए, 2005-06 के दौरान, पिछले वर्ष की तदनुसूची कालावधि में 43,800 करोड़ रुपए की गिरावट के विपरीत, अब तक (फरवरी 24, 2006) 56,904 करोड़ रुपए से बढ़ा (सारणी 2.27)।

सारणी 2.27 : केंद्र को निवल रिज़र्व बैंक ऋण- भिन्नताएँ

(करोड़ रुपए)

परिवर्ती	2004-05	2005-06 (फरवरी 24 2006 तक)	2004-05				2005-06		
			ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
केंद्र को निवल रिज़र्व बैंक ऋण (1+2+3+4-5)	-60,177	56,904	-30,029	-4,499	203	-25,852	14,600	-25,251	19,812
1. ऋण और अग्रिम	0	0	3,222	-3,222	0	0	0	0	0
2. रिज़र्व बैंक द्वारा धारित खजाना बिल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. रिज़र्व बैंक द्वारा धारित दिनांकित प्रतिभूतियाँ	12,323	25,975	-2,900	22,176	14,095	-21,048	8,221	-17,243	19,378
4. रिज़र्व बैंक द्वारा धारित रुपए सिक्के	57	53	175	-10	-94	-14	-40	-33	157
5. केंद्र सरकार की जमाराशियाँ	72,558	-30,874	30,525	23,443	13,799	4,791	-6,419	7,974	-277
ज़ापन मद*									
1. केंद्र द्वारा दिनांकित प्रतिभूतियों का बाजार उधार+	80,350	1,21,000	28,000	26,000	14,000	12,350	42,000	39,000	24,000
2. रिज़र्व बैंक का दिनांकित प्रतिभूतियों को प्राथमिक अंशदान	1,197	0	0	847	0	350	0	0	0
3. रेपो (+) / रिवर्स रेपो (-) (चलनिधि समायोजन सुविधा), निवल स्थिति	15,315	32,045	-26,720	34,205	27,600	-19,770	9,660	-14,835	18,635
4. निवल खुले बाजार बिक्री #	2,899	3,718	429	427	871	1,171	1,543	941	261
5. बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत संग्रहण	64,211	-32,253	37,812	14,444	353	11,602	7,469	-4,353	-19,713
6. प्राथमिक परिचालन \$	-6,625	-12,237	37,353	-30,484	-36,984	23,490	18,205	-24,689	-38,715

* अंकित मूल्य पर।

खजाना बिलों को अलग करता है परंतु समेकित ऋण शोधन निधियों और अन्य निवेशों को सलमिलित करके।

+ खजाना बिलों को छोड़कर।

\$ बाजार स्थिरीकरण योजना के लिए समायोजित और केंद्र का अधिशेष निवेश।

ध्यान दें : चौथी तिमाही के लिए (ति4) त्रैमासिक भिन्नता मार्च 31पर आधारित हैं और अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार अन्य तिमाहियों के लिए।

मौद्रिक सर्वेक्षण

2.69 फरवरी 17, 2006 को व्यापक मुद्रा (एम₃) में वर्ष-दर-वर्ष विकास, एक वर्ष पहले के 13.0 प्रतिशत की तुलना में, 16.3 प्रतिशत था (सारणी 2.28)। उच्चतर व्यापक मुद्रा विकास वाणिज्य क्षेत्र को उच्चतर ऋण के अलावा आधार प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है। खाद्येतर ऋण में जारी बढ़त और एक उत्साहजनक प्राथमिक पूंजी बाजार के साथ, अस्थायी रूप से निधियों को माँग जमाराशियों में रखने से माँग जमाराशियों में वृद्धि ऊंची रही। 2005-06 के अधिकांश भाग के दौरान मीयादी जमाराशियों में वृद्धि उच्चतर थी, जो आधार प्रभाव को अंशतः दर्शाता है। तथापि, जनवरी 2006 में मीयादी जमाराशियों की वृद्धि में, इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट के विमोचन को दर्शाते हुए, मंदी हुई। फरवरी 17, 2006 के समय वाणिज्य क्षेत्र के बैंक ऋण में 28.5 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष), एक वर्ष पहले की 22.00 वृद्धि के ऊपर, हुई। वाणिज्य ऋण की बढ़ती हुई माँग को बैंकों द्वारा, अधिकांशतः सरकारी प्रतिभूतियों में वृद्धिशील निवेश को घटाकर, पूरा किया गया।

बैंक ऋण

2.70 बैंक ऋण की माँग ने, कि जिसने 2004-05 के द्वितीय अर्ध में तीव्र गतिवृद्धि दर्शायी, 2005-06 में अपनी गति जारी रखी। फरवरी 17, 2006 के समय, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए वर्ष-दर-वर्ष खाद्येतर ऋण, पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में 26.6 प्रतिशत (रूपांतरण का निवल) के विकास से ऊपर, 33.6 प्रतिशत से बढ़े (सारणी 2.29 और चार्ट II. 10)। ऋण की बढ़ती हुई माँग जारी रहने के कारण, बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों में अपने वृद्धिशील निवेश को सीमित रखा।

2.71 कृषि, उद्योग और आवास निर्माण क्षेत्रों द्वारा मार्गदर्शित बैंक ऋण की माँग विस्तार आधारित रही है। कृषि संबंधी क्षेत्र को ऋण ने सुदृढ़ विकास दर्ज करना जारी रखा जो क्षेत्र के ऋण प्रवाह में सुधार के लिए विभिन्न नीति पहलों को दर्शाता है (सारणी 2.30)। औद्योगिक गतिविधि में बढ़त के अनुसरण में औद्योगिक ऋण में वृद्धि, प्रमुख रूप से ऑटो मोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्माण, पेट्रोलियम,

सारणी 2.28 : मौद्रिक संकेतक

(करोड़ रुपए)

परिवर्ती	फरवरी 17, 2006 के समय बकाया	भिन्नता (वर्ष-दर-वर्ष)			
		2004-05		2005-06	
		वास्तविक संख्या	प्रतिशत	वास्तविक संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
I. आरक्षित मुद्रा*	5,52,235	62,004	15.3	85,577	18.3
II. व्यापक मुद्रा (एम ₃)	25,80,002	2,55,294	13.0	3,61,783	16.3
क) जनता के पास मुद्रा	4,11,448	36,748	11.7	61,810	17.7
ख) कुल जमाराशियाँ	21,63,650	2,17,652	13.2	2,99,434	16.1
i) माँग जमाराशियाँ	3,53,867	42,255	18.2	79,737	29.1
ii) मीयादी जमाराशियाँ	18,09,783	1,75,397	12.4	2,19,696	13.8
उसमें से: अनिवासी विदेशी मुद्रा जमाराशियाँ	56,063	-255	-0.3	-19,499	-25.8
III. एनएम ₃	25,96,791	2,62,210	13.7	3,86,563	17.5
उसमें से: वित्तीय संस्थाओं से माँग मुद्रा निधीयन	77,155	7,298	31.4	11,448	17.4
IV. क) एल ₁	26,98,623	2,78,885	14.1	4,02,527	17.5
उसमें से: डाक जमाराशियाँ	1,01,832	16,675	24.1	15,964	18.6
ख) एल ₂	27,00,274	2,73,674	13.8	4,02,527	17.5
उसमें से: विसं जमाराशियाँ	1,651	-5,211	-75.9	0	0.0
ग) एल ₃	26,52,955	2,68,237	13.8	4,06,749	18.1
उसमें से: बैंकिंग जमाराशियाँ	21,694	-403	-2.0	1,796	9.0
V. व्यापक मुद्रा के प्रमुख स्रोत					
क) सरकार को निवल बैंक ऋण (i+ii)	7,77,319	12,342	1.7	18,337	2.4
i) सरकार को निवल रिजर्व बैंक ऋण	24,754	-39,506		26,792	
उसमें से: केंद्र को	24,796	-35,030		29,313	
ii) सरकार को अन्य बैंक ऋण	7,52,565	51,848	7.4	-8,455	-1.1
ख) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	15,85,853	2,16,567	22.0	3,52,128	28.5
ग) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	6,61,279	97,481	18.8	45,472	7.4

* आंकड़ें फरवरी 24, 2006 से संबंधित हैं। विसं : वित्तीय संस्थाएँ। गैर बैंकिंग : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ।

टिप्पणी: 1. आंकड़े अंतिम हैं।

2. चयनित समुच्चय की भिन्नताएँ, अक्टूबर 11, 2004 से गैर बैंकिंग इकाई को बैंकिंग इकाई में रूपांतरण के प्रभाव के लिए समायोजित की गई हैं।

3. एल₃ दिसंबर 2005 से संबंधित है।

सारणी 2.29 : अनुसूचित वाणिज्य बैंक : चयनित बैंकिंग संकेतकों में भिन्नता

(करोड़ रुपए)

मद	2003-04		2004-05		वर्ष-दर-वर्ष भिन्नता			
					2004-05 (फरवरी 18, 2005 तक)		2005-06* (फरवरी 17, 2006 तक)	
	वास्तविक संख्या	प्रतिशत	वास्तविक संख्या	प्रतिशत	वास्तविक संख्या	प्रतिशत	वास्तविक संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल जमाराशियाँ	2,23,563	17.5	1,92,269	12.8	2,10,255	14.3	2,86,458	17.0
माँग जमाराशियाँ	54,733	32.1	23,005	10.2	39,462	19.5	75,804	31.4
मीयादी जमाराशियाँ	1,68,830	15.2	1,69,264	13.2	1,70,793	13.5	2,10,655	14.6
बैंक ऋण	1,11,570	15.3	2,26,761	27.0	2,12,987	26.2	3,40,709	32.2
खाद्य ऋण	-13,518	-27.3	5,159	14.4	6,214	17.6	-954	-2.3
खाद्येतर ऋण	1,25,088	18.4	2,21,602	27.5	2,06,772	26.6	3,41,663	33.6
निवेश	1,30,042	23.8	49,373	7.3	36,999	5.5	-8,679	-1.2
सरकारी प्रतिभूतियाँ	1,31,341	25.1	52,031	8.0	39,754	6.1	-11,421	-1.6
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-1,299	-5.4	-2,658	-11.6	-2,755	-11.9	2,743	13.4

* अंतिम ।

ध्यान दें : 11 अक्टूबर 2004 से गैर बैंकिंग इकाई को बैंकिंग इकाई में रूपांतरण के प्रभाव को आंकड़े अलग करते हैं। आंकड़े दिसंबर 29, 2005 को इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट के विमोचन के प्रभाव को भी दर्शाते हैं।

रत्न और आभूषण, अन्य धातु और धातु उत्पादों, कपड़े और रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों के कारण थी। निम्न ब्याज दर एवं कर प्रोत्साहन से लाभान्वित होते हुए आवास निर्माण क्षेत्र का ऋण सुदृढ़ रहा।

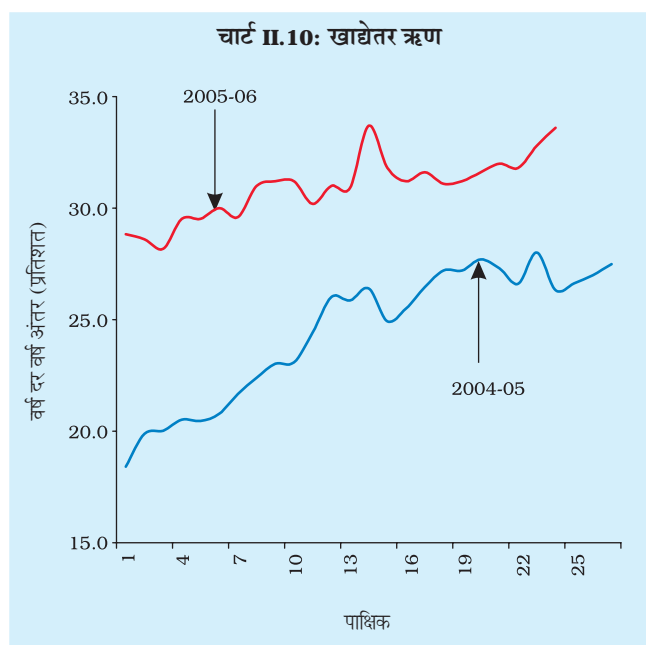
2.72 बैंक ऋण के अतिरिक्त, कंपनी क्षेत्र भी, हाल के वर्षों में, निधियों के गैर बैंक स्रोतों पर अधिकतर निर्भर रहे। पूंजी बाजारों में उछाल से लाभान्वित होकर अप्रैल-दिसंबर 2005 के दौरान ईक्विटी प्रचालन बढ़ा। वाणिज्यिक पत्रों के प्रचालन द्वारा संग्रहण भी सुदृढ़

रहा, हालाँकि, कुछ हद तक एक वर्ष पहले की अपेक्षा निम्नतर था। बाह्य वाणिज्यिक उधार (ई सी बी) के अंतर्गत अप्रैल-सितंबर 2005 के दौरान निवल निकासी लगभग वैसी ही थी कि जैसा एक वर्ष पहले, जो कि उत्साहजनक आर्थिक गतिविधि दर्शाती है (सारणी 2.31)।

मूल्य स्थिति

2.73 2005 की तीसरी तिमाही के दौरान कई अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति मजबूत हुई, जो कि कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तीव्र वृद्धि के प्रभाव को दर्शाती है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओ पी ई सी) द्वारा समय-समय पर आपूर्ति में वृद्धि करने के बावजूद, वैश्विक माँग में सुदृढ़ विकास विशेषतः अमरीका और चीन से, निम्न स्तरों की वैश्विक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता और उच्चतर ऊर्जा लागतों को आर्थिक लचिलेपन ने, तेल की कीमतों को उच्च स्तरों पर समर्थन दिया। अमरीकी बाजार में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें, अगस्त 30, 2005 को हरीकेन कैटरिना के परिणाम के तुरंत बाद, अमरीका में उष्ण कटिबंधीय तूफान, मध्य पूर्व से भू-राजनैतिक अनिश्चितता से आपूर्ति की अस्थिरता और सट्टेबाजी की प्रवृत्ति वाली खरीद के कारण आपूर्ति में विघटन की चिंता के बीच, प्रति बैरल अमरीकी डॉलर 70 को पार करके एक ऐतिहासिक ऊँचाई पर पहुँची (चार्ट II.11)। चौथी तिमाही के दौरान, यद्यपि ऊर्जा कीमतों में कुछ नरमी के कारण मुद्रास्फीति थोड़ी सामान्य हुई, वह उच्च स्तर पर सतत बनी रही।

2.74 कच्चे तेल की रिकार्ड ऊंची कीमत का वैश्विक आर्थिक गतिविधि और मुद्रास्फीति प्रत्याशा पर प्रभाव, पूर्ववर्ती तेल आघातों



हाल की आर्थिक गतिविधियाँ

सारणी 2.30 : खाद्येतर बैंक ऋण का विनियोजन

(करोड़ रुपए)

क्षेत्र / उद्योग	अक्टूबर 28, 2005 के समय बकाया	वित्तीय वर्ष भिन्नताएँ			
		अप्रैल-अक्टूबर 2004		अप्रैल-अक्टूबर 2005	
		वास्तविक संख्या	प्रतिशत	वास्तविक संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
सकल खाद्येतर बैंक ऋण	11,57,769	92,054	12.6	1,57,981	15.8
<i>उसमें से</i>					
कृषि और सहायक गतिविधियाँ	1,41,612	11,267	12.4	16,362	13.1
उद्योग (लघु, मध्यम और बड़े)	4,75,915	26,738	8.5	49,023	11.5
लघु उद्योग	78,780	1,322	2.0	4,192	5.6
व्यापार	69,315	7,580	30.5	11,367	19.6
गृह निर्माण	1,53,267	न.उ.	न.उ.	24,539	19.1
फिक्स्ड जमाराशियों के बदले अग्रिम	30,283	-651	-2.5	433	1.5
स्थावर संपदा ऋण	20,148	2,663	47.7	6,846	51.5
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	25,672	604	3.6	3,188	14.2
ज्ञापन :					
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	4,33,422	26,181	9.9	51,946	13.6
उद्योग (लघु, मध्यम और बड़े)	4,75,915	26,738	8.5	49,023	11.5
खाद्य प्रसंस्करण	26,259	-361	-1.7	1,826	7.5
कपड़े	48,229	-44	-0.1	4,252	9.7
कागज और कागज उत्पाद	7,910	181	3.0	1,028	14.9
पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और न्यूक्लियर ईंधन	20,549	3,533	28.8	4,980	32.0
रसायन और रासायनिक उत्पाद	40,723	-847	-2.8	1,231	3.1
रबर, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	5,596	249	9.6	1,930	52.6
लोहा और इस्पात	42,138	10	0	6,137	17.0
अन्य धातु और धातु उत्पाद	13,968	1,006	12.3	2,332	20.0
अभियांत्रिकी	32,694	-1,033	-3.9	3,298	11.2
वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपकरण	15,825	262	4.9	3,963	33.4
रत्न और आभूषण	17,880	2,323	25.3	3,574	25.0
निर्माण	10,726	1,716	28.7	2,604	32.1
इन्फ्रास्ट्रक्चर	96,639	14,169	27.6	17,630	22.3

न.उ. : नहीं उपलब्ध।

ध्यान दें : 1. आंकड़ें अनंतिम हैं और चयनित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं जो सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण का लगभग 90 प्रतिशत हैं।
2. क्षेत्रों / उद्योगों के वर्गीकरण में बदलाव और बैंकों के कार्यक्षेत्र के कारण, 2005-06 के लिए आंकड़े पूर्ववर्ती आंकड़ों से तुलनीय नहीं हैं।

की तुलना में, अब तक अधिकांशतः निष्प्रभावी प्रतीत होता है (चार्ट II.12 और सारणी 2.32)। इसका श्रेय, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में तेल की घटती हुई तीव्रता, वैश्वीकरण द्वारा प्रोत्साहित बढ़ी हुई स्पर्धा,

अंतिम उत्पादन में पण्य कीमतों की घटती हुई भूमिका, अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों का, सरकार द्वारा भार बाँटने के कारण, घरेलू तेल कीमतों को पास-थ्रू, विशेषतः कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में और प्रमुख

सारणी 2.31 : उद्योग के निधियों का चयनित स्रोत

(करोड़ रुपए)

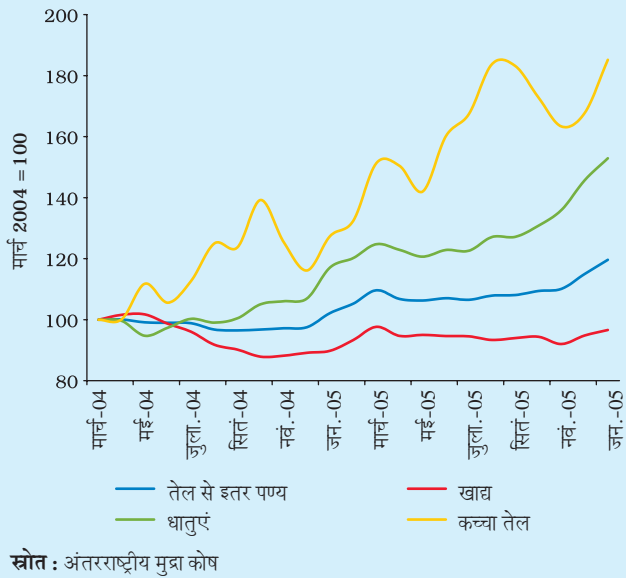
मद	अप्रैल-सितंबर 2004	अप्रैल-सितंबर 2005
1	2	3
I. उद्योग को बैंक ऋण (लघु, मध्यम और बड़े) (अक्टूबर तक)	26,738	49,023
II. गैर बैंकों से कंपनियों को प्रवाह		
1. पूंजी निर्गम * (i+ ii) (दिसंबर तक)	7,971	11,628
i) गैर- सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (क + ख)	5,287	11,628
क) बंधपत्र / डिबेंचर	0	118
ख) शेयर	5,287	11,510
ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी कंपनियाँ	2,684	0
2. अमरीकी निक्षेपागार (डिपाजिटरी) रसीद / वैश्विक निक्षेपागार (डिपाजिटरी) रसीद निर्गम + (दिसंबर तक)	1,642	5,165
3. बाह्य वाणिज्यिक उधार राशियाँ (ईसीबी) \$	15,872	16,264
4. वाणिज्यिक पत्रों का निर्गम (दिसंबर तक)	4,141	2,946
III. करोत्तर लाभ £	23,400	34,895
IV. मूल्यहास प्रावधान £	11,340	14,754

* सकल प्रचालन सिवाय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्गम। लिए बैंकों के पूंजी निर्गमों के निवेशके लिए आँकड़े समायोजित नहीं हैं, जो कि उल्लेखनीय नहीं हैं ऐसी आशा है।
+ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्गमों को छोड़कर। \$ अल्प-अवधि ऋण समेत।

£ आंकड़े, गैर-वित्तीय गैर सरकारी कंपनियों के चयनित नमूनों के लेखापरीक्षित / अलेखापरीक्षित संक्षिप्त परिणामों पर आधारित हैं।

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

चार्ट II.11: अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्य



केंद्रीय बैंकों द्वारा दूसरे-दौर के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए पूर्वक्रय मौद्रिक कठोरता, को दिया जा सकता है।

2.75 मुद्रास्फीति पर ऊर्ध्वमुखी दबावों को दर्शाते हुए, कई केंद्रीय बैंकों ने अपनी मौद्रिक नीतियों को कड़ा किया, विशेषतः उभरते एशिया में। अमरीका में, उपभोक्ता कीमत मुद्रास्फीति, जो सितंबर 2005 में ऊर्जा लागतों में तीव्र वृद्धि को दर्शाते हुए 4.7 प्रतिशत त्वरित हुई थी, जनवरी 2006 में 4.0 प्रतिशत तक सामान्य हुई। सुदृढ़ आर्थिक गतिविधि और आरंभिक मुद्रास्फीतीय दबावों के बल पर, अमरीकी फेडरल खुला बाजार समिति (एफ ओ एम सी) अपनी मौद्रिक कड़ाई की नियत गति पर दृढ़ रहा, अपने लक्ष्य फेडरल फंड दर को 175 आधार अंकों से बढ़ाते हुए (25 आधार अंकों की वृद्धि प्रत्येक सात बैठकों में), मार्च 2005 की समाप्ति से जनवरी 31, 2006 को 4.50 प्रतिशत तक। यू.के. में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति जो सितंबर 2005 में, उच्चतर

सारणी 2.32 : वार्षिक उपभोक्ता कीमत मुद्रास्फीति

(प्रतिशत)

देश/क्षेत्र	2000	2001	2002	2003	2004	2005पी
1	2	3	4	5	6	7
उन्नत अर्थ व्यवस्थाएँ	2.2	2.1	1.5	1.8	2.0	2.2
अमरीका	3.4	2.8	1.6	2.3	2.7	3.1
जापान	-0.9	-0.7	-1.0	-0.2	0.0	-0.4
यूरो क्षेत्र	2.1	2.3	2.3	2.1	2.1	2.1
अन्य उभरते बाजार और विकासशील देश	7.3	6.7	5.9	6.0	5.8	5.9
विकासशील एशिया	1.9	2.7	2.1	2.6	4.2	4.2
चीन	0.4	0.7	-0.8	1.2	3.9	3.0
भारत	4.0	3.8	4.3	3.8	3.8	3.9

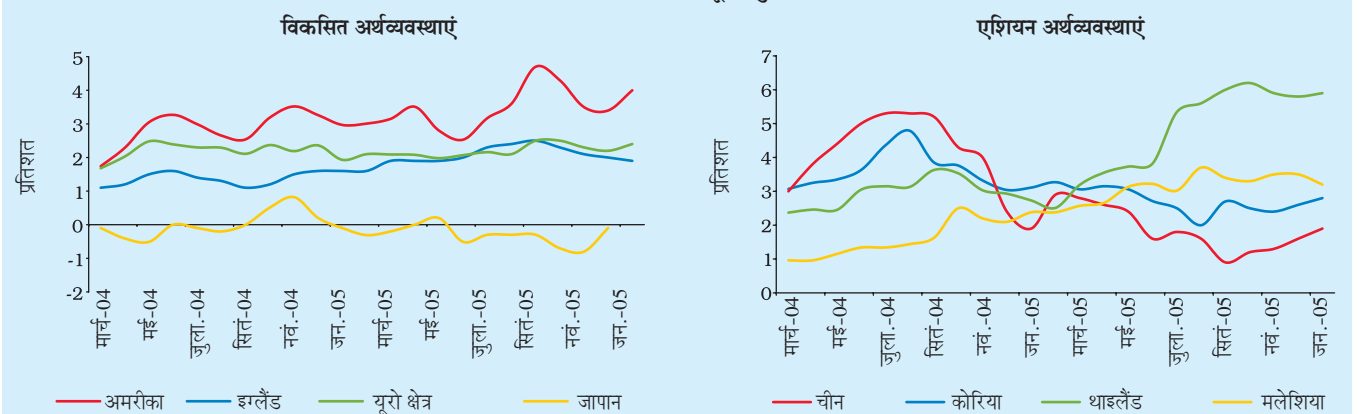
पी : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अनुमान।

स्रोत : विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, सितंबर 2005, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष।

तेल कीमतों के कारण, 2.5 प्रतिशत तक बढ़ी (एक वर्ष पहले 1.1 प्रतिशत) जनवरी 2006 में 1.9 प्रतिशत तक सामान्य हो गई। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, जिसने अगस्त 4, 2005 को, आर्थिक गतिविधि के कमजोर होने की प्रतिक्रिया स्वरूप, नीति रेपो दर 25 आधार अंकों से काटा था, अब तक अपना नीति रुझान बनाए रखा है। यूरो क्षेत्र में, मुद्रास्फीति, जिसे समीकृत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एच आई सी पी) द्वारा मापा जाता है, सितंबर 2005 में, लक्ष्य से अधिक, 2.5 प्रतिशत तक बढ़ी और जनवरी 2006 में 2.4 प्रतिशत थी। तेल मूल्यों में जारी वृद्धि के संभाव्य दूसरे दौर के प्रभाव और नियंत्रित कीमतों में अतिरिक्त वृद्धि तथा परोक्ष कर को ऊपरी सतह के जोखिमों की तरह देखने को ध्यान में रखते हुए, यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ई सी बी) ने, दिसंबर 1, 2005 को यूरो क्षेत्र में मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को समर्थन देने के लिए प्रमुख नीति दर को 25 आधार अंकों से बढ़ा दिया।

2.76 उभरते एशिया में, इंडोनेशिया, थाइलैंड, फिलीपीन्स और मलेशिया में, उच्चतर तेल कीमतों के प्रभाव के अंतर्गत, मुद्रास्फीति ऊंची रही, यद्यपि हाल के महीने में कुछ आसान हुई। इसलिए, इन देशों

चार्ट II.12: उपभोक्ता मूल्य मुद्रा स्फीति



के केंद्रीय बैंकों ने 2005 के दौरान अपनी नीति दरों को बढ़ाया (सारणी 2.33)। दूसरी तरफ, चीन में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति जनवरी 2006 में 1.9 प्रतिशत थी-पिछले वर्ष की ही तरह-जो कि उच्चतर तेल कीमतों का घरेलू तेल कीमतों का अपूर्ण अंतरण दर्शाता है।

2.77 भारत में, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तनों द्वारा मापी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति, मार्च 2005 की समाप्ति पर 5.1 प्रतिशत से (और एक वर्ष पहले 5.1 प्रतिशत) फरवरी 11, 2006 को 4.0 प्रतिशत पर सामान्य हुई। औसत थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर एक वर्ष पहले के 6.4 प्रतिशत से 4.6 प्रतिशत पर सामान्य हुई (चार्ट II.13)। पेट्रोल और डीजल कीमतों में वृद्धि (7-8 प्रतिशत प्रत्येक, जून और सितंबर 2005 में) और जून 2005 में विद्युत कीमतों में वृद्धि के बावजूद, हेडलाइन मुद्रास्फीति में संतुलन, नपे तुले मौद्रिक और राजकोषीय उपायों और आधार प्रभावों को दर्शाता है। तथापि, यह जानना जरूरी है कि ऊंची अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल कीमतों का घरेलू कीमतों को पास-थू अधूरा है क्योंकि उसे केवल पेट्रोल और डीजल तक सीमित रखा गया है।

2.78 वर्ष 2005-06 के दौरान मुद्रास्फीति, खनिज तेल की कीमतों के प्रभुत्व में रही है कि जिसने अकेले एक तिहाई से अधिक हेडलाइन मुद्रास्फीति को योगदान दिया। वर्ष-दर-वर्ष थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति, ईंधन समूह को छोड़कर, फरवरी 11, 2006 को 3.0 प्रतिशत पर निम्नतर थी।

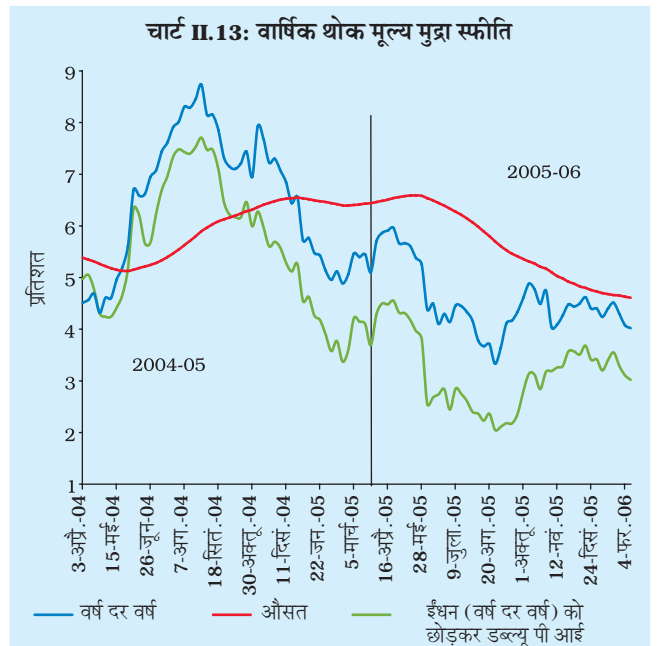
सारणी 2.33 : केंद्रीय बैंक नीति दरें

(प्रतिशत)

देश	जनवरी 1, 2003	जनवरी 1, 2004	जनवरी 1, 2005	जनवरी 28, 2006
1	2	3	4	5
आस्ट्रेलिया	4.75	5.25	5.25	5.50
ब्राजील	25.00	16.50	17.75	17.25
कनाडा	2.75	2.75	2.50	3.50
यूरो क्षेत्र	2.75	2.00	2.00	2.25
भारत*	5.50	4.50	4.75	5.50
इंडोनेशिया	12.93	8.31	7.43	12.75
इज्राइल	8.90	4.80	3.70	4.75
जापान	0.10	0.10	0.10	0.10
कोरिया	4.25	3.75	3.25	4.00
न्यूजीलैंड	5.75	5.00	6.50	7.25
पोलैंड	6.50	5.25	6.50	4.25
स्वीडन	3.75	2.75	2.00	2.00
स्विट्जरलैंड	0.25-1.25	0-0.75	0.25-1.25	0.50-1.50
थाइलैंड	1.75	1.25	2.00	4.25
यू. के.	4.00	3.75	4.75	4.50
यू.एस. ए.	1.25	1.00	2.25	4.50

* : रिवर्स रेपो दर।

स्रोत: केंद्रीय बैंक वेबसाइट



2.79 ईंधन समूह के अलावा, सब्जियाँ, अंडे, मांस और मछली और चीनी कीमतों ने, घरेलू मुद्रास्फीति पर, कुछ ऊर्ध्वमुखी दबाव डाला। पिछले वर्ष की अपेक्षा उच्चतर खाद्यान्न उत्पादन की संभावना से प्राथमिक कृषि संबंधी पण्य की कीमतें संतुलित रहने की आशा है। उच्चतर गन्ना उत्पादन चीनी कीमतों को, जो अभी तक अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्तियों की तरह ऊंची और अस्थिर रही हैं, नियंत्रित रखेगा ऐसी आशा है। कुल मिलाकर, ईंधन समूह (41.2 प्रतिशत) ने, फरवरी 11, 2006 के वर्ष-दर-वर्ष थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति को अधिकतम योगदान किया जिसका अनुरण निर्मित उत्पादों (31.9 प्रतिशत) और प्राथमिक वस्तुओं (27.5 प्रतिशत) ने किया (सारणी 2.34)।

2.80 दिसंबर 2005 के दौरान उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति अपने मार्च 2005 के स्तर से बढ़ी जो उच्चतर खाद्य और ईंधन कीमतों को दर्शाता है (सारणी 2.35)।

2.81 इस प्रकार, 2005-06 के दौरान मुद्रास्फीति परिणाम रिकार्ड ऊंची अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल कीमतों के प्रभुत्व में रहा। हालाँकि, ऊंची अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल कीमतों का घरेलू कीमतों को कुछ पास-थू हुआ, उसके दूसरे दौर का प्रभाव अभी तक दिखाई नहीं देता। यद्यपि, सरकार ने कर ढाँचे में संशोधन के माध्यम से घरेलू कीमतों पर प्रभाव को संतुलित किया, ऐसा राजकोषीय युक्तिचालन सीमित होता है। चलनिधि अधिकता का भलीभांति प्रबंध, चलनिधि प्रबंध परिचालनों (चलनिधि समायोजन सुविधा और बाजार स्थिरीकरण योजना) के माध्यम के अलावा, मौद्रिक क्रियाओं, जैसे नकदी आरक्षित अनुपात में वृद्धियाँ (50 आधार अंक सितंबर-अक्टूबर 2004 के दौरान) और रिवर्स रेपो दर (25 आधार अंक प्रत्येक अक्टूबर 2004, अप्रैल 2005, अक्टूबर 2005 और जनवरी 2006 में) जिसने मूल्य स्थिरता के लिए प्रमाण्य

सारणी 2.34 : अवयव द्वारा वार्षिक अंक-दर-अंक थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति
(आधार 1993-94=100)

(प्रतिशत)

समूह / मद	भार	वार्षिक भिन्नता			भिन्नता		भारत योगदान	
		2002-03	2003-04	2004-05	2004-05 (फरवरी 12)	2005-06 (फरवरी 11)	2004-05 (फरवरी 12)	2005-06 (फरवरी 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सभी पण्य	100.0	6.5	4.6	5.1	5.1	4.0	100.0	100.0
I. प्राथमिक वस्तुएँ	22.0	6.1	1.6	1.3	1.3	5.1	5.7	27.5
i) अनाज	4.4	4.0	-0.3	2.9	1.7	5.6	1.4	5.9
ii) दालें	0.6	0.3	-2.6	-2.6	-3.1	20.7	-0.4	2.8
iii) फल और सब्जियाँ	2.9	-1.2	-4.9	11.6	4.0	9.5	2.3	7.0
iv) कच्चा सूत	1.4	34.3	12.3	-23.8	-26.9	3.1	-7.6	0.8
v) तिलहन	2.7	30.0	-1.2	-6.5	-5.8	-12.1	-3.1	-7.4
vi) गन्ना	1.3	11.5	6.5	-0.7	-0.7	0.7	-0.2	0.3
II. ईंधन, पावर, रोशनी और चिकनाई	14.2	10.8	2.5	10.5	10.2	7.6	41.6	41.2
i) खनिज तेल	7.0	18.4	0.0	16.0	14.9	11.9	32.7	36.1
ii) विद्युत	5.5	3.4	4.9	0.8	1.6	2.7	2.4	5.1
iii) कोयला खनन	1.8	0.0	9.2	17.1	17.1	0.0	6.4	0.0
III. निर्मित उत्पाद	63.7	5.1	6.7	4.6	4.7	2.3	52.7	31.9
i) चीनी	3.6	-15.0	16.9	19.7	20.7	6.6	10.9	5.1
ii) खाद्य तेल	2.8	27.4	6.6	-8.4	-8.2	-3.4	-4.0	-1.8
iii) तेल खली	1.4	40.3	5.0	-17.4	-8.4	-3.8	-2.7	-1.3
iv) सूती कपड़े	4.2	8.3	15.6	-12.7	-14.1	-0.2	-11.7	-0.2
v) मनुष्य निर्मित रेशे	4.4	17.4	-0.4	0.6	1.5	-4.1	0.7	-2.3
vi) उर्वरक	3.7	2.1	-0.1	3.3	3.3	0.2	2.2	0.1
vii) लोहा और इस्पात	3.6	9.2	34.6	21.3	19.8	-2.8	15.7	-3.2
viii) सीमेंट	1.7	1.1	1.3	10.2	5.5	7.0	1.6	2.6
ix) गैर बिजली मशीनरी	3.4	2.5	4.7	10.0	11.2	3.6	6.7	2.9
x) बिजली की मशीनरी	5.0	-1.3	1.7	4.1	4.2	1.6	2.6	1.2
xi) परिवहन उपकरण और कल पुर्जे	4.3	-0.9	1.4	6.2	6.2	1.8	4.3	1.6

वचनबद्धता द्वारा मुद्रास्फीतीय प्रत्याशाओं को संतुलित रखना चाहा, किया गया। अंततः, खाद्य स्टॉकों और विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा उपलब्धि आराम ने अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को कायम रखने और स्थिर करने में योगदान दिया। संतुलन में, अंतर्निहित मुद्रास्फीतिकारी दबाव नियंत्रित प्रतीत होते हैं और मुद्रास्फीतीय प्रत्याशाएँ कायम हैं।

2.82 निष्कर्ष के लिए, वाणिज्यिक क्षेत्र से सतत और विस्तृत- आधार पर ऋण की माँग के बावजूद, मौद्रिक और चलनिधि परिस्थितियाँ 2005-06 के दौरान अब तक सुविधाजनक रहीं। ऋण की बढ़ी हुई माँग की वित्त-व्यवस्था करने में, अधिकांशतः सरकारी प्रतिभूतियों में अपने वृद्धिशील निवेशों को सीमित करके, बैंक सक्षम थे। रिजर्व बैंक की निवल विदेशी आस्तियों में निम्नतर क्रम की अभिवृद्धि, सतत ऋण की माँग और

सारणी 2.35 : भारत में उपभोक्ता कीमत मुद्रास्फीति (सी पी आई) (वर्ष-दर-वर्ष)

(प्रतिशत)

मुद्रा स्फीति	मार्च 2003	मार्च 2004	दिसंबर 2004	मार्च 2005	जून 2005	सितंबर 2005	अक्तूबर 2005	दिसंबर 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सीपीआई-आइ डब्ल्यू	4.1	3.5	3.8	4.2	3.3	3.6	4.2	5.6
सीपीआई-यूएनएमई	3.8	3.4	3.6	4.0	3.9	4.8	4.5	5.7
सीपीआई-एएल	4.9	2.5	3.0	2.4	2.7	3.2	3.2	4.7
सीपीआई-आरएल	4.8	2.5	3.0	2.4	2.7	3.2	3.2	4.9
ज्ञापन :								
डब्ल्यू पी आई मुद्रास्फीति (अवधि की समाप्ति)	6.5	4.6	5.7	5.1	4.3	4.3	4.8	4.4
आइ डब्ल्यू : औद्योगिक कामगार। यूएनएमई : शहरी गैर मैन्युअल कर्मचारी। एएल : कृषि श्रमिक। आरएल : ग्रामीण श्रमिक। डब्ल्यू पी आई : थोक मूल्य सूचकांक								

इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट के विमोचन से दिसंबर 2005 में उत्पन्न कुछ दबाव की पृष्ठभूमि में, रिजर्व बैंक ने रेपो परिचालनों के माध्यम के अलावा बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत खजाना बिलों की नीलामियों को रद्द करके चलनिधि उपलब्ध कराई। अधिकतर, ये सभी परिचालन घरेलू वित्तीय बाजारों को स्थिर रखने में सक्षम रहे।

2.83 वर्ष 2004 के उत्तरार्ध से घरेलू मुद्रास्फीति के अलावा मुद्रास्फीति प्रत्याशाएँ भलीभांति नियंत्रित रहीं जो समयबद्ध और नपे तुले मौद्रिक तथा राजकरोषीय उपायों को दर्शाती है। 2005-06 के दौरान मुद्रास्फीति परिस्थितियाँ, भारत और अन्य जगहों दोनों में, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल कीमतों का ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुँचने के द्वारा संचालित थीं। तेल कीमतों के प्रभाव के अंतर्गत, 2005 के उत्तरार्ध में कई अर्थव्यवस्थाओं में हेडलाइन मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी। फिर भी, उच्चतर तेल कीमतों का आर्थिक गतिविधि के अलावा मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर प्रभाव, पूर्ववर्ती तेल आघातों के संबंध में निष्प्रभावी रहा। यद्यपि, हेडलाइन मुद्रास्फीति पर ऊंची तेल कीमतों के दूसरे दौर का प्रभाव अब तक नियंत्रित रहा, ऊंची और अस्थिर तेल कीमतों के संदर्भ में एक उच्चतर डिग्री का दूसरे दौर के प्रभाव की संभावना और उसका मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं के लिए निहितार्थ, केंद्रीय बैंकों की चिंता का कारण बना रहा है।

IV. वित्तीय बाजार

मुद्रा बाजार

2.84 मुद्रा बाजार अल्पावधि निधियों की माँग और आपूर्ति का संतुलन आसानी से निष्पादन करते रहे और अधिकतर बाजार अत्यधिक अस्थिरता के बिना मुक्त रहे। 2005-06 के दौरान मुद्रा बाजार ब्याज अधिकांशतः मौद्रिक नीति के रुझान के तालमेल में चला। चूँकि, मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को स्थिर करने के लिए नपेतुले उपायों के साथ मौद्रिक नीति ने प्रभाव दिखाया, मुद्रा बाजारों के विविध खंडों में ब्याज दरों ने मौद्रिक नीति कार्रवाइयों का प्रत्युत्तर दिया। चलनिधि समायोजन सुविधा (एल ए एफ) और बाजार स्थिरीकरण योजना (एम एस एस) के माध्यम से बाजार परिचालनों ने अधिशेष चलनिधि को पर्याप्त मात्रा में साफ किया और बदलते परिदृश्य के मद्देनजर रिजर्व बैंक, सितंबर 2005 से, अपने प्रगतिशील मूल्यांकन में, निष्क्रिय चलनिधि को, नपेतुले ढंग से मुक्त करने लगा। इससे दिसंबर 2005 में, अमरीकी डॉलर 7.1 बिलियन की आई एम डी देयता के विमोचन के दौरान चलनिधि प्रबंध में सहायता मिली, जब जारी रहे अधिशेष से प्रणाली सीमांत चलनिधि के रूप में निकट तटस्थ स्थिति में संचालित हुई।

2.85 वर्ष 2005-06 के वृहत्तर हिस्से में, मुद्रा बाजार, सुविधाजनक चलनिधि परिस्थितियों से विशिष्ट रहा, औसत दैनिक माँग मुद्रा दरें सामान्यतः रिजर्व रेपो दर से स्थिर रहने के साथ (सारणी 2.36)। माँग मुद्रा दरें लगभग 25 आधार अंकों से बढ़ीं, फिक्स्ड रिजर्व रेपो दर के आगे-पीछे, जिसे अप्रैल 29, 2005 को 25 आधार

अंकों से बढ़ाकर 5.00 प्रतिशत कर दिया गया। जून 2005 के अंत में, माँग दरें रिजर्व रेपो दर से ऊपर बढ़ीं, जो कि, मुख्यतः बैंकों द्वारा रिपोर्टिंग पखवाड़ों की शुरुआत में जरूरत से ज्यादा भंडार रखने की चाह के कारण चलनिधि बेमेलता, बैंकिंग प्रणाली को अग्रिम कर भुगतान और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामी से उत्पन्न दबाव को दर्शाता है। मुंबई में अनवरत वर्षा से सामान्य वित्तीय गतिविधियों में बाधा पड़ने के कारण कुछ अनुसूचित खजाना बिलों की नीलामियों को निरस्त करने से और बैंकिंग प्रणाली को अग्रिम कर भुगतान की वापसी से जुलाई 2005 के उत्तरार्ध में चलनिधि परिस्थितियाँ सुधरीं। जुलाई-अगस्त 2005 के दौरान प्राधिकृत व्यापारियों से प्रचुर मात्रा में विदेशी मुद्रा की खरीद ने भी चलनिधि परिस्थितियों को सुधारा। परिणामतः, औसतन, चलनिधि समायोजन सुविधा रिजर्व रेपो के अंतर्गत शेष जमाराशियों ने, जुलाई में 10,754 करोड़ रुपए से अगस्त 2005 में 34,832 करोड़ रुपए तक छलाँग लगाई। इस तरह, माँग मुद्रा बाजार, अगस्त 2005 और सितंबर 2005 के पूर्वार्ध के दौरान, मोटे तौर पर, स्थिर रहा। सितंबर 2005 के उत्तरार्ध में, माँग मुद्रा बाजार ने हल्का दबाव दर्ज किया जो अग्रिम कर बाहिर्वाह और अनुसूचित नीलामियों को दर्शाता है। अक्टूबर 2005 में, चालू समष्टि आर्थिक और समग्र मौद्रिक परिस्थितियों के मद्देनजर, रिजर्व बैंक ने रिजर्व रेपो दर को 25 आधार अंकों से बढ़ाने का निर्णय लिया, जबकि रिजर्व रेपो दर और रेपो दर के बीच विस्तार को 100 आधार अंकों पर बनाए रखा। तदनुसार, 26 अक्टूबर 2005 से प्रभावी, रिजर्व रेपो और रेपो दर को क्रमशः 5.25 और 6.25 प्रतिशत पर अटल रखा गया। औसत चलनिधि समायोजन सुविधा रिजर्व रेपो स्तरों में गिरावट, सितंबर में 31, 570 करोड़ रुपए से नवंबर में 3,268 करोड़ रुपए, से प्रतिबिंबित अक्टूबर और नवंबर 2005 में अधिशेष चलनिधि में हास से, माँग मुद्रा दरें मजबूत हुईं। प्रगतिशील मूल्यांकन करते हुए, रिजर्व बैंक ने सितंबर 2005 से बाजार स्थिरीकरण योजना को मुक्त करना शुरू किया। इसके अतिरिक्त, दिसंबर 2005 के बाद की छमाही में, अग्रिम कर बाहिर्वाह और इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट विमोचन के दबाव के कारण माँग मुद्रा दरें स्पष्ट रूप से मजबूत हुईं। रिजर्व बैंक द्वारा रेपो खिड़की के अंतर्गत चलनिधि का प्रवाह और बाजार स्थिरीकरण योजना को मुक्त करना, चलनिधि का उचित ढंग से प्रबंध करने में सहायक हुए। दिसंबर और जनवरी 2006 में चलनिधि में तुलनात्मक तंगी के बीच में, एस एल ए एफ के रूप में अतिरिक्त खिड़की ने भी बैंक के लिए विकल्प का विस्तार किया। जनवरी 2006 में, चालू समष्टि आर्थिक और समग्र मौद्रिक परिस्थितियों के दृष्टिकोण से, रिजर्व रेपो और रेपो दरों को 25 आधार अंकों से बढ़ाया गया जबकि दोनों के बीच के विस्तार को 100 आधार अंकों पर बनाए रखा। तदनुसार, जनवरी 24, 2006 से प्रभावी, रिजर्व रेपो और रेपो दरों को क्रमशः 5.50 और 6.50 प्रतिशत पर अटल रखा गया।

सारणी 2.36 : घरेलू वित्तीय बाजार-चयनित संकेतक

वर्ष/ महीना	माँग मुद्रा		सरकारी प्रतिभूतियाँ		विदेशी मुद्रा			चलनिधि प्रबंध			ईक्विटी			
	औसत दैनिक पण्यावर्त (करोड़ रुपए)	औसत माँग मुद्रा दरें * (प्रति शत)	औसत 10-वर्ष आय @ (प्रति शत)	औसत दैनिक पण्यावर्त (करोड़ रुपए) +	औसत दैनिक अंतर-बैंक पण्यावर्त (अमरीकी \$ मिलियन)	औसत दर विदेशी मुद्रा (रुपए प्रति अमरीकी \$)	रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा बिक्री (-)/ खरीद (+) (अमरीकी \$ मिलियन)	औसत वायदा अधि मूल्यता 3- माह (प्रति शत)	औसत एमएसएस बकाया (करोड़ रुपए)	औसत रिवर्स रेपो (एलएएफ) बकाया (करोड़ रुपए)	औसत दैनिक बीएसई पण्यावर्त (करोड़ रुपए)	औसत दैनिक एनएसई पण्यावर्त (करोड़ रुपए)	औसत बीएसई सेनसेक्स **	औसत एस एंड पी सी एन एक्स निफ्टी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2004-05														
अप्रैल	12,916	4.29	5.10	10,029	10,302	43.93	7,427	-0.36	14,296	75,006	2,243	5,048	5,809	1,848
मई	10,987	4.30	5.19	6,202	8,882	45.25	-220	-1.33	27,518	74,502	2,188	4,710	5,205	1,640
जून	10,973	4.35	5.50	5,860	7,847	45.51	-413	0.93	35,283	61,981	1,681	3,859	4,824	1,506
जुलाई	8,632	4.31	5.91	4,206	7,756	46.04	-1,180	2.25	43,739	59,594	1,793	4,265	4,973	1,568
अगस्त	11,562	4.41	6.38	4,173	5,974	46.34	-876	2.85	48,541	42,692	1,736	3,948	5,144	1,615
सितंबर	17,088	4.45	6.08	5,854	7,348	46.10	19	2.20	52,421	31,589	1,800	4,023	5,423	1,692
अक्टूबर	16,667	4.63	6.73	3,636	7,262	45.78	-99	2.87	53,660	10,805	1,730	3,785	5,702	1,795
नवंबर	13,820	5.62	7.14	2,607	9,929	45.13	3,792	2.16	54,157	-5,066	1,787	4,102	5,961	1,874
दिसंबर	19,527	5.28	6.73	4,305	9,447	43.98	1,393	2.03	52,085	7,570	2,184	5,026	6,394	2,022
जनवरी	16,534	4.72	6.68	3,566	9,114	43.75	0	2.50	53,790	18,721	2,310	5,249	6,307	1,978
फरवरी	16,041	4.76	6.58	4,640	11,583	43.68	4,974	1.99	58,141	19,895	2,484	4,999	6,595	2,067
मार्च	15,293	4.72	6.65	2,835	11,286	43.69	6,030	1.82	63,737	29,809	2,706	5,139	6,679	2,096
2005-06														
अप्रैल	17,213	4.77	7.02	3,001	9,880	43.74	0	1.96	65,638	30,675	1,890	4,136	6,379	1,987
मई	15,269	4.99	7.13	3,805	10,083	43.49	0	1.57	68,539	22,754	1,971	3,946	6,483	2,002
जून	20,134	5.10	6.88	6,807	10,871	43.58	-104	1.40	70,651	13,916	2,543	4,843	6,926	2,134
जुलाई	20,046	5.02	7.12	3,698	11,003	43.54	2,473	1.56	70,758	10,754	3,095	6,150	7,337	2,237
अगस्त	16,158	5.02	7.04	4,239	11,749	43.62	1,552	0.69	71,346	34,832	3,451	6,624	7,726	2,358
सितंबर	16,292	5.05	7.04	5,207	11,040	43.92	0	0.62	67,617	31,570	3,871	6,923	8,272	2,512
अक्टूबर	17,169	5.12	7.14	2,815	13,087 P	44.82	0	0.69	68,602	18,608	2,955	6,040	8,220	2,487
नवंबर	22,620	5.79	7.10	3,314	11,228 P	45.73	0	0.67	67,041	3,268	2,635	5,479	8,552	2,575
दिसंबर	21,149	6.00	7.13	2,948	13,632 P	45.64	6,541	1.51	52,040	1,452	3,516	6,814	9,162	2,773
जनवरी	17,911	6.79	7.16	3,094	16,365 P	44.40	..	2.60	40,219	-15,386	3,966	7,472	9,540	2,893
फरवरी	13,497	6.87	7.32	2,584	..	44.33	..	2.85	33,405	-13,532	3,688	7,125	10,090	3,019
.. नहीं उपलब्ध। * दैनिक भारत माँग मुद्रा उधार दरों का औसत। + केंद्रीय सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का एकमुश्त पण्यावर्त। # साप्ताहिक बकाया बाजार स्थिरीकरण योजना का औसत। ** दैनिक लेखा बंदी सूचकांक का औसत। @ दैनिक लेखा बंदी दरों का औसत। पी: अनंतिम।														

2.86 मध्यावधि उद्देश्य के साथ मौद्रिक नीति रुझान को बनाए रखते हुए, इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट विमोचन के होते हुए, असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए चलनिधि प्रबंध कार्यान्वित किया गया। विमोचन के कारण बहिर्वाह को इस संबंध में आसान व्यवस्थाओं द्वारा पूरा किया गया। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आई एम डी के विमोचन से मेल खाते हुए लगभग 23,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन के औसत से, रेपो खिड़की (दूसरे एल ए एफ को मिलाकर) के माध्यम से। चलनिधि मुक्त करके, अग्रिम कर भुगतानों के कारण बहिर्वाह और ऋण के उठाव में जारी प्रवाह द्वारा चलनिधि में अस्थायी तंगी को, पूरा किया गया। जनवरी 2006 के प्रथम सप्ताह में अल्प-कालिक मुद्रा बाजार दरें आई एम डी के आसान विमोचन को प्रतिबिंबित करते हुए, असाधारण रूप से सामान्य हुई जो वित्तीय बाजारों की बढ़ती हुई परिपक्वता को और चलनिधि प्रबंध प्रणाली, जिसे व्यवस्था में लगाया गया है, के सामर्थ्य को दर्शाते हैं। माँग मुद्रा दरें, हालाँकि, पुनः जनवरी 2006 के दूसरे सप्ताह से मजबूत हुई, जो सरकारी प्रतिभूतियों की अनुसूचित नीलामियों से उत्पन्न माँग दबावों और मजबूत ऋण माँग को दर्शाते हैं।

2.87 वार्षिक नीति वक्तव्य (जनवरी 24, 2006) की तीसरी तिमाही समीक्षा में रिजर्व बैंक ने अपनी सक्रिय माँग प्रबंध की नीति को, खुला बाजार परिचालन समेत बाजार स्थिरीकरण योजना, चलनिधि समायोजन सुविधा और नकदी आरक्षित अनुपात और अपने अधिकार में सभी नीति यंत्रों का, स्थिति की माँग के अनुसार, लोचपूर्ण ढंग से उपयोग, के माध्यम से जारी रखा। समष्टि आर्थिक गतिविधियों के सूचित मूल्यांकन पर आधारित, विकास और मुद्रास्फीति के बारे में प्रगतिशील ढंग के दृष्टिकोण समेत और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किसी प्रतिकूल और अप्रत्याशित गतिविधियों के उन्मज्जन को छोड़कर, मूल्य स्थायित्व पर जोर को कायम रखने के उद्देश्य से मुद्रास्फीतीय प्रत्याशाओं को स्थिर रखने के लिए, समष्टि आर्थिक, कीमत और वित्तीय स्थायित्व के लिए एक सहायक ब्याज दर माहौल सुनिश्चित कर के, बैंक दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया। यद्यपि, रिजर्व बैंक, नकदी आरक्षित अनुपात को 3.0 प्रतिशत के सांविधिक न्यूनतम स्तर तक कम करने के अपने मध्यम-अवधि उद्देश्य को लगातार जारी रखता है, चालू चलनिधि स्थिति की समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया कि नकदी आरक्षित अनुपात का 5.0 प्रतिशत पर वर्तमान स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा।

सारणी 2.37 : मुद्रा बाजारों में ब्याज दरें

(प्रतिशत)

	मार्च-2002	मार्च-2003	मार्च-2004	मार्च-2005	सितंबर-2005	दिसंबर-2005	जनवरी-2006
1	2	3	4	5	6	7	8
माँग मुद्रा	6.97	5.86	4.37	4.72	5.05	6.00	6.79
वाणिज्यिक पत्र (61-90 दिन)	7.78	6.53	5.11	5.84	5.87	6.70	7.29
जमा प्रमाणपत्र	5.00-10.03	5.00-7.10	3.87-5.16	4.21-6.34	4.66-7.00	5.50-7.25	5.40-7.75

ब्याज दर परिदृश्य

2.88 निधियों की माँग और आपूर्ति में साथ-साथ वृद्धि का परिणाम ब्याज दरों का सामान्यतः 2004-05 के दौरान और अब तक चालू वर्ष में, स्थिर रहने में हुआ। इस अवधि के दौरान, ब्याज दर वातावरण, चलनिधि की पर्याप्त आपूर्ति के कारण, सुसाध्य रहा, यद्यपि, उद्योगों के अलावा अन्य क्षेत्रों से ऋण की माँग तेजी से बढ़ी। जमाराशियों पर प्रस्तावित ब्याज दरों का परास, इस अवधि के दौरान, विस्तृत हुआ। वर्ष के दौरान उप-बेंचमार्क मूल उधार दर (सब-पीएलआर) ऋण का हिस्सा बढ़ा। तथापि, उप-बेंचमार्क मूल उधार दर ऋण दरों में, बाद में सख्ती होने के बावजूद, चालू वर्ष के दौरान दिसंबर तक, ऋण दरों में कुछ नरमी दर्ज की गई।

2.89 2004-05 के दौरान, वित्तीय बाजार सामान्यतः स्थिर रहे, यद्यपि ब्याज दरों ने वर्ष-भीतर कुछ ऊर्ध्वमुखी गति दिखाई। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक ब्याज दरों में उसी प्रकार की प्रवृत्तियाँ जारी रहीं। बाजार के लघु सिरे पर, भारित औसत माँग मुद्रा दर 35 आधार अंकों से बढ़ी, मार्च 2004 में 4.37 प्रतिशत से मार्च 2005 तक 4.72 प्रतिशत और आगे फरवरी 2006 में 6.87 प्रतिशत तक। 61 से 90-दिवसीय परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्र (सी पी) पर भारित औसत

छूट दर 73 आधार अंकों से बढ़ी, मार्च 2005 तक 5.11 प्रतिशत से 5.84 प्रतिशत, सितंबर 2005 में लगभग उसी स्तर पर रही, दिसंबर 2005 में 6.70 प्रतिशत तक बढ़ी और आगे जनवरी 2006 में 7.29 प्रतिशत तक बढ़ी (सारणी 2.37)।

बैंक जमाराशि और ऋण दरें

2.90 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रस्तावित मीयादी-जमाराशि दरें एक वर्ष तक की परिपक्वता के लिए, मार्च 2004 में 3.75-5.25 प्रतिशत से मार्च 2005 में 2.75-6.0 प्रतिशत और आगे फरवरी 2006 में 2.25-6.00 प्रतिशत के परास में चलीं। एक वर्ष के ऊपर की मीयादी-जमाराशियों पर ब्याज दरें, मार्च 2004 में 5.00-6.00 प्रतिशत से मार्च 2005 में 4.75-7.00 प्रतिशत और आगे फरवरी 2006 में 5.50-7.00 प्रतिशत के परास में चलीं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बेंचमार्क मूल उधार दरें (बीपीएलआर) मार्च 2004 में 10.25-11.25 प्रतिशत से मार्च 2005 में 10.25-11.50 प्रतिशत के परास में चलीं और फरवरी 2006 में उसी पर रहीं। विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों की बीपीएलआर, क्रमशः मार्च 2004 में 11.00-14.85 प्रतिशत और 10.50-13.00 प्रतिशत से मार्च 2005 में 10.00-14.50 प्रतिशत और 11.00-13.50 प्रतिशत के परास में चलीं (सारणी 2.38)। फरवरी 2006 में निजी और विदेशी

सारणी 2.38 : जमाराशि और ऋण ब्याज दरों की गति

(प्रतिशत)

ब्याज दरें	मार्च 2002	मार्च 2003	मार्च 2004	मार्च 2005	दिसंबर 2005	फरवरी 2006*
1	2	3	4	5	6	7
मीयादी जमाराशि दरें						
सरकारी क्षेत्र के बैंक						
क) 1 वर्ष तक	4.25 - 7.50	4.00 - 6.00	3.75 - 5.25	2.75 - 6.00	2.00 - 6.00	2.25 - 6.00
ख) 1 वर्ष से ऊपर 3 वर्ष तक	7.25 - 8.50	5.25 - 6.75	5.00 - 6.00	4.75 - 6.50	5.50 - 6.50	5.50 - 6.50
ग) 3 वर्ष से अधिक	8.00 - 8.75	5.50 - 7.00	5.75 - 6.00	5.25 - 7.00	5.80 - 7.00	5.80 - 7.00
निजी क्षेत्र के बैंक						
क) 1 वर्ष तक	5.00 - 9.00	3.50 - 7.50	3.50 - 7.50	3.00 - 6.25	3.00 - 6.25	3.00 - 6.25
ख) 1 वर्ष से ऊपर 3 वर्ष तक	8.00 - 9.50	6.00 - 8.00	5.75 - 7.75	5.25 - 7.25	5.50 - 7.00	5.50 - 7.00
ग) 3 वर्ष से अधिक	8.25 - 10.0	6.00 - 8.00	6.00 - 8.00	5.75 - 7.00	6.00 - 7.25	6.00 - 7.25
विदेशी बैंक						
क) 1 वर्ष तक	4.25 - 9.75	3.00 - 7.75	3.00 - 7.75	3.00 - 6.25	3.00 - 5.75	3.00 - 5.75
ख) 1 वर्ष से ऊपर 3 वर्ष तक	6.25 - 10.0	4.15 - 8.00	3.50 - 8.00	3.50 - 6.50	4.25 - 6.00	4.25 - 6.00
ग) 3 वर्ष से अधिक	6.25 - 10.0	5.00 - 9.00	4.75 - 8.00	3.50 - 7.00	5.00 - 7.00	5.00 - 7.00
बीपीएलआर						
सरकारी बैंक	10.00 - 12.50	9.00 - 12.25	10.25 - 11.50	10.25 - 11.25	10.25 - 11.25	10.25 - 11.25
निजी क्षेत्र के बैंक	10.00 - 15.50	7.00 - 15.50	10.50 - 13.00	11.00 - 13.50	11.00 - 13.50	11.00 - 13.50
विदेशी बैंक	9.00 - 17.50	6.75 - 17.50	11.00 - 14.85	10.00 - 14.50	10.00 - 14.50	10.00 - 14.50

* 3, फरवरी 2006 को।

बैंकों के लिए बीपीएलआर के परास अपरिवर्तित रहे। वर्ष 2004-05 के दौरान, ऋण बाजार में स्पर्धात्मक परिस्थितियों से, बैंकों के ऋण का एक बड़ा हिस्सा उप-बीपीएलआर दरों पर था। उप-बीपीएलआर ऋण का हिस्सा, वाणिज्यिक बैंकों के कुल ऋण में, 2 लाख रूपए से अधिक ऋण सीमा के साथ, निर्यात ऋण को छोड़कर, मार्च 2004 में लगभग 50 प्रतिशत से मार्च 2005 में 60 प्रतिशत से ऊपर बढ़ा, जो कि दिसंबर 2005 में भी कायम रहा। दिसंबर 2005 की समालप्त पर, सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के माध्य (प्रतिनिधि) ऋण दर ने, दोनों माँग और मीयादी ऋणों (जिस पर अधिकतम कारोबार अनुबंधित हो) के लिए, 8.00-11.63 प्रतिशत के परास में, मार्च 2005 में उनके तदनुरूपी स्तरों, 9.00-12.50 और 8.38 -12.00 प्रतिशत प्रत्येक की तुलना में, नरमी दर्शाई। इस प्रकार, नवंबर 2003 की मध्यावधि समीक्षा में ऋण दरों की अधोमुखी गति में अवलोकित दृढ़ता के संबंध में व्यक्त चिंता को ध्यान में रखते हुए, ऋण दरों की गति अपेक्षित दिशा में थी।

निर्यात ऋण पर ब्याज दर

2.91 अप्रैल 2002 में, मौद्रिक एवं ऋण नीति वक्तव्य ने संकेत दिया कि निर्यात ऋण पर घरेलू ब्याज दरों को, वर्तमान परिस्थितियों में, मूल उधार दर (पीएलआर) से जोड़ना अनावश्यक हो गया है क्योंकि रूपए के अनुसार निर्यात ऋण पर प्रभावी ब्याज दरें पर्याप्त मात्रा में पीएलआर से निम्नतर थीं। अक्टूबर 29, 2002 को घोषित मध्यावधि समीक्षा में, रिजर्व बैंक ने संकेत दिया कि पीएलआर-जुड़ी सीमा दर ने, बैंकों को विश्वसनीय कर्जदारों को उप-मूल उधार दरों पर ऋण देने की स्वतंत्रता देने के कारण, अपना महत्त्व खो दिया है। निर्यातक, मूल कर्जदार होने के कारण, सामान्यतया उप-मूल उधार दर पर निर्यात ऋण ले सकेंगे। इसलिए, बैंकों में स्पर्धा को प्रोत्साहन देने के दृष्टिकोण से और निर्यात क्षेत्र में ऋण-प्रवाह की वृद्धि के लिए भी, रिजर्व बैंक ने रूपए के अनुसार निर्यात ऋण पर ब्याज दरों को उदार बनाया। 180 दिनों से परे और 270 दिनों तक पूर्व-पोत लदान ऋण और 180 दिनों से परे और 270 दिनों तक पोतलदानोत्तर ऋण पर पीएलआर और 0.5 प्रतिशत अंकों की सीमा दर को प्रभावी मई 1, 2003 से अविनियमित किया गया। इससे अधिक उदारीकरण पर बाद की तारीख में विचार किया जाएगा और यह परीक्षण किया जाएगा कि क्या 180 दिनों तक के पूर्व-पोत लदान ऋण और 90 दिनों तक के पोतलदानोत्तर ऋण पर के सीमा दरों को भी, बैंकों के बीच निर्यात ऋण के लिए अधिक स्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए, अविनियमित किया जाए। पूर्व-पोत लदान (180 दिनों तक) और पोतलदानोत्तर (90 दिनों तक) रूपए में निर्यात ऋण पर ब्याज की वर्तमान सीमा अप्रैल 30, 2006 तक वैध है। पीसीएफसी (विदेशी मुद्रा में पोतलदानोत्तर ऋण) पर सीमा दर, लिबोर +75 आधार अंकों से अनुरूपी मुद्राओं के लिए, अपरिवर्तित रही।

माँग मुद्रा बाजार : प्रमुख प्रवृत्तियाँ

2.92 वर्ष 2004-05 के दौरान मुद्रा बाजार में एक दिलचस्प घटनाक्रम था संपार्श्वीकृत खंड के तुलनीय आकार का असंपार्श्वीकृत खंड के मुकाबले बढ़ना। बाजार रेपो और संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता (सीबीएलओ) का संयुक्त औसत दैनिक लेनदेन उनसे, जो असंपार्श्वीकृत माँग/नोटिस मुद्रा बाजार में थे, अनुपातिक उच्चतर था। यह ध्यान रखा जाए कि, प्राथमिक व्यापारियों के सिवाय गैर बैंक सहभागियों को माँग/नोटिस मुद्रा बाजार से चरणबद्ध बाहर करने के बाद, बीमा कंपनियों और म्युचुअल फंडों से संस्थागत निधियों की आपूर्ति, संपार्श्वीकृत बाजार में अंतरित हुई, जो सामान्यतः माँग मुद्रा बाजार से निम्नतर दर पर निधियाँ भी उपलब्ध कराते हैं। माँग/नोटिस मुद्रा पण्यावर्त, अगस्त 2004-दिसंबर 2005 के दौरान व्यापक रूप से बढ़ा, परंतु उसके बाद घट गया।

संबंधित बाजार शेयर

2.93 इस बाजार में विभिन्न घटकों के तुलनात्मक हिस्से उल्लेखनीय रूप से परिवर्तित हुए हैं (सारणी 2.39)। अर्थव्यवस्था में चलनिधि की अधिकता के फलस्वरूप उधार लेने की जरूरत में कुल मिलाकर कमी, नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को पर्याप्त मात्रा में घटाना, और सामान्यतः, मुद्रा बाजार खंडों अर्थात् माँग मुद्रा बाजार, रेपो और सीबीएलओ के मुकाबले उच्चतर रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो दर के कारण माँग मुद्रा बाजार से लिए हुए उधार में बैंकों का हिस्सा धीरे-धीरे वर्षों में 2003-04 तक घटा। इस स्थिति का एक प्रत्यक्ष परिणाम, रिजर्व बैंक के रिवर्स रेपो खिड़की में उच्चतर निधियों के नियोजन से हुआ। माँग मुद्रा बाजार में घटते हुए पण्यावर्त के परिदृश्य में, प्राथमिक व्यापारी, जिसकी माँग बाजार उधार कार्यक्रम के परिमाण से संचालित थी, 2003-04 में सबसे बड़े उधारकर्ता समूह के रूप में उभरा।

सारणी 2.39 : माँग / नोटिस मुद्रा बाजार में तुलनात्मक हिस्से

(प्रतिशत)

वर्ष	उधार लेना		ऋण देना		
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	गैर-बैंक
1	2	3	4	5	6
2000-01	67	33	47	12	41
2001-02	62	38	65	10	25
2002-03	53	47	69	2	29
2003-04	36	64	57	2	41
2004-05	65	35	70	1	29
2005-06*	76	24	95	1	4

* फरवरी 2006 तक .

2.94 तथापि, ऋण माँग में वृद्धि, सीआरआर के रख रखाव में 50 आधार अंकों से, दो चरणों सितंबर और अक्टूबर 2004 में बढ़त और सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम में कटौती जिसके बाद प्राथमिक व्यापारियों द्वारा उधार राशियाँ कम हुईं, के कारण 2004-05 के दौरान स्थिति बदली और बैंक एकबारगी पुनःसबसे बड़े उधारकर्ता समूह के रूप में उभरे।

2.95 ऋण देने की तरफ, गैर बैंक इकाइयों का हिस्सा, माँग / नोटिस बाजार से उनके चरणबद्ध बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, 2001-02 और 2002-03 के दौरान कम हुआ। उसके बाद, 2003-04 के दौरान, माँग मुद्रा बाजार के कुल पण्यावर्त में स्पष्ट संकुचन की पृष्ठभूमि में, उनका हिस्सा तुलनात्मक आधार पर बढ़ा। सितंबर 2004 से, बैंकिंग क्षेत्र का हिस्सा बढ़ रहा है, और अगस्त 2005 से गैर बैंकों को चरणबद्ध बाहर करने के बाद केवल बैंक और प्राथमिक व्यापारी माँग मुद्रा बाजार में रह गए हैं।

नीति गतिविधियाँ

2.96 एनडीएस (तयशुदा लेनदेन प्रणाली) / सीसीआईएल (भारतीय समाशोधन निगम लि.) के कार्य में उत्साहवर्धक गतिविधियों के कारण, रेपो/मीयादी मुद्रा बाजार को और गहन बनाने को सुसाध्य करने के लिए शुद्ध अंतर-बैंक माँग मुद्रा /नोटिस मुद्रा बाजार की ओर चलने की प्रक्रिया त्वरित हुई। तदनुसार, प्रभावी जून 26, 2004 से शुरू पखवाड़े से, रिपोर्टिंग पखवाड़े में एक औसत में, 2000-01 के दौरान माँग/नोटिस मुद्रा बाजार में उनके औसत दैनिक ऋण देने के पिछले 60 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक गैर बैंक सहभागियों को उधार देने की अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त, प्रभावी जनवरी 8, 2005 से शुरू पखवाड़े से, इस सीमा को घटाकर, 2000-01 में माँग/नोटिस मुद्रा बाजार में उनके औसत दैनिक ऋण देने का 30 प्रतिशत कर दिया गया। उसके बाद, प्रभावी जून 11, 2005 से शुरू पखवाड़े से गैर बैंक सहभागियों को, रिपोर्टिंग पखवाड़े में एक औसत में, उनके 2000-01 के दौरान माँग/नोटिस मुद्रा बाजार में औसत दैनिक ऋण का 10 प्रतिशत तक उधार देने की अनुमति दी गई और उसके बाद प्रभावी अगस्त 6, 2005 से, गैर बैंक सहभागियों को, प्राथमिक व्यापारियों के सिवाय, माँग /नोटिस मुद्रा बाजार से पूर्णतः चरणबद्ध बाहर कर दिया गया।

2.97 इसके अतिरिक्त, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मामले में, माँग/नोटिस मुद्रा बाजार के एक्सपोजर पर विवेकपूर्ण सीमाओं को निर्धारित करने के लिए बेंचमार्क को अब उनकी पूंजी निधियों (टियर I और टियर II पूंजी का योग) से, अप्रैल 30, 2005 से शुरू के पखवाड़े से, जोड़ दिया गया है। पारदर्शिता में सुधार लाने के दृष्टिकोण से, वार्षिक नीति वक्तव्य 2005-06 में माँग /नोटिस और मीयादी मुद्रा लेनदेन के लिए एक स्क्रीन-आधारित तयशुदा उद्धरण-संचालित प्रणाली का प्रस्ताव किया गया।

2.98 चलनिधि प्रबंध के और अधिक उत्तम-तालमेल के लिए, बाजार सहभागियों को दूसरे चलनिधि समायोजन सुविधा (एसएलएएफ) के रूप

में एक अतिरिक्त खिड़की उपलब्ध कराई गई है जो नवंबर 28, 2005 से, बाजार सहभागियों के सुझाव के प्रतिसाद में, चालू है। एसएलएएफ सभी कार्यदिवसों को, सिवाय शनिवार के, संचालित होता है और एसएलएएफ के लिए बोलियाँ सायंकाल 3.00 और 3.45 के बीच प्राप्त होती हैं। एसएलएएफ के प्रमुख लक्षण वही हैं जैसे की एलएएफ के। तथापि, एलएएफ और एसएलएएफ का निपटान अलग-अलग और सकल आधार पर किया जाता है। अनुभव पर आधारित, जरूरत पड़ने पर एसएलएएफ समीक्षा और संशोधन का विषय है।

जमा प्रमाणपत्र (सी डी)

2.99 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) की बकाया राशि सुस्पष्ट रूप से मार्च 2004 में 4,461 करोड़ रुपए से मार्च 2005 में 12,078 करोड़ रुपए तक बढ़ी। सीडी पर विशिष्ट छूट दर (3-माह परिपक्वता के लिए) मार्च 2004 में 4.96 प्रतिशत से मार्च 2005 में 5.90 प्रतिशत से बढ़ी। मार्च 18, 2005 को कुल बकाया सीडी, सीडी जारी करने वाले बैंकों की समुच्चय बैंक जमाराशियों का 3.9 प्रतिशत बना। 2005-06 के दौरान अब तक, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी सीडी की बकाया राशि और बढ़ी, अप्रैल 2005 में 14,975 करोड़ रुपए से जनवरी 2006 में 34,521 करोड़ रुपए, और सीडी पर विशिष्ट छूट दर (3-माह परिपक्वता के लिए) 5.87 प्रतिशत से 7.21 प्रतिशत तक बढ़ी। प्रणाली स्तर पर, कुल बकाया सीडी, सीडी जारी करने वाले बैंकों की समग्र बैंक जमाराशियों का, जनवरी 20, 2006 को, 3.1 प्रतिशत हुआ।

2.100 जारी करने वाले छोटे समूह, सुगम चलनिधि के वातावरण में, जब बैंक सामान्यतः सीडी जारी नहीं करते, दर्शाते हैं कि यह बैंक-विशिष्ट घटक है, जो हाल की अवधि में सीडी के विकास का संचालन कर रहे हैं। इस संदर्भ में यह पाया गया है कि, चुनिंदा विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंक, केवल कम शाखाओं के कारण ही नहीं बल्कि उनके लागत-प्रभाव के कारण भी, सीडी जारी करने के माध्यम से संसाधन एकत्र कर रहे हैं। फिर भी, सीडी का नियमित जारी करना बहुत से समष्टि घटकों के कारण है, जिसमें बैंकों द्वारा गैर एसएलआर (सांविधिक चलनिधि अनुपात) ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के बारे में रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित दिशानिदेश, प्रभावी मार्च 1, 2004 से सीडी पर स्टैंप शुल्क में कटौती, स्रोत पर कर कटौती नहीं, पूर्व अदायगी या अपरिपक्व समापन नहीं जैसा कि मीयादी जमाराशियों के मामले में होता है और द्वितीयक बाजार ट्रेडिंग के लिए बृहत्तर अवसर, शामिल हैं। माँग की तरफ, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) का म्युचुअल फंडों (एमएफ) पर बैंक जमाराशियों में निधियों को रोकने पर अंकुश के साथ म्युचुअल फंडों में निधियों की सुधरी हुई स्थिति ने जमा प्रमाणपत्र बाजार को आवेग दिया। एक प्रोत्साहित घटनाक्रम जो घटा वह था कुछ उच्च-मूल्यांकित बैंकों द्वारा अपनी सीडी को, बाजार की बेहतर

पहुँच के लिए, मुल्यांकित करवाना हालाँकि ऐसा मूल्यांकन वर्तमान दिशानिदेश के अंतर्गत अनिवार्य नहीं है।

नीति गतिविधियाँ

2.101 मीयादी जमाराशियों और वाणिज्यिक पत्रों के लिए न्यूनतम अवधि की कटौती को ध्यान में रखते हुए, सीडी की न्यूनतम परिपक्वता अवधि, प्रभावी अप्रैल 28, 2005 से, 15 दिनों से घटाकर 7 दिनों की कर दी गई थी। इसने बैंकों को, सीडी के माध्यम से अल्प-कालिक संसाधन एकत्र करने का एक अतिरिक्त विकल्प दिया।

वाणिज्यिक पत्र (सीपी)

2.102 2004-05 के दौरान वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) के लिए बाजार उत्साहजनक बना रहा। सीपी की बकाया राशि मार्च 2004 में 9, 131 करोड़ रुपए से मार्च 2005 में 14, 235 करोड़ रुपए बढ़ी। इस अवधि के दौरान सीपी पर छूट परास, 4.70-6.50 प्रतिशत के परास से 5.20-7.25 प्रतिशत तक चली और भारित औसत छूट दर (डब्ल्यू ए डी आर) 5.11 प्रतिशत से 5.84 प्रतिशत तक ऊपर ऊठी। सीपी की वरीयता प्राप्त परिपक्वता “ 61 से 90 दिनों” और “181 दिनों और अधिक” परास अवधियों की रही।

2.103 जारी करने वालों के प्रकार के संबंध में यह पाया गया कि, कालावधि में विनिर्माण कंपनियों द्वारा जारी सीपी में दीर्घ गिरावट हुई। इस प्रवृत्ति को दर्शाते हुए, 2004-05 के दौरान विनिर्माण और अन्य कंपनियों का हिस्सा सीपी की समग्र राशि में 31 प्रतिशत रहा (2003-04 के दौरान 44 प्रतिशत)। दूसरी ओर, वित्त / लीजिंग कंपनियों ने 56 प्रतिशत का हिस्सा रखा (2003-04 के दौरान 38 प्रतिशत) और वित्तीय संस्थाओं ने 13 प्रतिशत का हिस्सा रखा (2003-04 के दौरान 18 प्रतिशत)।

2.104 2005-06 के दौरान सीपी के लिए बाजार उत्साहजनक बना रहा। सीपी की बकाया राशि अप्रैल 2005 में 15,598 करोड़ रुपए से फरवरी 15, 2006 में 16,173 करोड़ रुपए बढ़ी। इस अवधि के दौरान सीपी पर छूट परास, 5.50-6.65 प्रतिशत के परास से 7.03-8.50 प्रतिशत तक चली। इस अवधि के दौरान भारित औसत छूट दर (डब्ल्यू ए डी आर) 5.84 प्रतिशत से 7.87 प्रतिशत तक बढ़ी। सीपी की वरीयता प्राप्त परिपक्वता “61 से 90 दिनों”, “91 से 180 दिनों” और “181 दिनों और अधिक” परास अवधियों की रही।

2.105 जारी करने वालों के प्रकार के संबंध में, विनिर्माण और अन्य कंपनियों का हिस्सा सीपी द्वारा एकत्रित समग्र राशि का 19.1 प्रतिशत रहा जबकि वित्त / लीजिंग कंपनियों ने, 2005-06 के दौरान फरवरी 15, 2006 तक, 80.9 प्रतिशत का हिस्सा लिया।

2.106 बैंकों द्वारा गैर एसएलआर ऋण प्रतिभूतियों में निवेश पर रिजर्व बैंक के दिशानिदेश के कारण म्युचुअल फंडों से बड़े निवेश की रुचि के बाद,

इस अवधि के दौरान सीपी का जारी करना बढ़ा। इसके अतिरिक्त, प्रभावी मार्च 1, 2004 से सीपी पर स्टैप शुल्क में कटौती भी उसके जारी करने में तेजी लाई। यद्यपि, सीपी बाजार प्रथम-वर्ग प्रधान-मूल्यांकित किए गए जारीकर्ताओं (अर्थात्, क्राईसिल या समतुल्य का P1 + और उससे ऊपर) से अत्यधिक प्रभावित रहा, यह पाया गया कि सीपी जारी करने में उनका हिस्सा, 2002-03 के दौरान 91.9 प्रतिशत से 2004-05 में 88.2 प्रतिशत तक घटा। तदनुसूची, इस अवधि में माध्यम-मूल्यांकित किए गए जारीकर्ताओं का 8.1 प्रतिशत से 11.8 प्रतिशत तक बढ़ा।

2.107 यद्यपि कंपनियों को, जिनकी निवल मालियत 4 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, सीपी के माध्यम से अल्प-अवधि संसाधन उगाहने की अनुमति है, यह देखा गया है कि 2005-06 के दौरान (अप्रैल-फरवरी 15, 2006) लगभग 92 प्रतिशत सीपी उन कंपनियों द्वारा जारी की गई कि जिनकी निवल मालियत 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है।

नीति संबंधी गतिविधियाँ

2.108 सीपी बाजार को और विकसित करने के लिए, एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया और सीपी जारी करने को तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) प्लेटफार्म पर, जारीकर्ता और भुगतानकर्ता एजेंटों (आईपीए) द्वारा अप्रैल 16, 2005 के प्रभाव से रिपोर्ट करने के लिए लागू किया गया। इसके अतिरिक्त, सीपी जारी करने के बारे में सूचना, जैसे, जारी करने की तारीख, परिपक्वता तारीख, जारी राशि, छूट / ब्याज दर, बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी और गारंटीकर्ता की साख दर, जैसा आईपीए द्वारा एनडीएस प्लेटफार्म पर सूचित हो, को जुलाई 1, 2005 के प्रभाव से रिजर्व बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध किया गया है।

वायदा दर करार (एफआरए) / ब्याज दर स्वैप (आइआरएस)

2.109 वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान एफआरए/ आइआरएस बाजार में मात्रा में तीव्र वृद्धि हुई। एफआरए/आइआरएस लेनदेन, संविदाओं की संख्याएँ तथा बकाया काल्पनिक मूलधन दोनों के अनुसार, बढ़ा, अप्रैल 2004 में 3,72,896 करोड़ रुपए की 13,960 संविदाओं से मार्च 2005 में 10,62,242 करोड़ रुपए की 37,864 संविदाएँ। 2005-06 के दौरान अब तक, संविदाओं की संख्याएँ तथा बकाया काल्पनिक मूलधन बढ़ा, अप्रैल 2005 में 10,76,513 करोड़ रुपए की 38,386 संविदाओं से अक्टूबर 2005 के पहले पखवाड़े में 13,42,335 करोड़ रुपए की 37,864 संविदाएँ।

2.110 इस संदर्भ में, डेरिवेटिव्स संविदाओं की कानूनी अस्पष्टता को दूर करने के लिए यथोचित कानूनी ढाँचे की जरूरत है। रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को यथोचित वैधानिक परिवर्तनों के लिए सुझाव किया है। 2005-06 के केंद्रीय बजट ने भी, ओवर द काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव्स संविदाओं की कानूनी अस्पष्टता को दूर करने का प्रस्ताव किया है।

संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता (सीबीएलओ)

2.111 मार्च 2005 तक, 110 सदस्यों को भारतीय समाशोधन निगम लि.(सीसीआइएल) के सीबीएलओ खंड में प्रवेश दिया गया, जिसमें से 56 सक्रिय सदस्य थे। पिछले दो वर्षों में बाजार ने पर्याप्त विकास किया। सीबीएलओ में दैनिक औसत पण्यावर्त अप्रैल 2004 में 2,496 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2005 में 9, 625 करोड़ रुपए हुआ। फरवरी 2006 तक, 150 सदस्यों को सीसीआइएल के सीबीएलओ खंड में प्रवेश दिया गया, जिसमें से 78 सक्रिय सदस्य थे। सीबीएलओ में दैनिक औसत पण्यावर्त अप्रैल 2005 में 10,369 करोड़ रुपए से बढ़कर फरवरी 2006 में 34,162 करोड़ रुपए हुआ। म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियाँ, सीबीएलओ खंड में निधियों की सबसे बड़ी संभरक हैं जबकि माँग की तरफ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक और प्राथमिक व्यापारी निधियों के प्रमुख उधारकर्ता हैं।

स्थायी चलनिधि सुविधा

2.112 निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा अब बैंकों के पात्र बकाया रुपए में निर्यात ऋण, दोनो पूर्व-पोतलदान और पोतलदानोत्तर चरणों के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। प्रभावी अप्रैल 1, 2002, अनुसूचित बैंकों को बकाया निर्यात ऋण का 15 प्रतिशत तक, जो दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत में पुनर्वित्त के लिए पात्र हो, ईसीआर सुविधा दी जा रही है। मार्च 29, 2004 के प्रभाव से सामान्य सुविधा (बैंक दर से जुड़े दर पर) और बैंक-स्टॉप सुविधा एलएएफ परिचालनों अथवा राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई)-मुंबई अंतर बैंक प्रस्तावित दर (एमआइबीओआर) से जुड़े दर का विलय कर दिया गया और तदनुसार, ईसीआर एकल दर से, रिजर्व बैंक के रेपो दर से, दिया जा रहा है। चूँकि प्रभावी अक्टूबर 26, 2005 से एलएएफ के अंतर्गत रेपो दर, पूर्ववर्ती 6.00 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत तक, संशोधित कर दिया गया है, उसी तारीख से ईसीआर 6.25 प्रतिशत पर दिया गया। प्रभावी जनवरी 24, 2006 से रेपो दर में 6.25 प्रतिशत से 6.50 प्रतिशत तक वृद्धि के परिणाम स्वरूप ईसीआर चालू रेपो दर पर दी जा रही है।

निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा के उपयोग में प्रवृत्तियाँ

2.113 कुल निर्यात ऋण मार्च 18, 2005 को 69, 059 करोड़ रुपए से फरवरी 3, 2006 को 83, 601 करोड़ रुपए तक बढ़ा। निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमा जो मार्च 18, 2005 को 4,928 करोड़ रुपए पर थी, फरवरी 3, 2006 को 5, 526 करोड़ रुपए तक बढ़ी। इस अवधि के दौरान, निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा, कभी-कभी, दिसंबर 2005 तक उपयोग में लाई गई। दिसंबर 2005 से माँग मुद्रा दरों में दृढ़ता और बाजार में चलनिधि परिस्थितियों में कड़ाई के कारण, ईसीआर का दैनिक औसत उपयोग जनवरी 6, 2006 को 1, 412 करोड़ रुपए से फरवरी 3, 2006 को 2, 469 करोड़ रुपए तक बढ़ा।

चयनित वित्तीय संस्थाओं (एफआइ) द्वारा संरक्षक सीमा के अंतर्गत संसाधन का संग्रहण

2.114 वर्ष 1990 तक वित्तीय संस्थाएं बाजार अनुशासन के अधीन नहीं थीं लेकिन प्रमुख रूप से भारत सरकार के प्लान प्राथमिकताओं और औद्योगिक लाइसेंस निर्धारण के मुताबिक पूंजी उपलब्ध कराने के यंत्र थे। उनका वित्तपोषण रियायती संसाधनों के माध्यम, सरकार द्वारा गारंटीशुदा बंधपत्रों और रिजर्व बैंक के लंबी-अवधि परिचालन (एलटीओ) निधियों से अग्रिम, द्वारा हुआ। वर्तमान समय में, एक वित्तीय संस्था अल्प-अवधि के अलावा दीर्घ-अवधि के संसाधन उगाह सकती है कि जिससे ऐसी निधियों का कुल बकाया, किसी भी समय नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार उसके निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) निधियों के 10 गुने से अधिक न हो। इस समग्र सीमा के भीतर, नौ संस्थाओं अर्थात्, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आइडीबीआई), भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम (आइएफसीआई), निर्यात आयात बैंक (एलकजम बैंक), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि. (आइआइबीआई), भारतीय पर्यटन वित्त निगम (टीएफसीआई), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), बुनियादी सुविधा विकास वित्त कंपनी (आइडीएफसी) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के पास, उनके नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार निवल स्वाधिकृत निधि के 100 प्रतिशत के बराबर संसाधन जुटाने के लिए, संरक्षक सीमाएँ थीं। तथापि, अक्टूबर 1, 2004 के प्रभाव से आइडीबीआई का खुद को अनुसूचित बैंक, आइडीबीआई लिमिटेड में परिवर्तित करने के कारण, चयनित वित्तीय संस्थाओं की संख्या आठ तक नीचे आई। प्रसंगवश, आइडीबीआई लिमिटेड का प्रभावी अप्रैल 2, 2005 से आइडीबीआई बैंक लि. के साथ विलय हुआ। इन चयनित वित्तीय संस्थाओं की, मीयादी मुद्रा, मीयादी जमाराशि, अंतर-कंपनी जमाराशियों (आइसीडी), जमाराशि प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पत्र के माध्यम से संसाधन जुटाने के लिए समुच्चय सीमाएँ अप्रैल 1, 2005 को 16,160 करोड़ रुपए से बढ़कर दिसंबर 23, 2005 को 17,046 करोड़ रुपए हुईं।

संसाधन संग्रहण की प्रवृत्तियाँ

2.115 इन यंत्रों से, वित्तीय संस्थाओं द्वारा उगाहे गए संसाधन की कुल बकाया राशि, अप्रैल 1, 2005 को 2, 862 करोड़ रुपए (सीमा का 17. 7 प्रतिशत) से थोड़ी घटकर फरवरी 3, 2006 को 2, 002 करोड़ रुपए (सीमा का 11.74 प्रतिशत) हुई। औसत के आधार पर, वाणिज्यिक पत्र सबसे अधिक वरीयता प्राप्त यंत्र था (1,900 करोड़ रुपए), अनुसरण में मीयादी उधार राशियों (50 करोड़ रुपए), जमा प्रमाणपत्र (26.66 करोड़ रुपए), मीयादी जमाराशियों (25 करोड़ रुपए) और आइसीडी (0.25 करोड़ रुपए)। उल्लेखनीय रूप से, केवल चार संस्थाएँ, अर्थात्, बुनियादी सुविधा विकास वित्त कंपनी, निर्यात आयात बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, चालू वर्ष 2005-06 के दौरान अब तक (अप्रैल-फरवरी 3, 2006), इन यंत्रों के जरिए संसाधन जुटाने में सक्रिय थे।

2.116 मुद्रा बाजार, बहुत से यंत्रों की बढ़ती हुई मात्रा से, गहराई में बढ़ रहे हैं। हाल में, विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से, इन बाजारों की निपुणता को बढ़ाने एवं स्थिरता के लिए, अनेक उल्लेखनीय गतिविधियाँ, मौद्रिक नीति संवेगों को प्रसारित करने समेत, घटित हुई हैं (बॉक्स II.1)। ऐसी प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं माँग मुद्रा बाजार का शुद्ध अंतर-बैंक बाजार के रूप में उभरने के साथ केवल बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के रूप में पात्र ईकाइयाँ और गैर बैंक ईकाइयों को संपाश्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता (सीबीएलओ) के नए जमानती यंत्र की ओर अंतरण और बाजार रेपो। द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा के रूप में एक अतिरिक्त एलएएफ खिड़की के खोलने से भी चलनिधि प्रबंध मजबूत बना। प्रचुर मात्रा और अस्थिर विदेशी विदेशी मुद्रा प्रवाह ने, तथापि, चलनिधि प्रबंध के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रस्तुत करना जारी रखा। चूँकि, सरकारी नकद राशि-प्रवाह का भी निम्न आनुमानिकता है, चलनिधि प्रबंध कुछ अनिश्चितता से करना होता है। इस पृष्ठभूमि में, भारत में मौद्रिक नीति परिचालनों के लिए अल्प-अवधि ब्याज दरों में अस्थिरता को, हाल के समय में, नियंत्रित करना पर्याप्त मात्रा में सफलता का विषय है।

सरकारी प्रतिभूतियाँ बाजार

2.117 रिज़र्व बैंक, लागत को समय से कम करने और केंद्र और राज्यों दोनों के लिए ऋण की परिपक्वता रूपरेखा के संप्रसारण के जुड़वाँ उद्देश्यों की खोज में, ऊर्ध्वमुखी अंतरित उत्पन्न वक्र के परिदृश्य में, चालू वर्ष के दौरान अब तक कायम रहा। 2005-06 के दौरान केंद्र सरकार का बाजार उधार, पिछले वर्ष के तदनुसूची अवधि की तुलना में, उल्लेखनीय रूप से उच्चतर था, जबकि राज्य सरकारों का निम्नतर, जो प्रमुख रूप से ऋण विनिमय योजना (डीएसएस) का 2004-05 में बंद होना दर्शाता है। वर्ष के दौरान जारी किए गए सरकारी प्रतिभूतियों का भारित औसत उत्पन्न कुछ हद तक मजबूत हुआ जबकि, अधिक मात्रा में दीर्घ-अवधि बंधपत्रों के जारी करने के कारण भारित औसत

परिपक्वता थोड़ी बढ़ी। प्रणाली में सुविधाजनक चलनिधि स्थिति के साथ कतिपय राज्य सरकारों की भावी वित्तीय स्वास्थ्यवर्धक बाजार संभावनाएँ-उनके राजकोषीय दायित्व विधिनिर्माण अधिनियमन द्वारा कुछ हद तक प्रेरित किया-ने संभवतः निम्नतर विस्तार की नीलामियों की सफलता में, ‘‘टैप इश्यू’’ की तुलना में, योगदान किया (तदनुसूची सरकारी प्रतिभूतियों से ऊपर)। चलनिधि प्रबंध में तालमेल और बाजार सहभागियों के सुझावों के अनुसार, एक द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा नवंबर 28, 2005 के प्रभाव से शुरू की गई। रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2005-06 (जनवरी 24, 2006) के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की तीसरी तिमाही समीक्षा में घोषित किया कि वह प्रणाली में यथोचित चलनिधि बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करना जारी रखेगा जिससे ऋण की वास्तविक जरूरतें, कीमत और वित्तीय स्थायित्व के उद्देश्यों के सामंजस्य के साथ, पूरी की जा सकें। तदनुसार, चालू समष्टि आर्थिक और समग्र मौद्रिक परिस्थितियों के दृष्टिकोण से, रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत फिक्स्ड रिवर्स रेपो दर को, 25 आधार अंकों से, 5.25 प्रतिशत से 5.50 प्रतिशत तक बढ़ाया गया जबकि रिवर्स रेपो और रेपो दरों के बीच के विस्तार को फिलहाल 100 आधार अंकों पर बनाए रखा गया। एलएएफ के अंतर्गत फिक्स्ड रिवर्स रेपो दर, इसलिए, अविलंब प्रभाव से, अर्थात् जनवरी 24, 2006 को एसएलएफ के चालू होने से, 6.50 प्रतिशत पर रहेगा।

2.118 2005-06 के दौरान अब तक (फरवरी 28, 2006 तक) केंद्र और राज्य सरकारों का बाजार उधार कार्यक्रम, प्रमुख रूप से सुविधाजनक चलनिधि परिस्थितियों के कारण सफलतापूर्वक प्रबंधित किया गया। चालू वर्ष के दौरान अब तक, बहुत से राज्यों ने बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत संसाधन उगाहने के लिए नीलामी मार्ग का विकल्प अपनाया। चालू वर्ष के दौरान अब तक, केंद्र के अलावा राज्यों के बाजार उधार राशियों की भारित औसत लागत का बढ़ना जारी रहा जो वैश्विक ब्याज दरों में उलटाव, घरेलू विकास में उछाल और नवंबर-फरवरी 2006 के दौरान चलनिधि परिस्थितियों में कड़ाई को दर्शाता

बॉक्स II.1

मौद्रिक नीति पर रिज़र्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति

मौद्रिक नीति में परामर्शदात्री प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2005 में एक मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी), मौद्रिक अर्थशास्त्र, केंद्रीय बैंकिंग, वित्तीय बाजार और सार्वजनिक वित्त क्षेत्र के चार बाह्य विशेषज्ञों के साथ बनाई। रिज़र्व बैंक के गवर्नर टीएसी के अध्यक्ष हैं साथ में मौद्रिक नीति विभाग के प्रभारी उप गवर्नर आंतरिक सदस्य के रूप में हैं। अन्य उप गवर्नर (रों) और कोई विशेषज्ञ, आवश्यकता के अनुसार, टीएसी की मीटिंगों में विशेष अतिथि रहेंगे साथ में आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग

तथा मौद्रिक नीति विभाग के प्रमुख उपस्थित रहेंगे। मौद्रिक नीति विभाग को समिति के सचिवालय के रूप में नामित किया गया है।

समिति के अभिदेशन की शर्तें हैं समष्टि आर्थिक और मौद्रिक गतिविधियों की समीक्षा और मौद्रिक नीति के रुझान पर सलाह देना। समिति के लिए तिमाही में कम से कम एकबार मिलना अपेक्षित है और उसके विचारों पर चर्चा भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की आगामी मीटिंग में की जाएगी। वर्तमान समिति का कार्यकाल जनवरी 31, 2007 तक है।

है। बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र और राज्यों प्राथमिक प्रचालनों की भारित औसत परिपक्वता, वर्ष के दौरान, उच्चतर रही। चालू वर्ष के दौरान अब तक, केंद्र सरकार ने केवल दो अवसरों पर (मई 3, 2005 और जून 4, 2005) अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) का लाभ उठाया जो सुविधाजनक चलनिधि स्थिति को दर्शाता है। राज्य सरकारों द्वारा भी अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग, पिछले वर्ष की तुलना में, उल्लेखनीय रूप से घटा। तदनुरूपी, अधिकतर राज्यों और केंद्र बड़े अधिशेष नकदी शेष जमाराशि का संचय किया।

केंद्र सरकार के बाजार उधार 2005-06

2.119 2005-06 के लिए केंद्र सरकार के निवल बाजार उधार का केंद्रीय बजट अनुमान 1,10,291 करोड़ रुपए (समेत 182- दिवसीय खजाना बिलों का निवल प्रचालन) आँका गया। 68,282 करोड़ रुपए की चुकौतियों समेत, सकल बाजार उधार का अनुमान 1,78,573 करोड़ रुपए है। दिनांकित प्रतिभूतियों के संबंध में एक सांकेतिक प्रचालन कैलेंडर, वर्ष 2005-06 के प्रथमार्ध के लिए, सरकार से परामर्श के बाद 83,000 करोड़ रुपए की एक समुच्चय राशि के लिए, जारी किया गया। तथापि, मई 3, 2005 को 29.27 वर्ष परिपक्वता के लिए हुई नीलामी में अधिसूचित राशि में कटौती होने के कारण, 4,000 करोड़ रुपए से 2,000 करोड़ रुपए तक, वास्तविक प्रचालन 81,000 करोड़ रुपए का हुआ। सितंबर 19, 2005 को, केंद्र सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांकित प्रतिभूतियों का प्रचालन-कैलेंडर, चालू वित्तीय वर्ष के द्वितीयार्ध के लिए (अक्टूबर-मार्च), जारी किया गया। कैलेंडर ने फरवरी 2006 के अंत तक 58,000 करोड़ रुपए दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उगाहने का प्रस्ताव किया। अवधि के दौरान वास्तविक प्रचालन 40,000 करोड़ रुपए का हुआ क्योंकि 6,000 करोड़ रुपए के लिए 11.83 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2014 की अक्टूबर 6, 2005 को हुई नीलामी में सभी बोलियाँ, परिमित बोली के कारण निरस्त कर दी गई थीं, जबकि 4,000 करोड़ रुपए के लिए दूसरी अनुसूचित नीलामी, केंद्र सरकार के पास अधिशेष चलनिधि होने के कारण निरस्त की गई। इसके अतिरिक्त, फरवरी 7, 2006 को, 11.56 वर्ष अवधि की दिनांकित प्रतिभूति के प्रचालन के माध्यम से, कैलेंडर में घोषित 6,000 करोड़ रुपए के बदले 3,000 करोड़ रुपए की राशि, उगाही गई। फरवरी 20, 2006 को 5,000 करोड़ रुपए के लिए, परास 10-14 वर्ष के बीच अवधि की दिनांकित प्रतिभूति की अनुसूचित नीलामी निरस्त की गई।

2.120 2005-06 के दौरान अब तक (फरवरी 28, 2006 तक), केंद्र सरकार द्वारा उगाही गई सकल बाजार उधार राशियाँ (बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत प्रचालन के सिवाय), पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान उगाही गई 1,04,491 करोड़ रुपए (निवल 46,044 करोड़ रुपए) के विरुद्ध 1,58,339 करोड़ रुपए (निवल 95,589

करोड़ रुपए) थीं (सारणी 2.40)। सभी प्रचालन पुनः जारी किए गए थे सिवाय सितंबर 8, 2005 को जारी किए गए 30-वर्ष दिनांकित प्रतिभूति और फिक्स्ड कूपन प्रतिभूतियों के रूप में थे। 2005-06 के दौरान अब तक, पुनः जारी की गई कुल प्रतिभूतियों का हिस्सा, पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 60 प्रतिशत हिस्से के विरुद्ध 97 प्रतिशत निकला। पिछले वर्ष के दौरान 847 करोड़ रुपए और 985 करोड़ रुपए का डिवाॅल्वमेंट क्रमशः रिजर्व बैंक और प्राथमिक व्यापारियों पर और निजी प्लेसमेंट के द्वारा जारी किए गए 350 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष के दौरान अब तक डिवाॅल्वमेंट /निजी प्लेसमेंट नहीं हुआ।

दिनांकित प्रतिभूतियाँ

2.121 2004-05 की प्रवृत्ति को कायम रखते हुए, 2005-06 के दौरान जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत आय उर्ध्वमुखी रही। 2005-06 के दौरान अब तक (फरवरी 28, 2006 तक) जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत आय 7.30 प्रतिशत पर, पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 6.11 प्रतिशत के अलावा पूरे पिछले वर्ष की तुलना में, उच्चतर थी। 2005-06 के दौरान अब तक जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत परिपक्वता भी बढ़ी, जो दीर्घ-कालिक प्रतिभूतियों के बड़े प्रचालन को दर्शाता है। वर्ष के दौरान अब तक, जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत परिपक्वता, पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के अलावा पूरे पिछले वर्ष के लिए 14.13 वर्ष की तुलना में, 15.86 वर्ष निकली।

खजाना बिल

2.122 वर्ष 2005-06 के दौरान, 91-दिवसीय और 364-दिवसीय खजाना बिलों की अधिसूचित राशियाँ (सिवाय बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत), प्रत्येक नीलामी के लिए, क्रमशः 500 करोड़ रुपए और 1,000 करोड़ रुपए पर अपरिवर्तित रखी गईं। 182-दिवसीय खजाना बिलों की नीलामी को, 500 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि से, पुनः आरंभ किया गया। इसके अलावा, 91-दिवसीय खजाना बिलों की नीलामी के जरिए, बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत 1,500 करोड़ रुपए उगाहना था, जबकि 2005-06 के दौरान, 182-दिवसीय और 364-दिवसीय खजाना बिलों की नीलामियों के माध्यम से, 1,000 करोड़ रुपए प्रत्येक, अवशोषित करना था। अगस्त 31, 2005 और सितंबर 28, 2005 के बीच पांच नीलामियों के लिए 91-दिवसीय खजाना बिलों के अंतर्गत अधिसूचित राशि को 4,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया (500 करोड़ रुपए नियमित नीलामी के लिए और 3,500 करोड़ रुपए बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत)। प्रणाली की समग्र चलनिधि स्थिति को ध्यान में रख कर, नवंबर 16, 2005 को की गई खजाना बिलों की नीलामियों से बाजार स्थिरीकरण योजना-अवयव के प्रचालन को बंद कर दिया गया।

सारणी 2.40 : केंद्र सरकार का बाज़ार उधार

(करोड़ रुपए)

मद	2004-05		2004-05 (अप्रैल-फरवरी)		2005-06 (अप्रैल-फरवरी)	
	सकल	निवल	सकल	निवल	सकल	निवल
1	2	3	4	5	6	7
1. बजट अनुमान * उसमें से:	1,50,817	90,365			1,78,573	1,10,291
(i) दिनांकित प्रतिभूतियाँ	1,24,817	90,501			1,39,573	1,03,942
(ii) 182-दिवसीय खजाना बिल	0	0			13,000	6,500
(iii) 364-दिवसीय खजाना बिल	26,000	-136			26,000	-151
2. अब तक पूर्ण किया गया @ उसमें से:	1,06,501	46,050	1,04,491	46,044	1,58,339	95,589
(i) दिनांकित प्रतिभूतियाँ	80,350	46,034	80,350	46,034	1,21,000	88,370
(ii) 182-दिवसीय खजाना बिल	0	0	0	0	12,088	6,109
(iii) 364-दिवसीय खजाना बिल	26,151	16	24,141	10	25,251	1,110
3. निजी प्लेसमेंट	350		350		0	
4. डिवाॅल्वमेंट	1,832		1,832		0	
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक	847		847		0	
(ii) प्राथमिक व्यापारी	985		985		0	
5. दिनांकित प्रतिभूतियों पर भारित औसत आय (प्रतिशत)	6.11		6.11		7.30	
6. दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत परिपक्वता (वर्ष)	14.13		14.13		15.86	

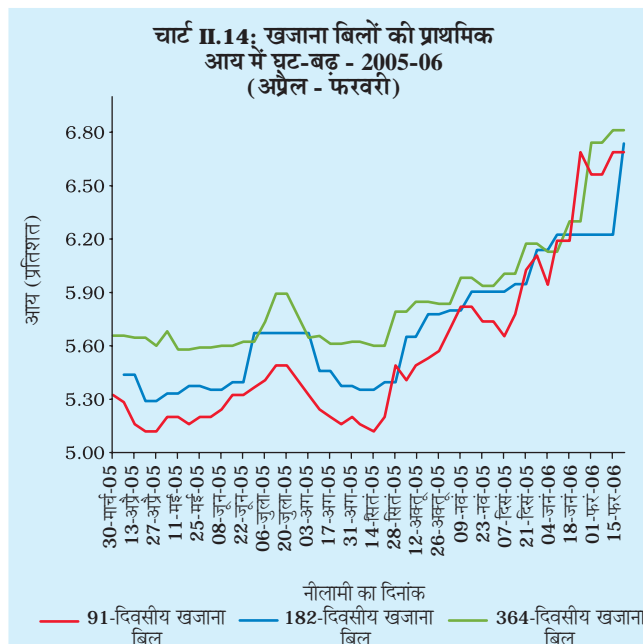
* पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए।

@ 2004-05 के लिए वास्तविक।

2.123 91-दिवसीय और 364-दिवसीय खजाना बिलों की प्राथमिक बाज़ार कट-ऑफ आय 137 आधार अंकों और 115 आधार अंकों से बढ़ी, क्रमशः 6.69 प्रतिशत और 6.81 प्रतिशत तक, क्रमशः फरवरी 22, 2006 और फरवरी 15, 2006 की नीलामियों में अंत- मार्च 2005 की तुलना में (चार्ट II.14)। अप्रैल 6, 2005 को उसकी शुरुआत के बाद से, फरवरी 22, 2006 को ली गई नीलामी में, 182-दिवसीय खजाना बिलों की प्राथमिक बाज़ार कट-ऑफ आय भी 130 आधार अंकों से 6.74 प्रतिशत तक बढ़ी।

राज्य सरकारों के बाज़ार उधार

2.124 चालू राजकोषीय वर्ष के दौरान अब तक (फरवरी 28, 2006 तक), राज्य सरकारों की सकल उधार राशियाँ 19,909 करोड़ रुपए [11,186 करोड़ रुपए (56.2 प्रतिशत) “टैप” प्रचालन के माध्यम से और 8,723 करोड़ रुपए (43.8 प्रतिशत) नीलामियों के जरिए], पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में 38,668 करोड़ रुपए [37,783 करोड़ रुपए (97.7 प्रतिशत) डेटैपड प्रचालन के माध्यम से और 885 करोड़ रुपए (2.3 प्रतिशत) नीलामियों के जरिए] की तुलना में, थीं। यह ध्यान रखा जाए कि, 2004-05 के दौरान 42,058 करोड़ रुपए के सकल आबंटन में 18,805 करोड़ रुपए और 2,351 करोड़ रुपए क्रमशः ऋण अदला-बदली योजना (डीएसएस) और ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरआइडीएफ) के अंतर्गत सम्मिलित हैं जबकि, 2005-06 के लिए सकल आबंटन को 25,589 करोड़ रुपए रखा गया है।



2.125 2005-06 के दौरान अब तक (फरवरी 28, 2006 तक) जारी राज्य सरकार के प्रतिभूतियों की भारित औसत आय, पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान 6.44 प्रतिशत और संपूर्ण 2004-05 के दौरान 6.45 प्रतिशत की तुलना में, 7.62 निकली। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सभी प्रचालन 10-वर्ष की परिपक्वता के थे जबकि, पिछले वर्ष की

तदनुसूची अवधि के दौरान जारी की गई राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की भारत औसत परिपक्वता 9.99 वर्ष थी। चालू वर्ष में अब तक (फरवरी 28, 2006 तक) बीस राज्यों ने बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत संसाधन उगाहने के लिए नीलामी मार्ग का विकल्प चुना, पिछले वर्ष में तीन राज्यों की तुलना में। 2005-06 के दौरान अब तक (फरवरी 28, 2006), यद्यपि राज्य विकास ऋणों की नीलामियों में कट-ऑफ आय 7.32-7.85 प्रतिशत के परास के बीच में रही, टैप प्रचालनों का कूपन 7.53-7.77 प्रतिशत परास के बीच में रहा।

खुले बाजार परिचालन

2.126 जनवरी 2004 से, रिजर्व बैंक ने किसी एकमुश्त खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) बिक्री का संचालन नहीं किया। 2005-06 के दौरान अब तक (फरवरी 24, 2006 तक), ओएमओ बिक्री (अधिशेष निवेश /सरकारी प्रतिभूतियों की परिपक्वता आगम के पुनर्निवेश के लिए संपूर्ण रूप से राज्य सरकारों को बेची गई प्रतिभूतियों की राशि के कारण और समेकित डूबंत कोष और गारंटी विमोचन कोष के निवेश के कारण), पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान 2, 493 करोड़ रुपए की ओएमओ बिक्री की तुलना में, कुल 3, 718 करोड़ रुपए की हुई।

बाजार स्थिरीकरण योजना

2.127 बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत अवशोषित कुल बकाया राशि फरवरी 28, 2006 को 31,958 करोड़ रुपए तक घटी, मार्च 31, 2005 को 64, 211 करोड़ रुपए की तुलना में (सारणी 2.41)। अगस्त 25, 2005 को, एमएसएस के अंतर्गत, 1.76 वर्ष की अवशिष्ट परिपक्वता वाली दिनांकित प्रतिभूति के पुनः प्रचालन के जरिए, 6, 000 करोड़ रुपए (अंकित मूल्य), अवशोषित किया गया। ध्यान रहे कि, 2004-05 में, दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से एमएसएस के अंतर्गत अवशोषित (अंकित मूल्य) 20, 000 करोड़ रुपए, सितंबर 3, 2005 को परिपक्व हुए।

2.128 अगस्त 27, 2005 को, एमएसएस के अंतर्गत खजाना बिलों और दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों की सांकेतिक अनुसूची, अगस्त 31, 2005 और सितंबर 28, 2005 के बीच पांच नीलामियों के लिए 91-दिवसीय खजाना बिलों की अधिसूचित राशि को 2, 000 करोड़

रुपए से 3, 500 करोड़ रुपए तक बढ़ाने के लिए, 10, 000 करोड़ रुपए की एक अतिरिक्त अधिशेष चलनिधि को जब्त करने के निमित्त, दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए संशोधित की गई। 182-दिवसीय और 364-दिवसीय खजाना बिलों की अधिसूचित राशियाँ एमएसएस के अंतर्गत अपरिवर्तित रहीं। प्रणाली की समग्र चलनिधि स्थिति को ध्यान में रख कर, नवंबर 16, 2005 को की गई खजाना बिलों की नीलामियों से, बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत खजाना बिलों की नीलामियों के माध्यम से अवशोषण को बंद कर दिया गया।

चलनिधि समायोजन सुविधा

2.129 वित्तीय वर्ष के दौरान अक्टूबर 2005 तक चलनिधि परिस्थितियाँ सामान्यतः सुविधाजनक रहीं लेकिन उसके बाद, प्रमुख रूप से त्यौहार मौसम से मुद्रा प्रचलन में तीव्र वृद्धि के अलावा भारत सरकार अधिशेष नकदी शेष जमाराशि में वृद्धि के कारण, कठोर हुई, जो अंशतः मध्य-दिसंबर में अग्रिम कर बाहिर्वाह और दिसंबर 29, 2005 को हुए इंडिया मिलेनियम डिफॉजिट के विमोचन को दर्शाता है। अप्रैल 2005 के दौरान, निवल औसत दैनिक चलनिधि अवशोषण 30, 765 करोड़ रुपए पर था जो जुलाई 2005 के दौरान धीरे-धीरे 10, 754 करोड़ रुपए पर घटा। अगस्त 2005 के दौरान निवल औसत चलनिधि अवशोषण 34, 832 करोड़ रुपए पर बढ़ा परंतु नवंबर 2005 के दौरान तेजी से 3, 268 करोड़ रुपए पर घटा और आगे दिसंबर 2005 के दौरान 1, 452 करोड़ रुपए और ऋणात्मक हुआ, जनवरी 2006 के दौरान (-) 15, 386 करोड़ रुपए पर तथा फरवरी 2006 के दौरान (-) 13, 532 करोड़ रुपए पर। परिणामतः, रेपो बोलियाँ प्राप्त हुईं और स्वीकार की गईं, नवंबर 9-18, 2005 के दौरान सात लगातार कार्यदिवसों के लिए परास 200 करोड़ रुपए और 5, 175 करोड़ रुपए के बीच में, दिसंबर 16-30, 2005 के दौरान 11 लगातार कार्यदिवसों के लिए परास 1,085 करोड़ रुपए-30,110 करोड़ रुपए के बीच में, जनवरी, 2006 के दौरान 18 कार्यदिवसों के लिए परास 50 करोड़ रुपए-33, 290 करोड़ रुपए के बीच में, और फरवरी, 2006 के दौरान 19 कार्यदिवसों के लिए परास 4,515 करोड़ रुपए-5, 175 करोड़ रुपए के बीच में।

सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन

2.130 द्वितीयक बाजार के लेनदेन की मात्रा अप्रैल 2005 में 1,75, 527 करोड़ रुपए (लेनदेन का 47.98 प्रतिशत एकमुश्त था और

सारणी 2.41 : बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत बकाया

(करोड़ रुपए)

यंत्र	मार्च 31, 2005	जून 30, 2005	सितंबर 30, 2005	फरवरी 28, 2006
1	2	3	4	5
दिनांकित प्रतिभूतियाँ	25,000	25,000	11,000	11,000
91-दिवसीय खजाना बिल	19,248	19,251	23,557	0
182-दिवसीय खजाना बिल	-	5,844	9,815	3,919
364-दिवसीय खजाना बिल	19,963	21,585	21,777	17,039
कुल	64,211	71,680	66,149	31,958

बाकी रेपो के कारण) से फरवरी 2006 के दौरान 1,81, 854 करोड़ रुपए (लेनदेन का 23.8 प्रतिशत एकमुश्त था और बाकी रेपो के कारण) तक बढ़ी। यद्यपि, एकमुश्त लेनदेन की मात्रा, अप्रैल 2005 के दौरान 84, 225 करोड़ रुपए से फरवरी 2006 में 43, 306 करोड़ रुपए तक घटी, रेपो लेनदेन की मात्रा, अप्रैल 2005 के दौरान 91, 302 करोड़ रुपए से उसी अवधि के दौरान 1,38, 548 करोड़ रुपए तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ी। फरवरी 2006 के दौरान पण्यवर्त (एकमुश्त लेनदेन का दुगुना और रेपो का चार गुना परिकलित) 6,40,805 करोड़ रुपए से अप्रैल 2005 के दौरान 5,33,658 करोड़ रुपए तक बढ़ा।

2.131 फरवरी 2006 के दौरान, तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) में पांच सबसे अधिक लेनदेन की हुई प्रतिभूतियों ने, अप्रैल 2005 के दौरान 78.5 प्रतिशत की तुलना में, कुल लेनदेन के 68.3 प्रतिशत का हिसाब लिया, जिससे प्रतिभूतियों में चलनिधि के बढ़ते फैलाव का संकेत होता है।

आय गतिशीलता और आय वक्र

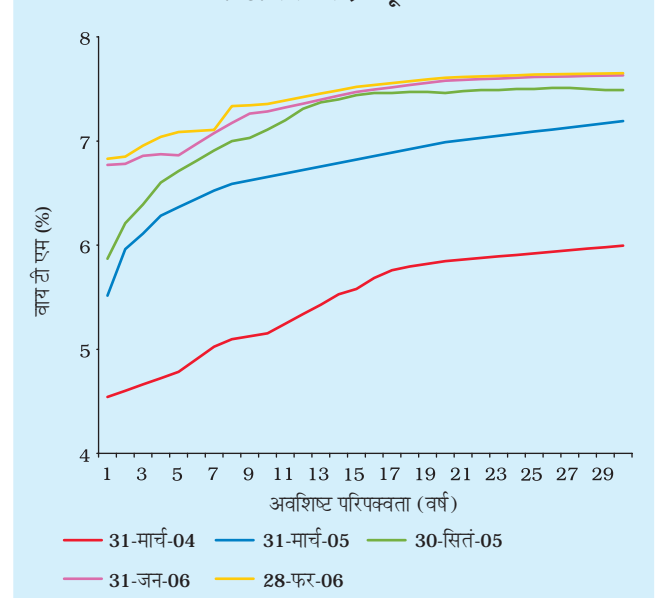
2.132 अप्रैल 2005 के दौरान, वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतों की पृष्ठभूमि में और घरेलू ईंधन की कीमत वृद्धि की चिंताओं से, आय सुदृढ़ हुई। अप्रैल 28, 2005 को घोषित वार्षिक नीति वक्तव्य में 25 आधार अंकों से रिवर्स रेपो दर की वृद्धि ने विक्री को प्रेरित किया और दिन के दौरान 10-वर्ष आय 11 आधार अंकों से मजबूत हुई। मार्च 2005 की समाप्ति से 66 आधार अंकों से उच्चतर, अप्रैल 30, 2005 को, 10-वर्ष आय 7.31 प्रतिशत पर बंद हुई।

2.133 तथापि, मई 2005 के दौरान सुविधाजनक चलनिधि स्थिति और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच में आय की वापसी हुई। अमरीकी खजाना आय ने भी भावना को सहारा दिया। प्रतिभूतियों की कीमतें जून और जुलाई के दौरान सीमित रहीं। जुलाई में बाजार थोड़ा संभला, जब बाजार सहभागियों द्वारा अपेक्षित रिवर्स रेपो दर की वृद्धि, जुलाई 26, 2005 को वार्षिक नीति वक्तव्य की पहली तिमाही समीक्षा में, लागू नहीं की गई। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों की सख्ती, जुलाई और अगस्त 2005 में सहभागियों के लिए प्रमुख चिंता का कारण थी और व्यापार निस्तेज था। प्रभावी अगस्त 1, 2005 से शुरू स्क्रीन- आधारित मेलखाती हुई आदेश प्रणाली (एनडीएस-ओएम) ने द्वितीयक बाजारों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाया। अगस्त 31, 2005 को 10-वर्ष आय 7.09 प्रतिशत पर बंद हुई (चार्ट II.15)। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के साथ 10-वर्ष आय का सितंबर 15, 2005 को 6.99 प्रतिशत पर बंद होने के कारण, सितंबर 2005 के प्रथमार्ध में कीमतें संभलीं। उसके बाद, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण और संभावित

उच्चतर मुद्रास्फीति दर की चिंता से, सितंबर 30, 2005 को आय 7.11 प्रतिशत तक मजबूत हुई जबकि, केंद्र सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत चालू वर्ष के द्वितीयार्ध के लिए 58, 000 करोड़ रुपए के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों का कैलेंडर जारी करने की घोषणा बाजार प्रत्याशाओं के अनुरूप थी।

2.134 अक्टूबर 2005 के दौरान, महीने की शुरुआत में कीमतें संभलीं लेकिन उसके बाद, तीव्र उतारचढ़ावों के बिना, सीमित रहीं क्योंकि वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा बाजार प्रत्याशाओं के अनुसार थी। 10-वर्ष आय सितंबर 30, 2005 को 7.11 प्रतिशत से अक्टूबर 31, 2005 को 7.10 प्रतिशत तक थोड़ी घटी। मजबूत चलनिधि परिस्थितियों और नवंबर 8, 2005 को भारत सरकार की दो प्रतिभूतियों की नीलामियों के कारण नवंबर 2005 की शुरुआत में कीमतें थोड़ी गिरीं। 7.49 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2017 की नीलामी में पहुँची कट-ऑफ आय बाजार प्रत्याशाओं के अनुसार थी, जबकि 7.40 प्रतिशत 2035 के लिए कट-ऑफ बाजार प्रत्याशाओं से उच्चतर था। 10-वर्ष आय, नवंबर 4, 2005 को 7.10 प्रतिशत से नवंबर 11, 2005 को 7.12 प्रतिशत तक बढ़ी। प्रतिभूति कीमतें सीमित रहीं क्योंकि बाजार भावना, बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) नीलामियों के निरस्त करने से और अनुसूचित नीलामी को निरस्त करने की प्रत्याशाओं से सकारात्मक रहीं। 10-वर्ष आय, नवंबर 18, 2005 को 7.11 प्रतिशत तक थोड़ी घटी। उसके बाद, घरेलू बाजार में मजबूत चलनिधि परिस्थितियों के आसान होने, फेड रिजर्व के कठिन चक्रों के रुकने की प्रत्याशाएँ और स्थिर तेल कीमतों से “जी-सेक” आय में थोड़ी नरमी आई। 10-वर्ष आय, नवंबर 30, 2005 को 7.08 प्रतिशत पर आसान हुई। दिसंबर

चार्ट II.15: सरकारी प्रतिभूति आय वक्र



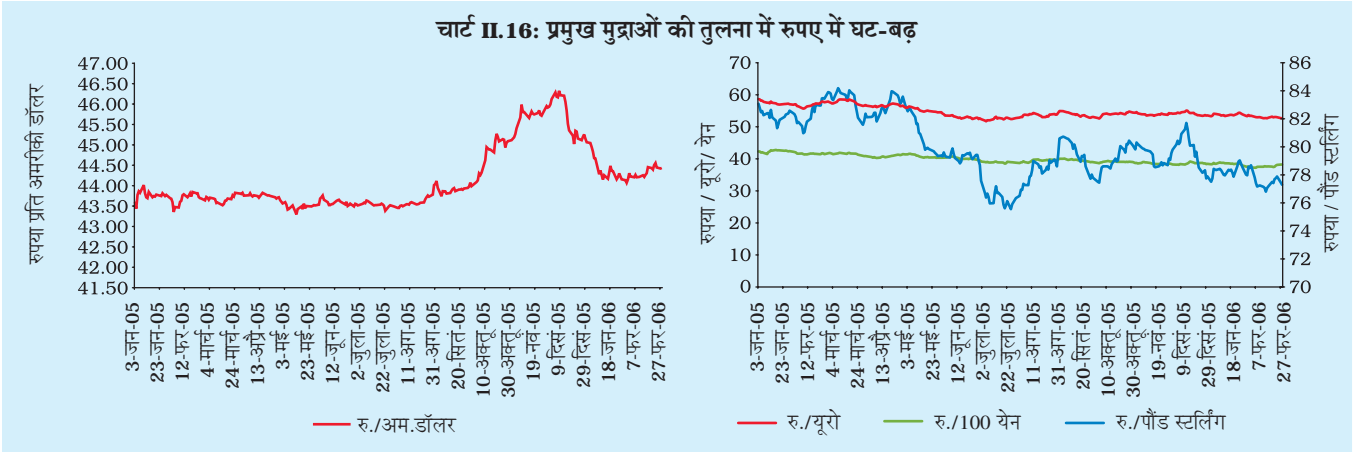
2005 के दौरान, “जी-सेक” आय, चलनिधि की कड़ी परिस्थितियों से अल्प-अवधि में मजबूत हुई, जबकि आय ने लंबे छोर पर, ईपीएफ दलों को कम करने के प्रस्ताव के बाद और अधिक परिपक्वता वाली “जी-सेक” नीलामी को अच्छे प्रतिसाद के कारण, एक आसान प्रवृत्ति दर्शाई। जनवरी 1 से 23, 2006 के दौरान, सरकारी प्रतिभूतियों की आय सामान्यतः सीमित रहीं। लंबे छोर पर आय के आसान होने के कारण आय वक्र थोड़ा सपाट हुआ। तथापि, रिवर्स रेपो और रेपो दरों, दोनों में क्रमशः 5.50 प्रतिशत और 6.50 प्रतिशत वृद्धि होने के कारण, जनवरी 24, 2006 को 10-वर्ष आय तेजी से 7.41 प्रतिशत तक बढ़ी। उसके बाद, प्रमुख रूप से चलनिधि में तंगी अर्जन और मूल्य खरीद से आय में नरमी आई। जनवरी 31, 2006 को 10-वर्ष 7.28 प्रतिशत पर बंद हुआ। फरवरी 2006 की शुरुआत में, वैश्विक कच्चे तेल कीमतों में आसानी और निम्नतर मुद्रास्फीति के कारण, प्रतिभूति कीमतें संभलीं। उसके बाद, फरवरी 8, 2006 को दिनांकित प्रतिभूति की अनुसूचित नीलामी में अधिसूचित राशि में कटौती, 6,000 करोड़ रुपए से 3,000 करोड़ रुपए तक, ने बाजार की चलनिधि चिंताओं को और आसान बनाया। फरवरी 3, 2006 को 10-वर्ष आय 7.30 प्रतिशत पर बंद हुई। उसके बाद, कठिन चलनिधि स्थिति के कारण प्रतिभूति कीमतें सीमित रहीं। तथापि, 5,000 करोड़ रुपए के लिए दिनांकित प्रतिभूति की, फरवरी 14-22, 2006 के बीच में अनुसूचित, नीलामी के निरस्तीकरण ने एक छोटी हालाँकि अल्पकालीन प्रतिभूति कीमतों की रैली की अगुआई की। 3,700 करोड़ रुपए के लिए राज्य सरकार प्रतिभूति की नीलामी की घोषणा से आय बढ़ी। फरवरी 28, 2006 को 10-वर्ष आय 7.37 प्रतिशत पर बंद हुई।

2.135 वर्ष के दौरान अब तक, केंद्र और राज्य सरकारों का बाजार उधार कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किया गया। राजकोषीय वर्ष 2006-07 के प्रभाव से, रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए प्राथमिक बाजार से अलग हो जाएगा। यद्यपि, यह मौद्रिक नीति के संचालन में अधिक लचीलापन और युक्तिचालना प्रदान करेगा, सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार को, अनावश्यक अस्थिरता का निवारण करने के लिए, और विकसित करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में चलनिधि के मामले को भी संबोधित करने की आवश्यकता है। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के साथ, 2005-06 के लिए राज्य योजनाएँ हेतु केंद्रीय ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था और राज्यों को अनुरूप संसाधन उगाहने के लिए बाजार में पैठ करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। भविष्य में राज्यों के बाजार उधार कार्यक्रम की सतत सफलता, जारी राजकोषीय सुधार प्रक्रिया पर निर्भर रहेगी। राज्यों को इसलिए राजकोषीय समेकन के लिए, विधि-निर्माण के अधिकार के साथ, विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति अपनाना जरूरी है।

विदेशी मुद्रा बाजार

2.136 विदेशी मुद्रा बाजार ने 2005-06 के दौरान अब तक (फरवरी 28, 2006 तक) सामान्यतः व्यवस्थित परिस्थितियाँ दर्शाई हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान (फरवरी 28, 2006 तक), भारतीय रुपए की विनिमय दर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 43.30-46.33 प्रति अमरीकी डॉलर के परास में रहीं। अप्रैल-मई 2005 के दौरान, विदेशी संस्थागत निवेशकर्ताओं द्वारा बहिर्वाह और उच्चतर माल व्यापार घाटा होने के बावजूद रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ, मार्चात 2005 के 43.76 रुपए से मई 12, 2005 को 43.30 रुपए प्रति अमरीकी डॉलर। बाद के सप्ताहों में, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अमरीकी डॉलर के सुदृढ़ होने से, भारतीय रुपए का हास जून 2, 2005 को 43.76 रुपए प्रति अमरीकी डॉलर तक हुआ। जुलाई 21, 2005 को चीनी युआन का पुनर्मूल्यन होने से, अधिमूल्यन दबाव के अंतर्गत, रुपया, अगस्त 1, 2005 को, 43.46 रुपए प्रति अमरीकी डॉलर पर रहा। तथापि, उसके बाद उसका महीने भर हास हुआ। रिजर्व बैंक ने जुलाई-अगस्त 2005 के दौरान 4.0 बिलियन अमरीकी डॉलर की निवल बाजार खरीदी की। हरीकेन कैटरिना से तेल की कीमतों के अंतरराष्ट्रीय बाजार में 70.8 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल की ऊँचाई छूने के प्रभाव के अंतर्गत अगस्त 2005 के अंतिम सप्ताह में रुपया पुनः दबाव में आया और 44.12 रुपए प्रति अमरीकी डॉलर पहुँचा (सितंबर 1, 2005)। उसके बाद, रुपए में थोड़ा सुधार आया और 43.99 रुपए प्रति अमरीकी डॉलर (सितंबर 29, 2005) पर पहुँचा। अक्टूबर 2005 के पहले सप्ताह से, चालू खाते के घाटे में तीव्र वृद्धि और मजबूत अमरीकी डॉलर के संमुख, रुपया दबाव में आया। संपूर्ण अक्टूबर और नवंबर महीने में रुपए ने अपनी हास होने की प्रवृत्ति जारी रखी, जो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के, अमरीकी डॉलर के मुकाबले हास के छलकने के प्रभाव और विदेशी संस्थागत निवेशकर्ताओं द्वारा बाहिर्वाह को दर्शाता है। विनिमय दर दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक घटी और दिसंबर 8, 2005 को 46.33 रुपए प्रति अमरीकी डॉलर पर रही। उसके बाद, कुछ प्रमुख मुद्राओं की वैश्विक रैली विशेषतः जापानी येन के मूल्य में एक भारी उछाल और विदेशी संस्थागत निवेशकर्ता अंतर्वाह के साथ, रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ। उसमें बढ़ोत्तरी हुई और फरवरी 28, 2006 को वह 44.44 रुपए प्रति अमरीकी डॉलर पर पहुँचा। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (फरवरी 28, 2006 तक) भारतीय रुपए में 1.5 प्रतिशत से हास हुआ। तथापि, उसी अवधि के दौरान रुपए में पाउंड स्टर्लिंग, यूरो और जापानी येन के मुकाबले क्रमशः 6.2 प्रतिशत, 7.4 प्रतिशत और 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट II. 16)। वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक (फरवरी 28, 2006 तक), 6-मुद्रा (व्यापार-आधारित भार) मासिक औसत वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरइआर) 0.5 प्रतिशत से बढ़ी और नाममात्र प्रभावी विनिमय दर (एनइआर) 0.6 प्रतिशत से बढ़ी।

चार्ट II.16: प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रूपए में घट-बढ़



2.137 वायदा बाजारों ने विदेशी मुद्रा बाजार के तत्काल खंड की गतिविधियों को प्रतिबिंबित किया। 2005-06 की पहली तिमाही के दौरान तत्काल बाजार-परिस्थितियों ने वायदा किस्तों को निम्न रखा। गैर बैंकों की डेरिवेटिव सौदेबाजी के ब्याज दर का मूल्यनिर्धारण करने के लिए, बेंचमार्क की तरह मुंबई अंतर-बैंक वायदा प्रस्तावित दर (मीफोर) को चरणबद्ध हटाने की घोषणा के कारण, मई 2005 में वायदा किस्त घटे। अमरीकी ब्याज दरों में वृद्धि के बाद ब्याज-दर विभेदक के संकुचन से वायदा किस्तों का घटना जारी रहा। तथापि, 1-माह वायदा दर ने, सितंबर 2005 से वृद्धि दर्शाई है (चार्ट II.17)।

पूजी बाजार

2.138 सार्वजनिक निर्गम, निजी प्लेसमेंट और यूरो निर्गम द्वारा उगाहे गए संसाधन, पिछले वर्ष की तदनु रूपी अवधि की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक, उच्चतर बने रहे। घरेलू शेयर बाजार सुव्यवस्थित ढंग से काम करें यह सुनिश्चित करने के लिए और उन्हें अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजारों के बराबर लाने के लिए, शेयर बाजारों का डीम्युचुअलाइजेशन और कॉर्पोरेटायजेशन, निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करना, प्रतिभूति बाजार का राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करना और कंपनी ऋण बाजार का विकास समेत, वर्तमान समय में अनेक सुधारों को लागू किया जा रहा है। वर्तमान समय में, भारत में शेयर बाजार अपने ऐतिहासिक उच्च स्तरों पर हैं।

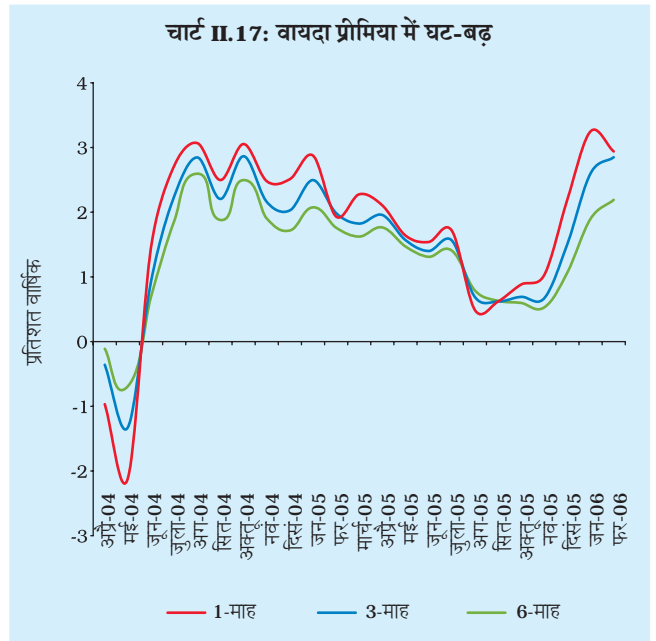
प्राथमिक बाजार

2.139 चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक (अप्रैल-जनवरी 2005-06), प्राथमिक बाजार ने, निर्गमों की संख्या और उगाहे गए संसाधन दोनों की वृद्धि से, एक प्रोत्साहित प्रवृत्ति को चित्रित किया। अप्रैल-जनवरी 2005-06 के दौरान, 101 सार्वजनिक निर्गमों द्वारा संसाधन उगाही, पिछले वर्ष की तदनु रूपी अवधि में 42 सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से उगाहे गए 14,799 करोड़ रुपए से, पर्याप्त मात्रा में, 53.2 प्रतिशत से 22,670 करोड़ रुपए तक बढ़ी। इसमें

से, 5 सार्वजनिक निर्गम सार्वजनिक क्षेत्र में थे, जो कुल उगाहे गए संसाधनों का 23.3 प्रतिशत था और शेष 96 सार्वजनिक निर्गम, अप्रैल-जनवरी 2005-06 के दौरान, निजी क्षेत्र के थे (सारणी 2.42)। इसके अतिरिक्त, अप्रैल-जनवरी 2005-06 के दौरान जारी किए गए 101 सार्वजनिक निर्गमों में से 100 सार्वजनिक निर्गम ईक्विटी निर्गम थे जो कुल उगाहे गए संसाधनों के 99.5 प्रतिशत थे।

2.140 निजी प्लेसमेंट के अलावा यूरो निर्गमों के माध्यम से संसाधन उगाही ने पर्याप्त मात्रा में वृद्धि दर्ज की। निजी प्लेसमेंट के माध्यम से, अप्रैल-दिसंबर 2005 के दौरान 37.6 प्रतिशत से 67, 288 करोड़ रुपए तक बढ़ी, अप्रैल-दिसंबर 2004 के दौरान 48, 887 करोड़ रुपए की तुलना में। सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों का निजी प्लेसमेंट बाजार में प्रभुत्व रहा। अप्रैल-दिसंबर 2005 के दौरान, उन्होंने 37, 741 करोड़ रुपए उगाहे (निजी प्लेसमेंट द्वारा कुल उगाहे गए का 56.1

चार्ट II.17: वायदा प्रीमिया में घट-बढ़



सारणी 2.42 : प्राथमिक बाजार * से संसाधन संग्रहण

(करोड़ रुपए)

मद	अप्रैल- जनवरी #							
	2003-04		2004-05		2004-05		2005-06	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क. प्रॉस्पेक्टस और राइट निर्गम@	47	7,851	59	21,892	42	14,799	101	22,670
I. सार्वजनिक क्षेत्र	9	4,176	5	8,410	3	5,018	5	5,291
II. निजी क्षेत्र	38	3,675	54	13,482	39	9,781	96	17,379
ख. निजी प्लेसमेंट	874	63,901	914	84,052	654	48,887	780	67,288
I. सार्वजनिक क्षेत्र	234	45,141	198	48,308	121	23,345	108	37,741
II. निजी क्षेत्र	640	18,760	716	35,744	533	25,543	672	29,547
ग. यूरो निर्गम	18	3,098	15	3,353	11	2,606	40	9,526

* ऋण और ईक्विटी दोनों समेत। # निजी प्लेसमेंट के लिए, आंकड़े अप्रैल-दिसंबर से संबंधित हैं। @ बिक्री के लिए प्रस्ताव के सिवाय।
ध्यान दें : अनुमान व्यवस्था करने वाले, वित्तीय संस्थाओं और समाचार पत्र के रिपोर्टों की जानकारी पर आधारित हैं।

प्रतिशत), अप्रैल-दिसंबर 2004 में उगाहे गए 23, 345 करोड़ रुपए (कुल का 47. 8 प्रतिशत) की तुलना में (सारणी 2.42)।

2.141 यूरो निर्गम के माध्यम से संसाधन संग्रहण, जिसमें अमरीकी निक्षेपागार (डिपाजिटरी) रसीद (एडीआर), वैश्विक निक्षेपागार (डिपाजिटरी) रसीद (जीडीआर) और विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) शामिल हैं, अप्रैल-जनवरी 2005-06 के दौरान तीव्र गति से बढ़ा। अप्रैल-जनवरी 2004-05 के दौरान ग्यारह निर्गमों के कुल 2, 606 करोड़ रुपए की तुलना में, अप्रैल-जनवरी 2005-06 के दौरान 9, 526 करोड़ रुपए के चालीस यूरो निर्गम थे (सारणी 2.42)। अधिकतर निर्गम जीडीआर द्वारा थे।

2.142 म्युचुअल फंडों द्वारा संसाधन संग्रहण (विमोचन का निवल) अप्रैल-जनवरी 2005-06 के दौरान 419.3 प्रतिशत से 35, 555 करोड़ रुपए तक, प्रमुख रूप से आय/ऋण अभिमुखी योजनाओं और विकास/ईक्विटी अभिमुखी योजनाओं दोनों के अंतर्गत संसाधन संग्रहण में वृद्धि के कारण, भारी मात्रा में बढ़ा। यूटीआइ म्युचुअल फंड और सार्वजनिक क्षेत्र के म्युचुअल फंडों ने अप्रैल-जनवरी 2005-06 के दौरान 545 करोड़ रुपए और 6, 646 करोड़ रुपए के निवल अंतर्वाह को, पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में क्रमशः 3, 071 करोड़ रुपए और 529 करोड़ रुपए के निवल बहिर्वाह की तुलना में, दर्ज किया। निजी क्षेत्र के म्युचुअल फंडों ने अप्रैल-जनवरी 2005-06 के दौरान 28,364 करोड़ रुपए के निवल अंतर्वाह को, अप्रैल-जनवरी 2004-05 के दौरान 10, 447 करोड़ रुपए के निवल अंतर्वाह की तुलना में, दर्ज किया (सारणी 2. 43)।

द्वितीयक बाजार

2.143 शेयर बाजार, जो अप्रैल-मई 2005 के दौरान घटा था, अन्य उभरते बाजारों के साथ मुंबई शेयर बाजार सेसेक्स और एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी के उच्च शिखर छूने से, जून-सितंबर 2005 के

दौरान तीव्र गति से संभला। अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ समष्टि आर्थिक मूल-सिद्धांत, प्रोत्साहक निवेश वातावरण, एफआइआइ द्वारा जारी अंतर्वाह और भारतीय कंपनियों द्वारा मजबूत कार्यनिष्पादन ने घरेलू शेयर बाजारों की ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति को योगदान दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज में विवादों का निपटारा, मानसून की संतोषजनक प्रगति, घरेलू मुद्रास्फीति दर में गिरावट, भारतीय एडीआर की कीमतों में उभार और घरेलू संस्थागत निवेशकों से सहारा ने भी बाजार भावना को उत्साही बनाया।

2.144 अक्टूबर 2005 महीने के दौरान, प्रमुख रूप से अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतों, कंपनियों के दूसरे तिमाही के वित्तीय परिणाम के पहले निवेशकों द्वारा अपनाए गए सतर्क दृष्टिकोण और विदेशी संस्थागत निवेशकर्ताओं (एफआइआइ) द्वारा निवेश में धीमापन के कारण बाजार भावना कमजोर हुई। तथापि, नवंबर 2005 के महीने में बाजारों में पुनःउछाल आरंभ हुआ जो अब तक जारी है। कंपनियों द्वारा दूसरी और तीसरी तिमाहियों के दौरान सुदृढ़ वित्तीय परिणामों की

सारणी 2.43 : म्युचुअल फंडों द्वारा निवल संसाधन संग्रहण

(करोड़ रुपए)

श्रेणी	अप्रैल-जनवरी			
	2003-04	2004-05	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
I. भारतीय यूनिट ट्रस्ट*	1,667	-2,722	-3,071	545
II. निजी क्षेत्र	42,544	7,600	10,447	28,364
III. सार्वजनिक क्षेत्र	2,597	-2,677	-529	6,646
कुल (I+II+III)	46,808	2,201	6,847	35,555

* पहले के यूटीआइ को यूटीआइ म्युचुअल फंड (सेबी से पंजीकृत) और यूटीआइ के विनिर्दिष्ट उपक्रम (सेबी से पंजीकृत नहीं) में विभाजित किया गया है। उपर्युक्त आंकड़ों में केवल यूटीआइ म्युचुअल फंड संबंधी जानकारी समाहित है।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी)।

घोषणा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा 2005-06 के लिए जीडीपी का उच्चतर विकास अनुमान (8.1 प्रतिशत), बैंकिंग क्षेत्र में नए सुधार उपायों की घोषणा जैसे, विदेशी निजी क्षेत्र के बैंकों को भारत में निजी क्षेत्र के कमजोर बैंकों के अधिग्रहण की अनुमति, भारतीय ईक्विटी बाजार में एफआइआइ निवेशों का जारी रहना और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और एशियाई ईक्विटी बाजारों में सुदृढ़ प्रवृत्तियों ने बाजार भावना में तेजी लाई। 2006-07 के केंद्रीय बजट में घोषित उपायों ने बाजार भावना को और उत्साही रखा। नीति घोषणाओं में शामिल हैं, सरकारी प्रतिभूतियों और कंपनी ऋण में एफआइआइ निवेश सीमा को क्रमशः 2 बिलियन अमरीकी डॉलर तक (1.75 बिलियन अमरीकी डॉलर से) और 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर तक (0.50 बिलियन अमरीकी डॉलर से) बढ़ाना, विदेशी लिखतों में म्युचुअल फंडों द्वारा कुल निवेशों की सीमा को, 10 प्रतिशत पारस्परिक हिस्सा धारिता की वांछनीयता को हटाकर, 1 बिलियन अमरीकी डॉलर से 2 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ाना, सीमित संख्या में योग्य भारतीय म्युचुअल फंडों को, विदेशी एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों में, 1 बिलियन अमरीकी डॉलर के संचयी निवेश की अनुमति देना, सेबी के तत्वाधान में निवेशक रक्षा फंड की स्थापना, कंपनी बांडों के लिए एक एकीकृत एक्सचेंज ट्रेडेड बाजार के निर्माण के लिए उपाय करना, अनुसूचित बैंकों की फिक्स्ड जमाराशियों का, जिनकी अवधि 5 वर्ष से कम न हो, आय कर अधिनियम की धारा 80 सी में समावेशन, उच्च सीमा शुल्कों में कमी, चयनित क्षेत्रों में उत्पाद शुल्कों का यौक्तीकरण और अनुषंगी लाभ कर (एफबीटी) में छूट। परिणामस्वरूप, बीएसई सेंसेक्स और एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी दोनों, फरवरी 28, 2006 को, अब तक के सबसे ऊँचे स्तरों, क्रमशः 10370.24 और 3074.70, पर बंद हुए। इस स्तर पर, बीएसई सेंसेक्स ने मार्चांत 2005 के ऊपर 59.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर, बीएसई सेंसेक्स, फरवरी 28, 2006 को 54.5 प्रतिशत से बढ़ा। औसत आधार पर बीएसई सेंसेक्स वित्तीय वर्ष में अब तक (फरवरी 28, 2006 तक), पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के ऊपर, 42.1 प्रतिशत से बढ़ा।

2.145 शेयर मूल्यों में वृद्धि के साथ, फरवरी 28, 2006 को बीएसई का बाजार पूंजीकरण जीडीपी के 76.7 प्रतिशत से बढ़ा, मार्चांत 2005 के जीडीपी के 54.6 प्रतिशत से, और नकदी खंड में दैनिक पण्यवर्त ने (बीएसई और एनएसई को मिलाकर) कई दिनों तक 11, 000 करोड़ रुपए पार किया। शेयर मूल्यों में उछाल विस्तृत-आधार के हैं, जिसमें सभी सूचकांक (बीएसई 500, बीएसई स्माल-कैप, बीएसई मिड कैप और बीएसई सेंसेक्स) और सभी क्षेत्र (ऑटो, बैंक, पूंजीगत माल, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ, सूचना प्रौद्योगिकी, तेल और गैस, औषध, इत्यादि) सम्मिलित हैं। पण्यवर्त, बाजार पूंजीकरण, कीमत / अर्जन अनुपात और बीएसई एवं एनएसई में अस्थिरता भी चालू वर्ष में अब तक, जितने पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में थे उनसे, उच्चतर रहे (सारणी 2.44)।

2.146 लगभग सभी क्षेत्रवार सूचकांकों ने, पूंजीगत माल, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ, शीघ्र विक्रेय उपभोक्ता माल (एफएमसीजी), सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), बैंकिंग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम समेत, वृद्धि दर्ज की। निवेश गतिविधि बढ़ने से और सुदृढ़ औद्योगिक कार्यनिष्पादन के कारण पूंजीगत माल के शेयर चढ़े। शेयर-विशिष्ट गतिविधियों जैसे, विलयन, बिक्री में सुदृढ़ वृद्धि और कुछ कंपनियों के अच्छे वित्तीय परिणाम के कारण उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के शेयरों में उछाल था। मानसून की संतोषजनक प्रगति के कारण, जिसने बदले में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में तेजी लाई, एफएमसीजी शेयरों ने उच्चतर वृद्धि दर्ज की। प्रमुखतः विदेशी बैंकों को भारत में निजी क्षेत्र के कमजोर बैंकों के 75 प्रतिशत हिस्से के अधिग्रहण की अनुमति, बैंकों के खाद्येतर ऋण में जोर पकड़ना, बैंकों को चिरस्थायी बांडों और अन्य मिश्रित लिखतों को जारी करने के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों दोनों द्वारा नए ईक्विटी निर्गमों के माध्यम से निधियों की उगाही, के कारण बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों ने वृद्धि दर्ज की। तेल कंपनियों को उनके तुलन पत्रों को सुदृढ़ करने के लिए विशेष बांडों को जारी करने की अनुमति के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर भी लाभान्वित हुए (चार्ट II.18)।

सारणी 2.44 : शेयर बाजारों की प्रवृत्तियाँ

मद	बीएसई		एनएसई	
	अप्रैल-फरवरी 2005-06	अप्रैल-फरवरी 2004-05	अप्रैल-फरवरी 2005-06	अप्रैल-फरवरी 2004-05
1	2	3	4	5
औसत बीएसई सेंसेक्स /एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी अस्थिरता (भिन्नता का गुणांक)	8,033	5,652	2,444	1,778
पण्यवर्त (करोड़ रुपए)	14.66	10.54	13.70	10.72
बाजार पूंजीकरण (अवधि की समाप्ति) (करोड़ रुपए)	6,97,307	4,59,188	13,60,160	10,27,016
पी/ई अनुपात (अवधि की समाप्ति)	26,95,542	17,30,940	25,12,083	16,14,597
	19.06	16.09	18.27	15.02

स्रोत : मुंबई शेयर बाजार (बीएसई) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई)।

आय कम होने के बावजूद सरकारी क्षेत्र और नए निजी क्षेत्र के बैंकों के लाभ अर्जन में वृद्धि हुई है। ऋण की मात्रा में तीव्र वृद्धि होने से निवल ब्याज आय में भारी वृद्धि हुई है, जिसने ब्याज से इतर आय में हुई तीव्र गिरावट के प्रभाव को काफी हद तक समाप्त कर दिया है। इस प्रकार बैंक, ब्याज दर के ऊर्ध्वमुखी चक्र के प्रभाव से होने वाले नुकसान से बचने में सामान्यतया सफल रहे हैं।

2.152 हाल के समय में अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक ऋण लेने की जो प्रवृत्ति बढ़ी है, वह उधारकर्ताओं और उधारदाताओं में पैदा हुए विश्वास का सबूत है। 2001 से लेकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में समस्त बैंक ऋण का अनुपात तेजी से बढ़ा है जिससे यह परिलक्षित होता है कि फुटकर तथा अन्य गैर परंपरागत सेवा क्षेत्र में ऋण की मांग का व्यापक आधार विकसित हुआ है। भारत में वर्ष-दर-वर्ष खाद्येतर ऋण में हुई वृद्धि में इस समय जो वृद्धि हुई है वह सबसे अधिक है।

2.153 वर्ष 2004-05 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में और अधिक सुधार हुआ जिससे लगातार तीसरे वर्ष भी सकल गैर निष्पादक आस्तियों में निरपेक्ष रूप से गिरावट हुई, इसके कि मार्च 2004 से 90 दिवसीय चूक मानदंड भी अपनाए गए। बैंकों के पूंजी आधार में उतनी ही वृद्धि हुई जितनी तीव्रता से जोखिम भारित आस्तियों में हुई है। अधिकांश बैंकों के शेयरों की कीमतों में तीव्र वृद्धि यह दर्शाती है कि बैंकों के कारोबार और वित्तीय निष्पादन में सुधार हुआ है।

2.154 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल जमाराशियों में वर्ष 2004-05 के दौरान 15.4 प्रतिशत की धीमी दर से वृद्धि हुई है, जबकि पिछले वर्ष यह दर 16.4 प्रतिशत थी, क्योंकि मांग तथा बचत जमाराशियों में धीमापन था। मांग जमाराशियों में यह फिसलन मुख्यतया आधारभूत कारणों से था क्योंकि मांग जमाराशियों में पिछले वर्ष अप्रत्याशित तौर पर ऊंची वृद्धि हुई थी। ब्याज आय जो आय का प्रमुख स्रोत है, उसमें पिछले वर्ष के 2.6 प्रतिशत की तुलना में 6.1 प्रतिशत तक की तीव्र वृद्धि हुई। बैंक, पूंजी की तुलना में जोखिम भारित आस्ति अनुपात कमोबेश पिछले वर्ष के स्तर पर बनाए रख सके, बावजूद इसके कि जोखिम भारित आस्तियों में तीव्र वृद्धि हुई है। जहां नए निजी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में पूंजी की तुलना में जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि हुई, वहीं भी अन्य बैंक समूहों के संबंध में इसमें मामूली गिरावट हुई है (सारणी 2.47)।

2.155 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सकल निवल एनपीए में पिछले कुछ वर्ष जो कमी आई थी उससे कहीं अधिक कमी हुई है। लगभग सभी बैंक समूह के निवल एनपीए में कमी आई है। एनपीए में यह कमी अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न कारणों से हुई है जैसे जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में सुधार, बेहतर वसूली प्रयास, एसएआर एफएईएसआई अधिनियम, 2002 तथा कंपनी ऋण पुनर्संरचना प्रणाली।

2.156 पिछले वर्ष की प्रवृत्ति को उलटते हुए अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों में 2004-05 के दौरान वृद्धि हुई है। यह काफी हद तक जमाराशियों एकत्र करके उधारियां वापस लेकर तथा आंतरिक सृजन के माध्यम से अधिक से अधिक संसाधन जुटाने से हुआ है, और यह वर्ष 2004-05 के दौरान तेजी से हुआ है। आस्ति पक्ष को देखें तो दिए गए ऋण और अग्रिम काफी अच्छी दर से बढ़े हैं जबकि पिछले वर्ष इसमें गिरावट आई थी। निवेश भी तेजी से बढ़ा है। निवल ब्याज आय में सुधार के बावजूद, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की लाभप्रदता में कमी हुई है क्योंकि ब्याज से इतर आय में काफी गिरावट हुई है। वर्ष के दौरान शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है (सारणी 2.48)। वर्ष 2003-04 के दौरान ग्रामीण सहकारी बैंकों ने विविध प्रवृत्तियां प्रदर्शित की है। परिचालनों को उच्च दर पर व्यापक बनाने के बावजूद, राज्य सहकारी बैंकों की लाभप्रदता में कमी हुई है। यह प्रवृत्ति के द्रीय सहकारी बैंकों के लिए विपरीत थी। ग्रामीण सहकारी बैंकिंग संरचना के बुनियादी स्तर अर्थात् प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों ने अपनी सदस्यता बढ़ाई है, हालांकि उनके उधार लेने वाले सदस्यों की संख्या में काफी कमी हुई है। तथापि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की जमाराशियों में गिरावट के बावजूद उनके समग्र परिचालनों में विस्तार हुआ है। यद्यपि, उनकी आस्तियों की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ है, फिर भी उनकी अतिदेय राशियां अभी भी बहुत अधिक हैं। दीर्घकालिक ग्रामीण सहकारी संरचना अर्थात् राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के परिचालनों में संतुलित वृद्धि हुई है, फिर भी उनके वित्तीय निष्पादन असंतोषजनक रहे हैं। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को छोड़कर सभी स्तर के ग्रामीण सहकारी बैंकों में आस्तियों की गुणवत्ता में कमी हुई है।

2.157 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता में 2004-05 के दौरान गिरावट आई है। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा (उस समय के आइडीबीआई को छोड़कर) जुटाए गए संसाधन की मात्रा बढ़ी है, जिसमें नाबार्ड ने सबसे अधिक रकम जुटाई है, उसके बाद एगिजम बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा आइडीएफसी ने जुटाया है। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए बाण्ड्स /डिबेंचर निधि जुटाने के मुख्य साधन रहे हैं जिनके माध्यम से वे उधार लेते रहे हैं। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण और अग्रिम देना उनकी निधियों को लगाने के मुख्य क्षेत्र हैं जिसमें उन्होंने काफी अच्छी वृद्धि दर्ज की है। स्प्रेड (निवल ब्याज आय) और परिचालनगत लाभ में निरपेक्ष रूप से तथा कुल आस्तियों की तुलना में अनुपात, दोनों तरह से वृद्धि हुई है। आइएफसीआई तथा आइआइबीआई को छोड़कर सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का पूंजी की तुलना में जोखिम भारित आस्ति अनुपात मार्च 2005 की समाप्ति पर 9 प्रतिशत के मानदंड से अधिक रहा है। वर्ष 2004-05 के दौरान आस्ति गुणवत्ता में अत्यधिक सुधार हुआ क्योंकि बकायों की काफी वसूली हुई है और प्रावधान भी अधिक किया गया है। (सारणी 2.49)।

सारणी 2.47: चुनिंदा बैंक समूहों के महत्वपूर्ण मानक

(प्रतिशत)

मद/बैंक समूह	1996-97	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
परिचालन व्यय/कुल आस्तियां					
अनुसूचित वाणिज्य बैंक*	2.9	2.2	2.2	2.2	2.2
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक*	2.9	2.3	2.3	2.2	2.1
पुराने निजी क्षेत्र के नए बैंक	2.5	2.1	2.1	2.0	2.0
नए निजी क्षेत्र के नए बैंक	1.9	1.1	2.0	2.0	2.1
विदेशी बैंक	3.0	3.0	2.8	2.8	2.9
निवल ब्याज आय/कुल आस्तियां					
अनुसूचित वाणिज्य बैंक*	3.2	2.6	2.8	2.9	2.9
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक*	3.2	2.7	2.9	3.0	3.0
पुराने निजी क्षेत्र के नए बैंक	2.9	2.4	2.5	2.6	2.7
नए निजी क्षेत्र के नए बैंक	2.9	1.2	1.7	2.0	2.2
विदेशी बैंक	4.1	3.2	3.4	3.6	3.3
निवल लाभ/कुल आस्तियां					
अनुसूचित वाणिज्य बैंक*	0.7	0.8	1.0	1.1	0.9
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक*	0.6	0.7	1.0	1.1	0.9
पुराने निजी क्षेत्र के नए बैंक	0.9	1.1	1.2	1.2	0.3
नए निजी क्षेत्र के नए बैंक	1.7	0.4	0.9	0.8	1.1
विदेशी बैंक	1.2	1.3	1.6	1.7	1.3
सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए					
अनुसूचित वाणिज्य बैंक*	15.7	10.4	8.8	7.2	5.2
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक*	17.8	11.1	9.4	7.8	5.5
पुराने निजी क्षेत्र के नए बैंक	10.7	11.0	8.9	7.6	6.0
नए निजी क्षेत्र के नए बैंक	2.6	8.9	7.6	5.0	3.6
विदेशी बैंक	4.3	5.4	5.3	4.6	2.8
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए					
अनुसूचित वाणिज्य बैंक*	8.1	5.5	4.4	2.9	2.0
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक*	9.2	5.8	4.5	3.0	2.1
पुराने निजी क्षेत्र के नए बैंक	6.6	7.1	5.5	3.8	2.7
नए निजी क्षेत्र के नए बैंक	2.0	4.9	4.6	2.4	1.9
विदेशी बैंक	1.9	1.9	1.8	1.5	0.9
सीआरएआर					
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	10.4	12.0	12.7	12.9	12.8
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	10.0	11.8	12.6	13.2	12.9
पुराने निजी क्षेत्र के नए बैंक	11.7	12.5	12.8	13.7	12.5
नए निजी क्षेत्र के नए बैंक	15.3	12.3	11.3	10.2	12.1
विदेशी बैंक	..	12.9	15.2	15.0	14.0

.. अनुपलब्ध. * 2004-05 के लिए बैंकेतर संस्था के बैंकिंग संस्था में रूपांतरण का प्रभाव छोड़कर।

स्रोत : बैंकों के तुलनपत्र और उनकी विवरणियां।

सारणी 2.48 : शहरी सहकारी बैंक - चुनिंदा वित्तीय संकेतक

संकेतक	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
प्रमुख समुच्चयों में वृद्धि (प्रतिशत)				
जमाराशि	15.1	9.1	1.7	0.7
ऋण	14.1	4.5	3.4	-1.5
वित्तीय संकेतक @				
<i>(कुल आस्तियों की प्रतिशतता के रूप में)</i>				
परिचालन लाभ	1.5	1.5	1.4	0.9
निवल लाभ	-0.9	-1.1	0.4	0.3
दायरा	2.2	2.0	1.6	1.9
सकल अनर्जक आस्तियां				
<i>(अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में)</i>				
	21.9	19.0	22.7	23.0

@ अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित।

2.158 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या में गिरावट जारी रही क्योंकि बड़े आकार वाली जमाराशि लेने वाली कंपनियों जमाराशि न लेने वाली कंपनियों में परिवर्तित होती रही हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) की आस्तियों में 2003-04 के दौरान तीव्र गिरावट हुई थी, किंतु 2004-05 के दौरान उसमें थोड़ा वृद्धि हुई (सारणी 2.50)। एनबीएफसी का वित्तीय निष्पादन वर्ष 2003-04 और 2004-05 इसलिए बढ़ा क्योंकि उन्होंने व्यय पर नियंत्रण रखा है। जहां 2003-04 तथा 2004-05 में सकल एनपीए कम हुआ है, वहीं 2004-05 में निवल एनपीए में थोड़ी-सी वृद्धि हुई है। एनबीएफसी के क्रार (सीआरएआर) काफी ठीक बने रहे क्योंकि अधिकांश एनबीएफसी ने क्रार को विनियामक रूप से निर्धारित स्तर से काफी ऊपर बनाए रखा है।

2.159 अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों (आरएनबीसी) का वित्तीय निष्पादन वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान धीमा रहा है।

सारणी 2.49 : वित्तीय संस्थाएं - चुनिंदा निष्पादक संकेतक

संकेतक	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4
तुलनपत्र संकेतक (आस्तियों की प्रतिशतता के रूप में)			
परिचालन लाभ	1.4	1.7	2.5
निवल लाभ	0.9	1.2	2.0
दायरा	0.7	1.1	1.7
संसाधन प्रवाह (करोड़ रुपए)			
स्वीकृतियां	16,374	17,770	15,605
संवितरण	10,611	9,647	10,025
टिप्पणी: तुलनपत्र संकेतक पर डाटा में आठ वित्तीय संस्थाएं, यथा आइ एफ सी आइ, आइ आइ बी आइ, आइ डी एफ सी, एगिजम बैंक, टी एफ सी आइ, सिडबी, नाबार्ड और एन एच बी और संसाधन प्रवाह में आइ एफ सी आइ, आइ डी एफ सी, आइ आइ बी आइ तक सिडबी शामिल है।			

आरएनबीसी की आस्तियां 2002-03 से लेकर 2004-05 तक निरंतर कम होती रहीं। उनके परिचालनगत और निवल लाभ में भी उक्त अवधि

सारणी 2.50 : एन बी एफ सी के समेकित तुलनपत्र

(राशि करोड़ रुपए)

मद	(मार्च के अंत में)		
	2003	2004	2005
1	2	3	4
देयताएं			
1. प्रदत्त पूंजी	2,860 (7.6)	2,327 (7.1)	2,106 (6.2)
2. रिजर्व और अधिशेष	4,745 (12.6)	4,414 (13.5)	3,855 (11.4)
3. जनता की जमाराशि	5,035 (13.4)	4,317 (13.2)	3,646 (10.8)
4. उधार	24,480 (64.9)	20,852 (63.7)	21,842 (64.5)
5. अन्य देयताएं	589 (1.6)	844 (2.6)	2,394 (7.1)
कुल देयताएं / आस्तियाँ	37,709	32,754	33,843
आस्तियाँ			
1. निवेश			
i) सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी निवेश	1,453 (3.9)	1,707 (5.2)	1,772 (5.2)
ii) गैर सांविधिक चलनिधि संबंधी निवेश	2,885 (7.7)	2,110 (6.4)	1,736 (5.1)
2. ऋण और अग्रिम	13,398 (35.5)	12,363 (37.7)	11,301 (33.4)
3. किराया खरीद आस्तियां	13,031 (34.6)	11,649 (35.6)	14,200 (42.0)
4. उपस्कर पट्टा आस्तियां	5,816 (15.4)	3,036 (9.3)	1,971 (5.8)
5. बिल संबंधी कारोबार	450 (1.2)	436 (1.3)	464 (1.4)
6. अन्य आस्तियां	676 (1.8)	1,453 (4.4)	2,398 (7.1)
टिप्पणी: 1) सूचनादाता कंपनियों की संख्या 2003 के 875 से कम होकर 2004 में 777 रह गई। 2) कोष्ठकों के आंकड़े कुल देयता/आस्ति का प्रतिशत है।			

में लगातार गिरावट मुख्यतया इसलिए होती रही क्योंकि उनके व्यय बढ़ गए (सारणी 2.51)।

2.160 विश्व में और घरेलू स्तर पर सुदृढ़ विकास दर तथा स्थिर वित्तीय बाजार स्थिति ने बैंकों को उन परिचालन बढ़ाने तथा आधार सतर में सुधार लाने को समर्थन प्रदान किया। औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक सुधार की वजह से वर्ष 2004-05 के दौरान उद्योगों (मझोले और बड़े) को दिए गए ऋण में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई। कृषि और उद्योग क्षेत्र के आवासीय तथा फुटकर क्षेत्र से जुड़ जाने से ऋण की मांग को बढ़ावा मिला और ऋण के उठाव का आधार व्यापक हुआ है। पिछले दो वर्षों में हो रही गिरावट की स्थिति को उलटते हुए वर्ष के दौरान खाद्य ऋण में वृद्धि हुई है क्योंकि सरकारी खरीद अधिक हुई है। थोक व्यापार तथा प्राथमिकता क्षेत्र में भी ऋण अत्यधिक मात्रा में दिया गया। हालांकि, शासकीय आय में कमी न बैंकों को इस बात के लिए उकसाया कि वे सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बढ़ चढ़कर निवेश न करें, जिसका परिणाम यह हुआ कि वृद्धिशील निवेश जमा अनुपात में तीव्र गिरावट हुई। सामान्य रूप से बैंक, ब्याज दर चक्र के ऊर्ध्वमुखी प्रभाव को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं, तथा सरकारी क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के बैंकों की लाभप्रदता में सुधार हुआ है।

सारणी 2.51 : अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों का प्रोफाइल

(राशि करोड़ रुपए)

मद	(मार्च के अंत में)		
	2003	2004	2005
1	2	3	4
क. आस्ति (i से v)			
(i) अभारित अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	6,129	5,824	2,037
(ii) बैंकों में सावधि जमा	1,470	2,033	4,859
(iii) सरकारी कंपनी / सरकारी क्षेत्र बैंक / सरकारी वित्त संस्था/निगम के बांड या डिबेंचर या वाणिज्यिक पत्र	6,553	6,048	9,225
(iv) अन्य निवेश	912	2,059	1,639
(v) अन्य आस्तियाँ	6,040	4,398	1,297
ख. निवल स्वाधिकृत निधि	809	1,002	1,065
ग. कुल आय (i से ii)			
(i) निधि आय	1,801	2,055	1,530
(ii) शुल्क आय	-	-	2
घ. कुल व्यय (i से iii)			
(i) वित्तीय लागत	1,212	1,368	1,196
(ii) परिचालन लागत	105	129	146
(iii) अन्य लागत	118	316	74
ड. कराधान	134	32	48
च. परिचालन लाभ (कर पूर्व लाभ)	366	242	136
छ. निवल लाभ (करोत्तर लाभ)	232	210	88
- शून्य / नगण्य।			

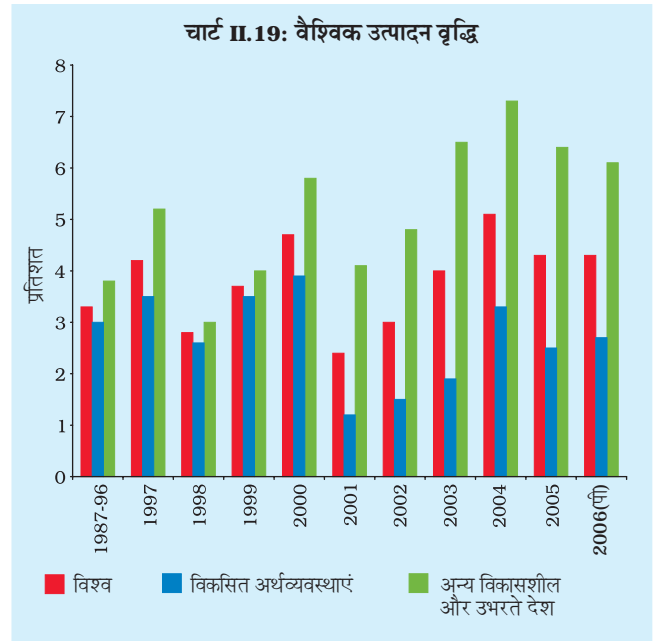
बैंक अपनी आस्तियों की बढ़ती गुणवत्ता को बनाए रखने में भी सफल रहे हैं। उनके पूंजी आधार में वृद्धि जोखिम भारित आस्तियों में हुई वृद्धि के समान रही है। वित्तीय क्षेत्र के अन्य खंडों में मिला जुला निष्पादन रहा है। जहां शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र तथा ग्रामीण सहकारी बैंकों के कई खंडों ने अपने परिचालन बढ़ाए हैं, वहीं उनकी लाभप्रदता तथा आस्ति की गुणवत्ता कम संतोषजनक रही है। वहीं पर वित्तीय संस्थाओं की ऋण स्वीकृतियों एवं उनके वितरण में गिरावट आई है, किंतु उनकी लाभप्रदता और आस्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। एनबीएफसी ने अपने परिचालन बढ़ाए हैं, उनकी लाभप्रदता में सुधार हुआ है तथा उन्होंने आस्ति गुणवत्ता एवं पूंजी पर्याप्तता को भी बनाए रखा है। दूसरी ओर, आरएनबीसी की आस्तियों में गिरावट आई है और उनके वित्तीय निष्पादन धीमे रहे हैं।

V. बाह्य क्षेत्र

विश्व का आर्थिक परिदृश्य

2.161 वर्ष 2004 के दौरान विश्व की 5.1 प्रतिशत की विकास दर लगभग तीन दशक की सबसे उच्चतम दर थी क्योंकि इस दौरान उसे व्यापार की मात्रा में 10.3 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि का समर्थन प्राप्त हुआ था। जो भी विस्तार हुए वे सही दिशा में थे, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्ष 2005 के लिए 4.3 प्रतिशत की भविष्यवाणी के अनुरूप थे, हालांकि जोखिम अभी भी निचली सतह की ओर खिसकता जा रहा है (चार्ट II.19)। वर्ष 2004 के मध्य में थोड़ी-सी मंदी रही, उसके बाद वर्ष 2005 की पहली तिमाही तक विश्व के सकल देशी उत्पाद में वृद्धि होती गई, जिसमें सेवा क्षेत्र उत्पादन में इतनी तीव्र वृद्धि हुई है कि उसने विश्व के विनिर्माण क्षेत्र तथा हाल के व्यापार क्षेत्र में हुई मंदी को न केवल पूरा कर लिया है, बल्कि उससे कहीं आगे निकल गई है।

2.162 वर्ष 2005 के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था काफी तेज गति से बढ़ती जा रही है। हालांकि, वर्ष 2005 की पहली और दूसरी तिमाही में अमरीका सहित कुछ देशों में विकास की दर धीरे-धीरे संतुलित होने के संकेत पाए गए हैं, वहीं चीन में विकास की गति वर्ष 2004 जैसी ही रही है और वर्ष 2005 की चौथी तिमाही में वह 9.9 प्रतिशत थी। चीन में विकास की दर अत्यधिक तीव्र बने रहना यह दर्शाता है कि वहां निर्यात को बढ़ावा देने तथा घरेलू बाजार में गर्मी बनाए रखने के प्रयास हो रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश में गिरावट की प्रवृत्ति के बावजूद, जापान की अर्थव्यवस्था ने चौथी तिमाही में संभली रही है और तीसरी तिमाही के 2.9 प्रतिशत की तुलना में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। इस वृद्धि में वहां के उपभोक्ता ने सहायता प्रदान की है। इसी प्रकार, यूरो क्षेत्र में दूसरी तिमाही में विकास की दर में 1.1 प्रतिशत की गिरावट हुई जो तीसरी और चौथी तिमाही में बढ़कर क्रमशः 1.5 प्रतिशत तथा 1.7 प्रतिशत हो गई (सारणी 2.52)। विश्व में लगातार बढ़ रही असंतुलन की स्थिति, साथ ही ऊंची एवं अनिश्चित तेल की कीमतें विश्व विकास के परिदृश्य के लिए मध्यकालिक जोखिम बनी रही हैं।



2.163 विश्व व्यापार की मात्रा, जिसमें वर्ष 2004 के दौरान 10.3 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई और जो वर्ष 2003 की मात्रा से लगभग दुगुनी थी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वर्ष 2005 के दौरान लगभग 7.0 प्रतिशत पर संतुलित रहने का अनुमान है। विनिर्माण क्षेत्र के विश्व व्यापार मूल्यों में भी वर्ष 2004 (चार्ट II.20) की 9.7 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2005 में 6.0 प्रतिशत तक गिरावट होने की संभावना थी। उभरते तथा विकासशील देशों में निजी निवल पूंजी प्रवाह वर्ष 2004 के 232.0 बिलियन अमरीकी डालर से गिरकर वर्ष 2005 के दौरान 132.9 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है।

2.164 वित्तीय बाजार की स्थिति वर्ष 2005 से लेकर अब तक काफी हद तक सौम्य बनी रही है। पूरे विश्व में दीर्घकालिक ब्याज दरों का न्यूनतर स्तर पर बने रहना वित्तीय बाजार के लिए समस्या रही है जिससे स्फीतिकारी स्थिति कम एवं सुस्थिर बने रहने तथा विश्व में बचत एवं निवेश दोनों के वांछित तथा वास्तविक अंतर का पता चलता है। विश्व के ईक्विटी बाजार में उछाल की स्थिति रही क्योंकि कार्पोरेट जगत को अत्यधिक लाभ हुआ है और उनके तुलनपत्र सशक्त रहे हैं। अमरीका के चालू खाता घाटे में और अधिक वृद्धि हो जाने के बावजूद, वर्ष 2005 के दौरान कुल मिलाकर व्यापार भारित दृष्टि से अमरीकी डालर के मूल्य में अच्छी खासी वृद्धि हुई है।

2.165 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें मुख्यतया अल्पकालिक आपूर्ति के भय के कारण काफी ऊंची एवं अस्थिर बनी रही हैं। यद्यपि तेल की कीमतों अगस्त के अंत तक थोड़ा तेज होकर 70 अमरीकी डालर प्रति बैरल पहुंच गई, किंतु उसके बाद कीमत सहज हुई। 1 अप्रैल 2005 तथा 3 मार्च 2006 के बीच डब्ल्यूटीआई, ब्रंट एंड दुबई फतह वरायटीज के अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर क्रमशः 6.4 अमरीकी डालर (प्रति बैरल 55.15 से बढ़कर 63.67 अमरीकी डालर), 7.5 अमरीकी डालर (प्रति

सारणी 2.52 : चुनिंदा देशों में जी डी पी की तिमाही वृद्धि दर

(प्रतिशत)

देश	2004	2004-ति1	2004-ति2	2004-ति3	2004-ति4	2005-ति1	2005-ति2	2005-ति3	2005-ति4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अमरीका	4.4	4.7	4.6	3.8	3.8	3.6	3.6	3.6	3.2
यूरो क्षेत्र	2.1	1.4	2.2	1.8	1.5	1.4	1.1	1.5	1.7
जापान	1.7	3.7	2.8	2.4	0.4	1.4	2.6	2.9	4.2
चीन	9.5	9.8	9.6	9.1	9.5	9.4	9.5	9.4	9.9
मलेशिया	7.1	7.6	8.0	6.8	5.6	5.7	4.1	5.3	5.2
इंडोनेशिया	5.1	4.4	4.3	5.0	6.7	6.4	5.5	5.3	4.9
दक्षिण कोरिया	4.6	5.3	5.5	4.7	3.3	2.7	3.3	4.4	5.2
थाइलैंड	6.9	6.7	6.4	6.1	5.1	3.3	4.4	5.3	..
ब्राजील	5.2	4.0	4.7	5.3	4.2	2.6	3.9	1.0	1.4
अर्जेंटीना	9.0	11.3	7.1	8.7	9.1	8.0	10.1	9.2	..
भारत	6.9@	8.4	7.9	6.7	7.0	7.0	8.1	8.0	7.6

@ वित्तीय वर्ष 2004-05.

.. अनुपलब्ध

स्रोत : दि इकोनॉमिस्ट, बैंक ऑफ जापान और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन।

बैरल 55.15 से बढ़कर 62.69 अमरीकी डालर), और 11.1 अमरीकी डालर (प्रति बैरल 48.38 से बढ़कर 59.51 अमरीकी डालर) हो गई। 17 जनवरी 2006 को तेल बाजार पर जारी रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने संशोधित करते हुए लिखा है कि वर्ष 2005 में विश्व तेल की प्रति दिन मांग 83.3 मिलियन बैरल थी जो वर्ष 2006 में बढ़कर 83.3 मिलियन बैरल प्रति दिन हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, यदि कच्चे तेल की कीमतों में स्थायी रूप से 10 प्रतिशत की वृद्धि रहती हो तो यह मानते हुए कि इसकी कीमतें मांग द्वारा संचालित हैं तथा मुद्रास्फीति पर इसका मामूली असर पड़ेगा, यह अनुमान लगाया गया है कि इससे विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में आने वाले वर्षों में 0.1 से 0.15 प्रतिशतता बिंदु की कमी आएगी। तेल की ऊंची कीमतों की वजह से विश्व में मुद्रास्फीति की थोड़ी तेजी सुखियों में बनी रही है, किंतु मुख्य मुद्रास्फीति की दर प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं

में सामान्यतया नियंत्रित रही है, जबकि उभरते हुए बाजारों में मुद्रास्फीति वृद्धि का थोड़ा दबाव बना रहा है।

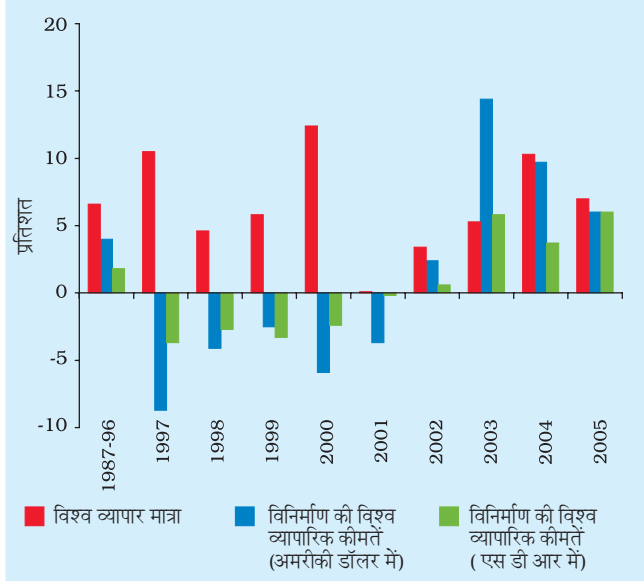
भारत का वणिक व्यापार

2.166 हाल के वर्षों में विदेशी व्यापार ने महत्वपूर्ण तेजी प्रदर्शित की है। डीजीसीआई एवं एस के अनुसार, वणिक निर्यात ने वर्ष 2004-05 के दौरान अमरीकी डालर में 26.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई है तथा तीन वर्ष अर्थात् 2002-05 में औसत वार्षिक वृद्धि दर 22.5 प्रतिशत रही है। वणिक आयात में वृद्धि उच्च स्तर पर बनी रही है (2004-05 में 39.7 प्रतिशत और 2002-05 में 28.8 प्रतिशत)। 2004-05 में व्यापार घाटा बढ़कर 28.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया, जो पिछले वर्ष के स्तर से दुगुना था। वर्ष 2005-06 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान निर्यात और आयात की संतुलित वृद्धि दर के वातावरण में व्यापार घाटा बढ़कर 48.4 प्रतिशत हो गया।

2.167 भारत में वणिक व्यापार में वर्ष 2004-05 में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसकी वजह विनिर्माण क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा है और जो बढ़ते हुए व्यापार एकीकरण के माहौल में है, समर्थनकारी घरेलू नीतिगत ढांचा, विश्व की मांग में निरंतर सुधार तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पण्यों की कीमतों में वृद्धि। वर्ष 2004 में चीन और कोरिया के बाद निर्यात क्षेत्र में सबसे तेजी से विकसित होनेवाला देश भारत है (सारणी 2.53)। भारत-चीन के बीच व्यापार में महत्वपूर्ण विस्तार होने से, चीन हाल के वर्षों में भारत का सबसे प्रमुख व्यापार भागीदार बन गया है। भारत के कुल निर्यात में चीन का हिस्सा 2002-03 के 3.7 प्रतिशत से बढ़कर आयात में चीन का हिस्सा 2002-03 के 4.5 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 6.2 प्रतिशत हो गया है।

2.168 वर्ष 2004-05 के दौरान वणिक निर्यात में 26.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो पिछले तीन दशक में सबसे अधिक थी और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित 16 प्रतिशत के लक्ष्य से कहीं अधिक

चार्ट II.20 : विश्व व्यापार मात्रा तथा कीमतों में वृद्धि



सारणी 2.53 : वैश्विक वणिक माल की निर्यात वृद्धि

(प्रतिशत)

देश/क्षेत्र	जनवरी-दिसंबर	जनवरी-अक्टूबर	
	2004	2004	2005
1	2	3	4
विश्व	21.2	20.8	13.0
उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ	17.9	17.4	9.1
अमरीका	13.0	13.4	10.1
जर्मनी	21.3	21.1	9.3
जापान	19.9	20.9	5.8
विकासशील देश	26.3	26.1	18.7
चीन	35.4	34.5	31.1
भारत	29.8	32.6	19.1
कोरिया	31.0	33.2	12.3
सिंगापुर	24.6	24.9	14.6
इंडोनेशिया	12.6	10.3	20.8
मलेशिया	20.5	21.8	11.1
थाइलैंड	19.8	19.7	15.3

स्रोत : आइ एम एफ, आइ एफ एस।

थी। वर्ष 2005-06 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान विश्व व्यापार में मंदी का माहौल होने से भारत के वणिक निर्यात में वृद्धि की जो गति थी वह थोड़ी कम हो गई। किंतु अप्रैल-जनवरी 2006 के दौरान निर्यात में हासिल की गई 18.9 प्रतिशत की वृद्धि भारत सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक निर्यात वृद्धि लक्ष्य के अनुसार रही है (सारणी 2.54)।

2.169 आयात में वर्ष 2004-05 में 39.7 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है-जो 1980-81 के बाद एक रिकॉर्ड-2003-04 के 27.3 प्रतिशत से भी ऊपर, यह वृद्धि तेल और तेल से इतर पण्यों के आयात से हुई है। वर्ष 2004-05 में तेल का आयात बढ़कर 45.1 प्रतिशत हो गया, इसका कारण मुख्यतया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि थी। मात्रा के हिसाब से तेल के आयात की वृद्धि दर 2003-04 में 10.6 प्रतिशत से घटकर 2004-05 में 5.5 प्रतिशत हो गई। 2004-05 में तेल से इतर आयातों ने वृद्धि की गति को बनाए रखा जो घरेलू विनिर्माण गतिविधियों में तेजी आने से हुआ है। 2005-06 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान आयात में वृद्धि की दर मजबूत बनी रही (26.8 प्रतिशत)। अप्रैल-जनवरी 2005-06 में पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के आयात में वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि से हुई है। तेल से इतर आयातों में वृद्धि कायम रही, और अप्रैल-जनवरी 2005-06 के दौरान 18.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (एक वर्ष पहले 35.5 प्रतिशत थी)।

2.170 वर्ष 2004-05 के दौरान वणिक व्यापार घाटा 28.6 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया जो ऐतिहासिक वृद्धि थी, जिसकी प्रमुख वजह तेल से इतर आयात (21.7 बिलियन अमरीकी डालर) में वृद्धि होना रहा है। तेल से इतर व्यापार का शेष जो वर्ष 2000-01 से 2003-04 तक अधिशेष की स्थिति में था, वह 2004-05 के दौरान 5.6 बिलियन अमरीकी डालर के घाटे में बदल गया (सारणी 2.54) वर्ष 2005-06 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान व्यापार घाटा 33.8 बिलियन

सारणी 2.54 : भारत का विदेशी व्यापार

(मिलि. अम. डॉलर)

मद	अप्रैल-मार्च			अप्रैल-जनवरी	
	2002-03	2003-04	2004-05	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6
निर्यात	52,719	63,843	80,540	63,042	74,981
	(20.3)	(21.1)	(26.2)	(26.7)	(18.9)
तेल	2,577	3,568	6,798	5,587	..
	(21.6)	(38.5)	(90.5)	(94.4)	
तेल से भिन्न	50,143	60,274	73,743	57,455	..
	(20.2)	(20.2)	(22.3)	(22.6)	
आयात	61,412	78,149	1,09,173	85,816	1,08,784
	(19.4)	(27.3)	(39.7)	(37.7)	(26.8)
तेल	17,640	20,569	29,844	24,038	35,300
	(26.0)	(16.6)	(45.1)	(43.8)	(46.8)
तेल से भिन्न	43,773	57,580	79,329	61,778	73,484
	(17.0)	(31.5)	(37.8)	(35.5)	(18.9)
व्यापार संतुलन	-8,693	-14,307	-28,633	-22,775	-33,803
तेल	-15,063	-17,001	-23,047	-18,452	..
तेल से भिन्न	6,370	2,694	-5,586	-4,323	..

.. अनुपलब्ध

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े वार्षिक वृद्धि दरें हैं।

स्रोत : डी जी सी आइ एंड एस।

अमरीकी डालर था, जो एक वर्ष पहले (22.8 बिलियन अमरीकी डालर) के घाटे से 48.4 प्रतिशत अधिक था, और ऐसा अप्रैल-जनवरी 2005-06 के दौरान तेल आयात (11.3 बिलियन अमरीकी डालर) और तेल से इतर आयात (11.7 बिलियन अमरीकी डालर) में विस्तार होने से हुआ है।

2.171 वर्ष 2004-05 के दौरान पण्यवार प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि निर्यात में वृद्धि बड़े पैमाने पर हुई है और सभी प्रमुख उत्पाद समूहों में हुई है (सारणी 2.55)। प्राथमिक उत्पादों के निर्यात को, कच्चे एवं खनिज पदार्थों के निर्यात में भारी वृद्धि से बल मिला, खास तौर से चीन को किए गए कच्चे लोहे के निर्यात से। विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की गति बनी रही क्योंकि पूर्वी एशिया, चीन तथा लैटिन अमरीका तथा अफ्रीका जैसे गैर पारंपरिक बाजारों में इंजीनियरिंग सामानों की मांग काफी तेज थी। प्रौद्योगिकी प्रधान मर्च जैसे धातु, मशीनरी और औजार, परिवहन उपकरण, तथा लोहा एवं इस्पात निर्यात में वृद्धि के प्रमुख कारक थे। हीरे और जवाहरात के निर्यात में तीव्र वृद्धि हुई है, जिससे यह परिलक्षित होता है कि विभिन्न संवर्धन उपायों का तथा इसके प्रमुख बाजारों जैसे अमरीकी के बाजार में हुए सुधार का इसे फायदा मिला है। पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात में 90.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो यह दर्शाती है कि यह वृद्धि घरेलू परिष्करण क्षमता में विस्तार तथा परिष्कृत उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊंची कीमतों से हुई है। भारत 2004 में विश्व का छठा सबसे बड़ा पेट्रोलियम परिष्करण राष्ट्र बन गया है।

2.172 वर्ष 2005-06 (अप्रैल-नवंबर) में प्राथमिक उत्पादों के निर्यात में अत्यधिक वृद्धि (19.2 प्रतिशत) हुई है, जो कच्चे सूत, चावल तथा काफी में हुए निर्यात से हुई है। समुद्री उत्पाद में अप्रैल-नवंबर 2005 के दौरान काफी तेजी आई है जो एक वर्ष पहले ऋणात्मक थी, यह तेजी प्रमुख बाजार जैसे जापान में इसकी बढ़ती हुई मांग के कारण है। विनिर्मित

वस्तुओं की निर्यात दर अप्रैल-नवंबर 2005 के दौरान 14.3 प्रतिशत रही जिसमें पिछले वर्ष (23.0 प्रतिशत) की तुलना में काफी नुकसान हुआ है। संतुलित वृद्धि के साथ-साथ, इंजीनियरिंग सामग्री और रसायन निर्यात वृद्धि के प्रमुख कारक की निर्यात वृद्धि (20.1 प्रतिशत) अप्रैल-नवंबर 2005 में काफी अधिक बनी रही है। वस्त्र क्षेत्र में तैयार कपड़े मुख्य आधार बने रहे और उनके निर्यात में वृद्धि प्रमुख बाजारों जैसे अमरीका और यूरोप में भारी मांग के कारण रही हैं। पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात में एक वर्ष पहले के अधिकतम 94.0 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2005 के दौरान 51.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

2.173 वर्ष 2004-05 के दौरान निर्यात का कार्य गंतव्यवार, पूरे एशिया, यूरोप, उत्तरी अमरीका और लैटिन अमरीका में भलीभांति किया गया। दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और मलेशिया सहित पूर्वी एशियाई देशों को किए गए निर्यात में भी वृद्धि हुई है। मांग में सुधार होने के कारण ओइसीडी देशों तथा अमरीका को किए गए निर्यात में वृद्धि हुई है (सारणी 2.56)। वर्ष 2005-06 (अप्रैल-नवंबर) में भारत के निर्यात के लिए सबसे अधिक विकसित क्षेत्र लैटिन अमरीका रहा, उसके बाद पूर्वी एशिया, अफ्रीका, यूरोपियन संघ तथा दक्षिण एशिया रहे हैं। भारत के निर्यात के लिए सिंगापुर, चीन, कोरिया, हांगकांग, नेदरलैंड, फ्रांस तथा ब्रिटेन प्रमुख बाजार रहे हैं।

2.174 जहां तक आयात का संबंध है, तेल से इतर सामग्री के आयात में वृद्धि मुख्यतया औद्योगिक इनपुट (स्वर्ण और चांदी को घटाकर तेल से इतर सामग्री का आयात, थोक उपभोक्ता वस्तुएं, विनिर्मित उर्वरक तथा व्यावसायिक उपकरण) के कारण हुई है, जिसमें एक वर्ष पहले के 29.1 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान 37.0 प्रतिशत की ऊंची वृद्धि दर्ज की गई है। विशेषतः पूंजीगत वस्तुओं के आयात (मुख्यतः धातु, मशीन टूल्स, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर आधारित) में

सारणी 2.55 : भारत के प्रमुख निर्यात

मद	अप्रैल-मार्च				अप्रैल-नवंबर			
	मिलि. अम. डॉलर		वृद्धि दर (प्रतिशत)		मिलि. अम. डॉलर		वृद्धि दर (प्रतिशत)	
	2003-04	2004-05 पी	2003-04	2004-05 पी	2004-05	2005-06 पी	2004-05	2005-06 पी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
प्राथमिक उत्पाद	9,902	12,994	13.7	31.2	7,393	8,814	34.3	19.2
कृषि और संबद्ध उत्पाद	7,533	8,158	12.3	8.3	5,002	5,669	16.9	13.3
अयस्क और खनिज धातुएं	2,369	4,836	18.7	104.2	2,391	3,146	94.6	31.5
विनिर्मित वस्तुएं	48,492	58,596	20.5	20.8	36,305	41,514	23.0	14.3
चमड़ा और विनिर्मित वस्तुएं	2,163	2,324	17.0	7.4	1,511	1,546	14.6	2.3
रसायन और संबंधित उत्पाद	9,446	11,897	26.7	25.9	7,281	8,080	29.9	11.0
अभियांत्रिकी सामान	12,405	16,685	37.3	34.5	10,026	12,028	37.4	20.0
कपड़ा और उत्पाद	12,792	12,788	10.1	-	8,296	8,851	8.8	6.7
रत्न और आभूषण	10,573	13,735	17.1	29.9	8,422	10,121	21.2	20.2
हस्तनिर्मित	500	368	-36.4	-26.4	257	272	-22.4	5.8
गालीचे	586	596	10.0	1.7	391	451	10.3	15.5
पेट्रोलियम उत्पाद	3,568	6,798	38.5	90.5	4,387	6,643	94.0	51.4
कुल निर्यात	63,843	80,540	21.1	26.2	49,369	58,651	29.0	18.8

स्रोत : डी जी सी आइ एंड एस।

सारणी 2.56 : भारतीय निर्यात के प्रमुख गंतव्य देश

देश	अप्रैल-मार्च				अप्रैल-नवंबर			
	मिलि. अम. डॉलर		वृद्धि दर (प्रतिशत)		मिलि. अम. डॉलर		वृद्धि दर (प्रतिशत)	
	2003-04	2004-05पी	2003-04	2004-05पी	2004-05	2005-06पी	2004-05	2005-06पी
अमरीका	11,490	13,272	5.5	15.5	8,748	10,065	21.1	15.1
यू ए इ	5,126	7,139	54.0	39.3	4,168	4,668	48.5	12.0
यू के	3,023	3,514	21.1	16.2	2,213	2,953	20.3	33.5
हांग कांग	3,262	3,660	24.8	12.2	2,245	2,815	6.8	25.4
जर्मनी	2,545	2,675	20.8	5.1	1,661	1,926	8.8	15.9
चीन	2,955	5,345	49.6	80.9	2,477	3,457	74.3	39.6
जापान	1,709	2,019	-8.3	18.1	1,227	1,369	11.7	11.6
बेल्जियम	1,806	2,453	8.7	35.8	1,531	1,672	33.0	9.3
सिंगापुर	2,125	3,825	49.5	80.0	2,229	3,545	107.3	59.0
इटली	1,729	2,181	27.4	26.1	1,282	1,318	25.2	2.8
बांग्लादेश	1,741	1,607	48.0	-7.7	962	919	-11.3	-4.4
श्रीलंका	1,319	1,355	43.2	2.7	891	1,258	10.9	41.3
फ्रांस	1,281	1,609	19.3	25.6	999	1,171	33.6	17.2

स्रोत : डी जी सी आइ एंड एस।

2003-04 के दौरान 33.8 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है (सारणी 2.57)। वर्ष 2005-06 में जो वृद्धि हुई है उसकी प्रमुख कारक पूंजीगत वस्तुएं रही हैं। पूंजीगत वस्तुओं के आयात में विस्तार, तथा अप्रैल-नवंबर 2005 के दौरान पूंजीगत वस्तुओं की देश में अत्यधिक वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र की भारी क्षमता निर्माण को प्रदर्शित करती है।

2.175 स्रोतवार, 2004-05 में आयात में हुई वृद्धि का समस्त प्रमुख क्षेत्रों में समुचित वितरण किया गया। वर्ष 2005-06 (अप्रैल-नवंबर) में भारत के आयात का सबसे बड़ा स्रोत चीन था, उसके

बाद अमरीका, स्विटजरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, संयुक्त अरब अमीरात और आस्ट्रेलिया रहे हैं (सारणी 2.58)।

2.176 जहां वर्ष 2005-06 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान निर्यात की वृद्धि दर में नवंबर माह में दर्ज की गई गिरावट के कारण कमी हुई है, वहीं वृद्धिगत निष्पादन का आधार समस्त उत्पाद समूह एवं बाजारों में व्यापक स्तर पर रहा है। पूंजीगत वस्तुओं के आयात में संतुलित वृद्धि साथ ही घरेलू स्तर पर पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में हुई तीव्र वृद्धि ने निवेश माहौल को आशावादी सिद्ध कर दिया है।

सारणी 2.57 : भारत के प्रमुख आयात

देश	अप्रैल-मार्च				अप्रैल-नवंबर			
	मिलि. अम. डॉलर		वृद्धि दर (प्रतिशत)		मिलि. अम. डॉलर		वृद्धि दर (प्रतिशत)	
	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और संबंधित सामग्री	20,569	29,844	16.6	45.1	19,362	27,752	51.4	43.3
खाद्य तेल	2,543	2,427	40.1	-4.6	1,625	1,323	-10.4	-18.6
अलौह धातुएं	949	1,262	42.3	33.0	810	1,028	53.1	26.9
धातु लौहिय अयस्क और धातु के टुकड़े	1,296	2,395	24.9	84.8	1,447	2,159	72.4	49.2
लोहा और इस्पात	1,506	2,595	59.6	72.3	1,529	2,833	65.8	85.2
पूंजीगत सामान	18,279	24,458	35.4	33.8	13,482	17,282	31.4	28.2
मोती, मूल्यवान व अर्ध मूल्यवान पत्थर	7,129	9,422	17.6	32.2	5,144	6,711	21.9	30.5
टेक्सटाइल यार्न, फैब्रिक आदि.	1,258	1,508	29.6	19.9	945	1,218	16.4	28.9
रसायन, जैविक और अजैविक	4,032	5,410	33.3	34.2	3,402	4,034	35.2	18.6
सोना और चांदी	6,856	10,940	59.9	59.6	6,242	7,352	37.4	17.8
कुल आयात	78,149	1,09,173	27.3	39.7	66,166	86,403	37.6	30.6

स्रोत : डी जी सी आइ एंड एस।

सारणी 2.58 : भारतीय आयात के स्रोत

देश	अप्रैल-मार्च				अप्रैल-नवंबर			
	मिलि. अम. डॉलर		वृद्धि दर (प्रतिशत)		मिलि. अम. डॉलर		वृद्धि दर (प्रतिशत)	
	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	2004-05	2005-06पी	2004-05	2005-06पी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अमरीका	5,035	6,833	13.3	35.7	3,926	4,614	25.8	17.5
बेल्जियम	3,976	4,567	7.1	14.9	2,676	3,271	13.4	22.2
चीन	4,053	6,769	45.2	67.0	4,167	5,977	73.3	43.4
यू के	3,256	3,498	17.3	7.4	1,949	2,493	0.8	27.9
जर्मनी	2,919	3,892	21.4	33.3	2,339	3,353	32.2	43.3
स्वीटजरलैंड	3,313	5,818	42.2	75.6	3,304	4,294	37.0	30.0
द. अफ्रीका	1,899	2,163	-9.3	13.9	1,194	1,519	-17.9	27.2
जापान	2,668	3,142	45.3	17.8	1,906	2,036	17.8	6.8
द. कोरिया	2,829	3,429	85.9	21.2	1,983	2,509	26.8	26.5
मलेशिया	2,047	2,246	39.7	9.8	1,429	1,397	13.2	-2.2
ऑस्ट्रेलिया	2,649	3,583	98.2	35.2	2,249	2,832	59.0	25.9
इंडोनेशिया	2,122	2,537	53.7	19.5	1,602	1,673	17.6	4.4
यू ए इ	2,060	4,567	115.2	121.7	2,418	2,935	150.5	21.4

स्रोत : डी जी सी आइ एंड एस।

अदृश्य मदे और चालू खाता

2.177 वर्ष 2005-06 की पहली छमाही (अर्थात अप्रैल-सितंबर 2005) के दौरान बाह्य क्षेत्र की गतिविधियां मुख्यतया तेजी से बढ़ते व्यापार घाटे द्वारा संचालित थीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और उनमें किसी भी तरह से कम न होना, पूंजीगत वस्तुओं के आयात तथा निर्यात संबंधी मदे की अत्यधिक मांग एवं स्वर्ण तथा चांदी के आयात में तेजी आना, ये ऐसे प्रमुख कारक रहे हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में राजकोषीय वर्ष की पहली छमाही में व्यापार घाटे को दुगुने से अधिक करने के जिम्मेदार रहे हैं। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि उच्च व्यापार घाटे को अदृश्य खाते में निरंतर दर्ज किए गए अधिशेष से पूरा किया गया। यह संबल विदेशी भारतीय कामगारों के निरंतर धन प्रेषण, सॉफ्टवेयर तथा यात्रा से होने वाली आय से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, औद्योगिक देशों में ब्याज दर चक्र बदले जाने के बावजूद वर्ष 2005-06 की पहली छमाही के दौरान पूंजी का अंतर्वाह (इनफ्लो) बढ़ा है। भारत में ईक्विटी निवेश के माध्यम से निरंतर अंतर्वाह बने रहना, स्टॉक बाजार में विदेशी संस्थागत निवेश के इनफ्लो की तेजी से वृद्धि, भारतीय कर्पोरेट द्वारा विदेश से उधार लेने में गति- ये सभी बातें घरेलू आर्थिक गतिविधियों की संतुलित प्रगति को दर्शाती हैं। चालू खाते के भारी घाटे (13 बिलियन अमरीकी डालर) के वित्तपोषण के बावजूद तीव्रतम पूंजी इनफ्लो ने विदेशी मुद्रा भंडार के संचय को कुछ हद तक बढ़ाया है।

2.178 वर्ष 2005-06 के प्रारंभिक संकेतों से पता चलता है कि हाल ही के बीते समय की तरह इस समय भी अदृश्य मदे में अधिशेष की स्थिति बहुत अधिक रहेगी (सारणी 2.59) और चार्ट II.21)। 2005-

06 की पहली छमाही के दौरान निवल अदृश्य अधिशेष को प्रवासी भारतीयों के धन प्रेषण, सॉफ्टवेयर निर्यात तथा यात्रा आय से मजबूती मिली है। निवल निवेश आय ऋणात्मक बनी रही है। अप्रैल-सितंबर 2005 के दौरान सेवा क्षेत्र के भुगतान में 2004-05 की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई है जो बाहरी पर्यटक की संख्या में वृद्धि, वणिक् व्यापार से संबंधित परिवहन तथा बीमा भुगतान के प्रभाव तथा कारोबारी सेवाओं जैसे व्यवसाय एवं प्रबंधन परामर्श सेवा, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी तथा वितरण सेवाओं के आयात के प्रति बढ़ती मांग को प्रदर्शित करती है। सॉफ्टवेयर निर्यात निरंतर अधिक रहा है जिससे सुरक्षा करने वालों के दबावों का भय बन गया है। अप्रैल-सितंबर 2005 के दौरान सॉफ्टवेयर निर्यात ने 32.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

2.179 सॉफ्टवेयर निर्यात में तेजी यह प्रदर्शित करती है कि उसे विभिन्न बाजारों की तरफ ले जाने की पहल की गई है, मूल्य शृंखला बढ़ती गई है, उच्चतम प्रोसेसिंग निष्पादन तथा दूरस्थ भागीदारों के लिए अनुसंधान और विकास केंद्रों की स्थापना पर ध्यान दिया गया है। अभी हाल ही में इस बात के स्पष्ट संकेत मिले हैं कि बीपीओ उद्योग समेकन की ओर बढ़ रहा है। विश्व की बड़ी फर्म द्वारा भारत की अग्रणी बीपीओ फर्मों का अधिग्रहण, भारत में बहुराष्ट्रीय फर्मों द्वारा कैपिटव बीपीओ परिचालन की स्थापना, भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी फर्मों का अधिग्रहण तथा संयुक्त पूंजीगत निवेश में वृद्धि सॉफ्टवेयर उद्योग के बीपीओ खंड की बढ़ती हुई महारत को दर्शाती है। वित्त और लेखांकन में अधिकतम संयुक्त पूंजी लगाई गई है। समेकन की दिशा में यह कदम कई प्रकार से फायदेमंद होंगे जैसे- बड़ी स्थापना वाले ग्राहक /अर्जित ज्ञान तथा कारोबारी परंपरा तक पहुंच हो सकेगी, प्रतिस्पर्धियों की तुलना में इन्हें अधिक सहूलियत

सारणी 2.59 : भारत का चालू खाता

(मिलि. अम. डॉलर)

मद	अप्रैल-सितंबर				
	2002-03	2003-04	2004-05	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6
I. वणिक माल शेष	-10,690	-13,718	-36,629	-14,768	-31,635
II. अदृश्य शेष (क + ख + ग)	17,035	27,801	31,229	14,283	18,679
क) सेवाएं	3,643	10,144	14,199	5,980	9,512
i) यात्रा	-29	1,435	985	-38	-1,073
ii) परिवहन	-736	879	259	251	-1,440
iii) बीमा	19	56	187	18	327
iv) जी एन आइ इ	65	28	67	66	-120
v) विविध	4,324	7,746	12,701	5,683	11,818
जिसमें से					
सॉफ्टवेयर सेवाएं	8,863	12,324	16,526	7,569	9,842
ख) अंतरण	16,838	22,162	20,844	10,220	12,245
i) सरकारी	451	554	591	252	202
ii) निजी	16,387	21,608	20,253	9,968	12,043
ग) आय	-3,446	-4,505	-3,814	-1,917	-3,078
i) निवेश आय	-3,544	-3,757	-2,669	-1,430	-2,417
ii) कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	98	-748	-1,145	-487	-661
कुल चालू खाता (I+II)	6,345	14,083	-5,400	-485	-12,956

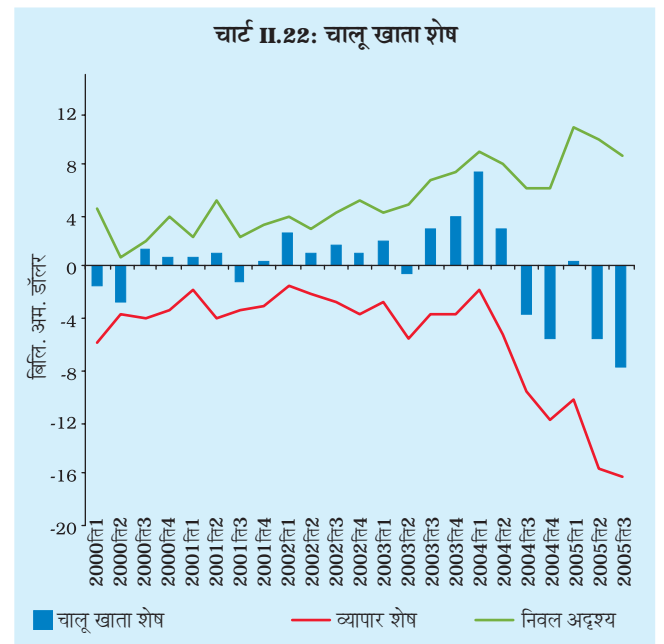
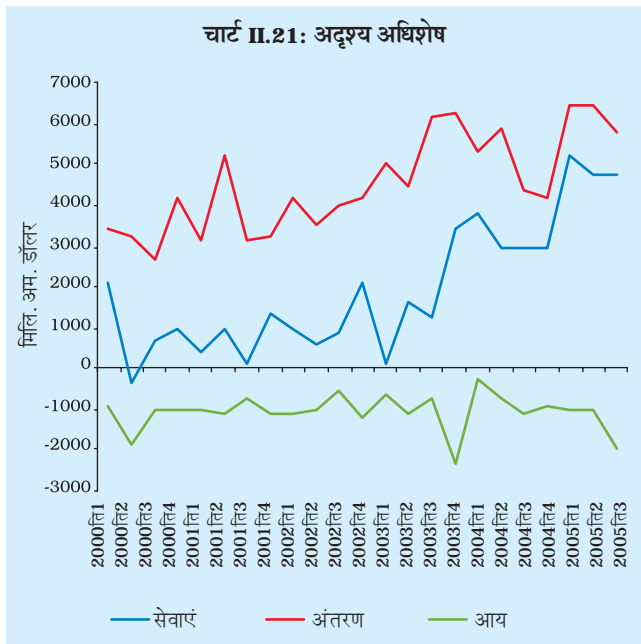
जी एन आइ इ : सरकारी अन्यत्र शामिल नहीं।

होगी, जबकि विलय होनेवाली संस्थाओं को अपनी परामर्शी कौशल को उच्च स्तरीय बनाने का अवसर प्राप्त होगा।

2.180 विदेश में कार्यरत भारतीयों द्वारा भेजे गए धन की मात्रा निरंतर बढ़ रही है, और विश्व में धनप्रेषण प्राप्त करनेवाले में भारत की स्थिति अग्रणी बनी हुई है। अप्रैल-सितंबर 2005 के दौरान कामगारों द्वारा भेजे गए धन चालू खाता का मुख्य आधार बन रहे हैं, जिसका कुल अदृश्य

प्राप्तियों में हिस्सा लगभग 26 प्रतिशत है। निवल अदृश्य अधिशेष में वृद्धि, व्यापार घाटे में हुई तीव्र वृद्धि को कुछ हद तक कम करती है। जुलाई-सितंबर 2005 के दौरान चालू खाते का घाटा पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में दुगुने से भी अधिक हो गया था (चार्ट II.22)।

2.181 यदि पूरे वर्ष को देखें तो, जहां अदृश्य अधिशेष से बढ़ते हुए व्यापार घाटे के बड़े हिस्से का वित्तपोषण किया जा सकता है, वहीं चालू



खाते का घाटा स्वीकार्य सीमा के भीतर रहने की उम्मीद है जिसका वित्तपोषण सामान्य पूंजी प्रवाहों से किया जा सकता है। अदृश्य अधिशेष में मामूली वृद्धि होते हुए भी, व्यापार घाटे में हुए तीव्र विस्तार से चालू खाते का घाटा अप्रैल-सितंबर 2005 में 13.0 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। (2004 की इसी अवधि में घाटा 0.5 बिलियन अमरीकी डालर था)।

पूँजी खाता

2.182 वर्ष 2005-06 के दौरान अब तक निवल पूंजी अंतर्वाह (इनफ्लो) तीव्रतम बना रहा है। 2005-06 (अप्रैल-सितंबर) की पहली छमाही में 18.7 बिलियन अमरीका डालर का निवल पूंजी प्रवाह, मुख्यतया विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधार, बैंकिंग पूंजी और विदेशी संस्थागत निवेश की वजह से था (सारणी 2.60)। प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक इनफ्लो में अत्यधिक वृद्धि हुई है, यह वृद्धि मुख्यतया सीमेंट, चीनी, प्लास्टिक, सिंथेटिक और रबड़ उद्योगों में हुई है, तथा मारिशस के होटल एवं अमरीका ने सबसे बड़े चढ़कर निवेश किया है। जून में भारी विदेशी संस्थागत निवेश दर्ज किया गया और इस महीने के दौरान निवल 1.3 बिलियन अमरीकी डालर का इनफ्लो हुआ है। अमरीकी डिपॉजिटरी रसीद/ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद के माध्यम से भी इनफ्लो काफी तेजी से हुआ है। भारत के बैंकों के विदेश में रखी विदेशी मुद्रा आस्तियों को कम किया है और अनिवासी भारतीयों की जमाराशियों में अल्प मात्रा में धनात्मक निवल इनफ्लो दर्ज किया गया है। निवल बहिर्वाह की तुलना में अल्पकालिक व्यापार ऋण में तेजी इसलिए रही कि तेल कंपनियों ने घरेलू स्तर पर अपने वित्तपोषण अधिक किए और चुकौती प्रक्रिया तेज रही। चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक जो विदेशी निवेश आया है वह मुख्यतया भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों के विश्वास के कारण है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चलनिधि की स्थिति तथा निदेशकों द्वारा संविभाग विविधीकरण की वजह से भी वर्ष के दौरान विदेशी निवेश आया है। (सारणी 2.61)।

सारणी 2.60 : पूंजी प्रवाह (निवल)

(मिलि. अम. डॉलर)

घटक	अप्रैल-मार्च		अप्रैल-सितंबर	
	2003-04	2004-05	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	2.4	3.2	2.0	2.3
संविभाग निवेश	11.4	8.9	0.5	5.1
बाहरी सहायता	-2.9	1.9	0.3	0.4
बाहरी वाणिज्यिक उधार	-2.9	5.0	1.5	2.8
एन आर आइ जमाराशि	3.6	-1.0	-1.3	0.2
अन्य बैंकिंग पूंजी	2.4	4.9	2.0	2.8
अल्पावधि ऋण	1.4	3.8	2.0	0.9
अन्य पूंजी	1.3	4.3	0.4	4.2
कुल	16.7	31.0	7.4	18.7

2.183 अब तक वर्ष 2005-06 (अप्रैल-सितंबर 2005) के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का इनफ्लो काफी तेज था जो समर्थनकारी नीतियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर निवेश के अवसर की वजह से था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सुधार यह दर्शाता है कि यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सहज वातावरण का निर्माण करने और नई प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन परंपराओं का समावेश करने के उद्देश्य से हाल में की गई पहल का प्रभाव है। वर्ष 2005-06 के बजट वक्तव्य में यह उल्लेख किया गया है कि आटोमोबाइल सॉफ्टवेयर, दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से फायदा पहुंचा है और वे विश्व की उत्पादन शृंखला में शामिल हो गए हैं। अन्य क्षेत्र जैसे खनन, व्यापार और पेंशन के क्षेत्र में भी ऐसे अवसर उपलब्ध है।

2.184 अमरीकी डिपॉजिटरी रसीद/ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद जारी करके संविभाग निवेश का फ्लो एक वर्ष पहले की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2005 के दौरान काफी तीव्र रहा है (सारणी 2.61)। अप्रैल-मई 2005 में मंद रहने के बाद, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाद के महीनों में भारतीय स्टॉक बाजार में बड़ी-बड़ी खरीद की है (चार्ट II/23)। अप्रैल-दिसंबर 2005 के दौरान निवल संचयी विदेशी संस्थागत निवेश 5.1 बिलियन अमरीकी डालर था (पिछले वर्ष इसी अवधि में 4.7 बिलियन अमरीकी डालर था)। सेबी के साथ विदेशी संस्थागत निवेशकों के पंजीकरण की संख्या निरंतर बढ़ रही है और फरवरी के अंत तक यह संख्या बढ़कर

सारणी 2.61 : श्रेणी के अनुसार विदेशी निवेश प्रवाह

(मिलि. अम. डॉलर)

मद	अप्रैल-नवंबर			
	2004-05पी	2003-04आर	2005पी	2004
1	2	3	4	5
अ. प्रत्यक्ष निवेश				
(I+II+III)	5,653	4,322	4,377	3,454
I. इक्विटी (क+ख+ग+घ+ङ)	3,778	2,229	3,489	2,534
क. सरकारी (एस आइ ए/एफ आइ पी बी)	1,062	928	890	774
ख. भा. रि. बैंक	1,259	534	1,206	847
ग. एन आर आइ	-	-	-	-
घ. शेयर प्राप्ति*	930	735	1,253	649
ङ. अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	527	32	140	264
II. पुनर्निवेशित आय \$	1,508	1,460	738	754
III. अन्य पूंजी \$\$	367	633	150	166
आ. संविभाग निवेश (क+ख+ग)	9,313	11,377	5,771	4,519
क. जी डी आर/ ए डी आर #	613	459	1,715	394
ख. एफ आइ आइ **	8,684	10,918	4,042	4,122
ग. अपतटीय निधि और अन्य	16	-	14	3
ग. कुल (अ+आ)	14,966	15,699	10,148	7,973
* अनिवासी द्वारा फेमा, 1999 की धारा 8 के अंतर्गत भारतीय कंपनी के शेयरों की प्राप्ति से संबंधित है। ऐसी प्राप्ति का डाटा जनवरी 1996 से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के भाग के रूप में शामिल किया गया है।				
\$ 2004-05 और 2005-06 के डाटा का अनुमान पिछले दो वर्षों के औसत के रूप में निकाला गया है।				
\$\$ डाटा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संस्थाओं के अंतर - कंपनी ऋण लेनदेन से संबंधित है।				
# भारतीय कंपनियों द्वारा जी डी आर और ए डी आर के माध्यम से जुटाई गई राशि है।				
** एफ आइ आइ के नए निधि आगम हैं।				
सं : संशोधित अ : अनंतिम				

चार्ट II.23: विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवल अंतर्वाह/बहिर्वाह



861 हो गई है (31 मार्च, 2005 में यह संख्या 685 थीं)। विदेशों में भारत उन्मुख निधियों की श्रृंखला जारी करने से यह संभावना है कि आनेवाले समय में विदेशी संस्थागत निवेशकों का इनफ्लो अत्यधिक तेज रहेगा।

2.185 अब तक 2005-06 (नवंबर 3005 तक) के दौरान अप्रैल-नवंबर 2005 के दौरान यहां से भजे गए धन की तुलना में अनिवासी भारतीयों द्वारा भेजा गया धन काफी संतुलित रहा है (सारणी 2.62 और चार्ट II.24)।

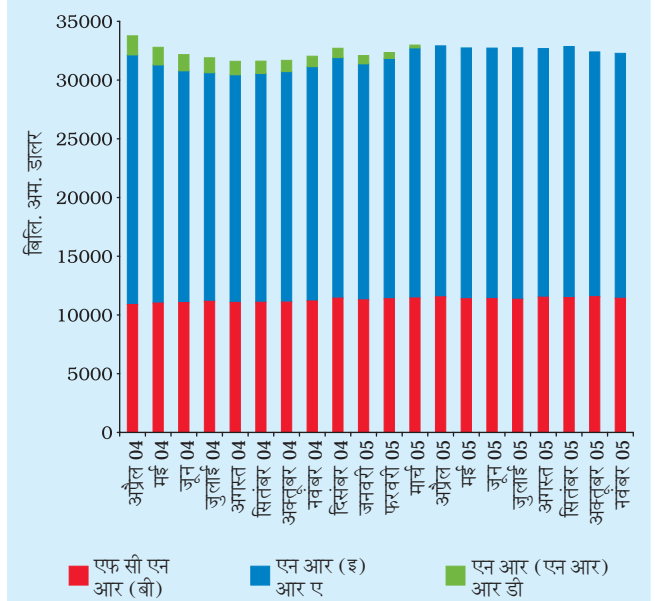
2.186 चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधार की स्थिति स्थिर रही है। बाद के महीनों के लिए अनुमोदित आंकड़े बाह्य वाणिज्यिक उधार की बढ़ती भूख को दर्शाते हैं (सारणी 2.63) आटोमैटिक मार्ग के अंतर्गत, कंपनियां ने बाह्य वाणिज्यिक उधार की ओर रुख किया है, खास तौर से पूंजीगत माल के आयात परियोजना वित्तपोषण पूंजीगत निवेश/संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने और गतिविधियों को विस्तार देने के लिए जिसे क्षमता और निवेश में विस्तार का संकेत माना जा सकता है। अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत, ईसीबी अनुमोदन प्रथमतया

सारणी 2.62 : एन आर आइ जमाराशि योजना के अंतर्गत अंतर्वाह

योजना	अप्रैल-मार्च		अप्रैल-नवंबर	
	2004-05	2003-04	2004-05	2005-06पी
1	2	3	4	5
1. एफ सी एन आर (बी)	492	762	235	-23
2. एन आर (इ) आर ए	84	4,695	-693	271
3. एन आर (एन आर) आर डी @	-1,538	-1,816	-850	-
कुल	-962	3,641	-1,308	248

@ 1 अप्रैल 2002 से समाप्त।
पी : अर्न्तम

चार्ट II.24: बकाया एन आर आइ जमाराशि



वित्तीय संस्थाओं (निर्यातकों को उधार देने के प्रयोजन से), विद्युत वित्त निगम (विद्युत परियोजना हेतु) और बैंकों (जिन्होंने इस्पात/वस्त्रोद्योग पुनर्संरचना पैकेज में हिस्सा लिया है) को प्रदान किया गया है।

2.187 विदेशों में भारतीय कंपनियों के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अत्यधिक महत्व मिल रहा है क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय सीमा से बाहर विस्तार के नए अवसर खोजना शुरू किया है जहां उन्हें उस क्षेत्र में स्पर्धा का लाभ मिल सके। बाजार तक पहुंच, प्राकृतिक संसाधन, वितरण नेटवर्क और विदेशी प्रौद्योगिकी कुछ ऐसे कारक हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय भागीदारों के साथ भारतीय कंपनियों द्वारा रणनीति संबंधी गठबंधन के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। विलय और अधिग्रहण, और संयुक्त उद्यम मार्ग ऐसे हैं जो भारतीय कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए आम तौर से अपनाए जाने वाले तरीके हैं। जिन क्षेत्रों का बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए प्राथमिकता दी जाती है वे हैं-सूचना प्रौद्योगिकी, इस्पात, दूरसंचार, तेल की खोज, विद्युत और फार्मास्युटिकल।

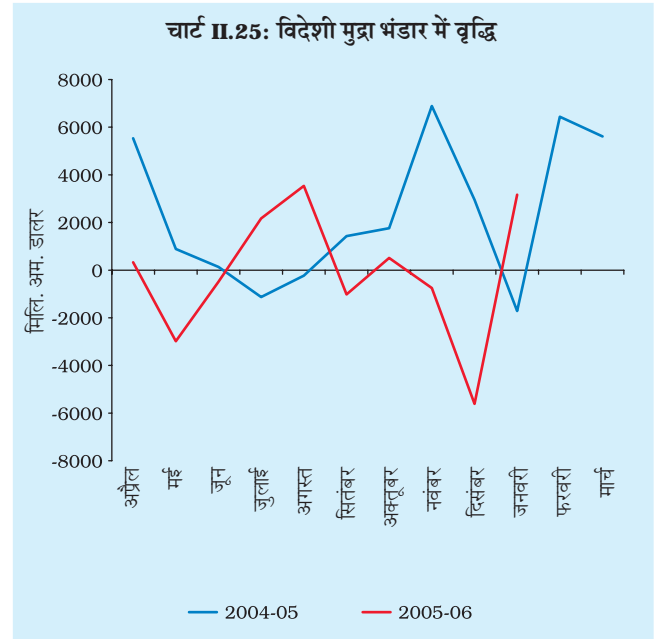
सारणी 2.63 : बाहरी वाणिज्यिक उधार अनुमोदन

माह	स्वचलित मार्ग		कुल
	अनुमोदित मार्ग	कुल	
1	2	3	4
अप्रैल 2005	504	40	544
मई 2005	722	-	722
जून 2005	1,066	51	1,117
जुलाई 2005	609	-	609
अगस्त 2005	1,102	2	1,104
सितंबर 2005	2,035	512	2,547
अक्टूबर 2005	600	11	611
नवंबर 2005	951	16	967
कुल	7,590	631	8,221

विदेशी मुद्रा भंडार

2.188 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जो विदेशी करेंसी आस्तियों, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार और निधि में आरक्षित खेप स्थिति (आरटीपी) पर आधारित है, 24 फरवरी, 2006 को 141.59 बिलियन अमरीकी डालर था (चार्ट 00.25)। वर्ष 2005-06 की तीसरी तिमाही में अदृश्य खाते का अधिशेष और निवल पूंजी प्रवाह, व्यापार घाटे का वित्तपोषण करने के लिए पर्याप्त थे। इस तिमाही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 4.3 बिलियन अमरीकी डालर की कमी हुई। समग्र रूप से, 24 फरवरी 2006 तक चालू वित्तीय वर्ष में विदेशी मुद्रा भंडार में 0.7 बिलियन अमरीकी डालर की गिरावट हुई है जबकि इसकी तुलना में 2004-05 की इसी अवधि में 22.7 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई थी। भंडार में कमी का मुख्य कारण 29 दिसंबर, 2005 को इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट का शोधन था।

2.189 भारत का सितंबर 2005 के अंत में कुल बाह्य ऋण 124.3 बिलियन अमरीकी डालर था जिसमें पिछली तिमाही में 2.2 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई थी (सारणी 2.64)। यह वृद्धि दर्शाती है कि बाह्य वाणिज्यिक उधार और निर्यात ऋण का अधिक इस्तेमाल किया गया है। अल्पकालिक ऋण भी बढ़े हैं क्योंकि अधिक आयात का वित्तपोषण करने के लिए व्यापार ऋण में वृद्धि हुई है। सितंबर 2005 के अंत में भारत के बाह्य ऋण के करेंसी कंपोजीशन में अमरीकी डालर हावी रहा है (चार्ट II.26)। इन वर्षों में बाह्य ऋण संकेतकों में प्रत्यक्ष सुधार हुआ है जो भारत के बाह्य ऋण लेने की बढ़ती हुई क्षमता को दर्शाते हैं। हालांकि, 2005-06 की दूसरी तिमाही में कुल ऋण की तुलना में अल्पकालिक ऋण के अनुपात और भंडार की तुलना में अल्पकालिक ऋण के अनुपात में वृद्धि हुई है, फिर भी वे काफी संतुलित रहे हैं (सारणी 2.65)। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, बाह्य ऋण से 18.7 बिलियन अमरीकी डालर अधिक था जो सितंबर 2005 के अंत में बाह्य ऋण के स्टॉक का 115.1 प्रतिशत



तक को कवर कर सकता है। कुल बाह्य ऋण में रियायती ऋण का हिस्सा निरंतर कम होता जा रहा है जो यह दर्शाता है कि भारत के बाह्य ऋण स्टॉक में गैर रियायती निजी ऋण में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। जो भी हो, रियायती ऋण कुल बाह्य ऋण का महत्वपूर्ण हिस्सा है, खास तौर से अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार।

2.190 तेल के आयात में तीव्र वृद्धि होते हुए भी भुगतान संतुलन की स्थिति सहज रही है। वणिज्य निर्यात की वृद्धि को सेवाओं के निर्यात और तीव्र धन प्रेषण से समर्थन प्राप्त हुआ है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के इनफ्लो में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है जो बेहतर विकास संभावनाओं तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे बुनियादी सुविधा क्षेत्र में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सतत आधार पर उदारीकृत उपाय की

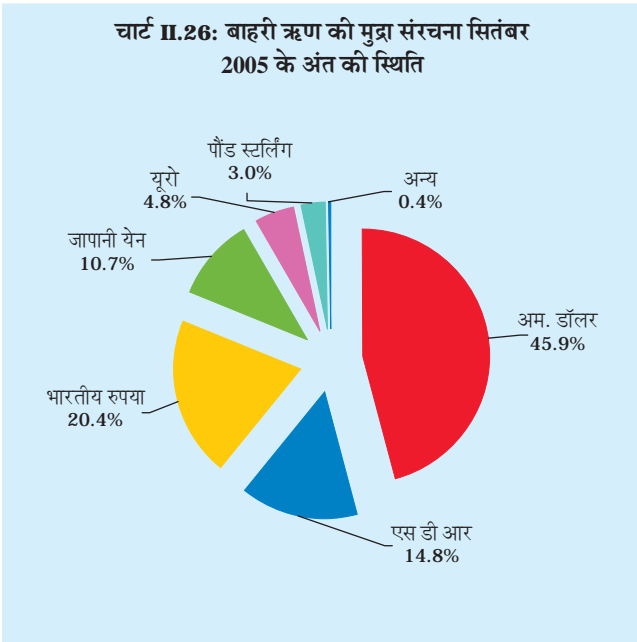
सारणी 2.64 : भारत का बाहरी ऋण

मद	जून 2005 के अंत में		सितंबर 2005 के अंत में		तिमाही में अंतर	
	राशि (मिलि. अम. डॉलर)	कुल में प्रतिशत	राशि (मिलि. अम. डॉलर)	कुल में प्रतिशत	मिलि. अम. डॉलर	(प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7
1. बहुपक्षीय	31,289	25.6	31,401	25.3	112	0.4
2. द्विपक्षीय	16,293	13.3	15,883	12.8	-410	-2.5
3. आइ एम एफ	0	0.0	0	0.0	0	0
4. निर्यात ऋण	5,212	4.3	5,290	4.2	78	1.5
5. वाणिज्यिक उधार #	27,173	22.2	28,527	22.9	1,354	5.0
6. एन आर आइ जमाराशि (दीर्घावधि)	32,730	26.8	32,802	26.4	72	0.2
7. रुपया ऋण	2,146	1.8	2,120	1.7	-26	-1.2
8. दीर्घावधि ऋण (1 से 7)	1,14,843	94.0	1,16,023	93.3	1,180	1.0
9. अल्पावधि ऋण	7,275	6.0	8,303	6.7	1,028	14.1
10. कुल ऋण (8+9)	1,22,118	100.0	1,24,326	100.0	2,208	1.8

100 प्रतिशत एफ आइ आइ ऋण निधि द्वारा निवल निवेश शामिल है।

स्रोत : भारिबैं. और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

चार्ट II.26: बाहरी ऋण की मुद्रा संरचना सितंबर 2005 के अंत की स्थिति



प्रतिक्रिया स्वरूप है। हाल के महीनों में संविभाग इनफ्लो बेहतर हुए हैं। समग्रतः भारत में सकारात्मक संवेदनशीलता के मद्देनजर पूंजी का फ्लो तीव्र रहने की उम्मीद है। हाल के वर्षों में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के लिए अपनाया गया समग्र दृष्टिकोण, भुगतान संतुलन के बदलते कम्पोजीशन को दर्शाता है, और विभिन्न प्रकार के फ्लो तथा अन्य अपेक्षाओं से जुड़े 'चलनिधि जोखिम' के प्रबंधन की नीति न्यायसंगत तरीके से कई निशानदेही किए जाने वाले कारकों एवं अन्य आकस्मिकताओं के आधार पर बनाई गई है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त है और विकास दर, अर्थव्यवस्था में बाह्य क्षेत्र के हिस्से तथा जोखिम समायोजित पूंजी प्रवाहों के आकार के अनुरूप है।

2.191 हालांकि हाल के महीनों में निर्यात और आयात दोनों की गति थोड़ी धीमी रही है, किंतु चालू राजकोषीय वर्ष के दौरान बाह्य क्षेत्र की जो समुत्थान-शक्ति थी, उससे परिलक्षित होता है कि विदेशी मुद्रा भंडार से कोई सहायता लिए बिना चालू खाते के रिकॉर्ड स्तर के घाटे का वित्तपोषण सामान्य पूंजी प्रवाह से किया गया। चालू खाते में उच्चस्तरीय घाटे की स्थिति, वस्तुतः घरेलू आर्थिक गतिविधियों की

सारणी 2.65 : ऋण संकेतक

(प्रतिशत)

संकेतक	मार्च 2005	सितंबर 2005
1	2	3
रियायती ऋण/ कुल ऋण	33.3	31.6
अल्पावधि ऋण/ कुल ऋण	6.1	6.7
अल्पावधि ऋण/ आरक्षित ऋण	5.3	5.8
आरक्षित ऋण / कुल ऋण	114.8	115.1

स्रोत: भारिबैं. और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

तीव्र गति की तस्वीर प्रस्तुत करती है। चालू खाते के एक और महत्वपूर्ण पहलू गैर सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में तीव्रता आना है जिसमें आंशिक योगदान कारोबारी एवं व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में निहित ऊर्जा का है। तथापि, इसकी महत्वपूर्ण वृद्धि में विभिन्न श्रेणियों का योगदान है जिनके लिए विशिष्ट सेवा शीर्ष ज्ञात नहीं हैं। 2005-06 की पहली छमाही में भुगतान संतुलन की गतिविधियां दर्शाती हैं कि उच्चस्तरीय व्यापार घाटे के बावजूद बाह्य वित्तपोषण को किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है। चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में पूंजी इनफ्लो की जो गति रही है, वह विशेष रूप से यह दर्शाती है कि विदेशी संस्थागत निवेश के इनफ्लो पुनः बहाल हुए हैं और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के इनफ्लो, एडीआर/जीडीआर तथा एफसीसीबी की गति बनी रही है, बड़े व्यापार घाटे के वित्तपोषण से कोई समस्या पैदा होने की संभावना नहीं है।

VI. निष्कर्ष

2.192 मौसम के प्रारंभ में दक्षिण-पश्चिम मानसून की खराब स्थिति से पैदा होने वाले जोखिमों तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों की निरंतर अनिश्चितता के होते हुए भी, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2005-06 के दौरान अब तक प्रभावशाली वृद्धि दर बनाए रखी है। 30 अगस्त, 2005 को 70.8 अमरीकी डालर प्रति बैरल की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतें थोड़ी कम हुईं किंतु अत्यधिक अस्थिर बनी रही हैं। इस समय आम सहमति यह बन रही है कि तेल की कीमतें ढलते हुए स्तर पर बनी रहेंगी। अतः विश्व में विकास में सुधार के प्रति जोखिम तीन दशाओं से पैदा होते हैं जैसे-समष्टिगत आर्थिक असंतुलनों की अनवाइंडिंग, परिणामी करेंसी समायोजन तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की भावी कीमतों की स्थिति। किंतु भारत में विकास की एक संतोषजनक विशेषता यह है कि घरेलू कारक विश्व कारकों पर हावी हैं। इसके अलावा, भारत सहित पूरे विश्व में विकास मुद्रास्फीति के तालमेल में महत्वपूर्ण सुधार इसलिए हुआ है कि घरेलू स्तर पर अत्यधिक स्पर्धा तथा अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते एकीकरण के फलस्वरूप उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है।

2.193 भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य अप्रैल, 2005 में यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2005-06 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि लगभग 7.0 प्रतिशत होगी, यह भी माना गया है कि मानसून सामान्य होगी और उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में विकास की गति बनी रहेगी। उसके बाद, हालांकि समष्टिगत आर्थिक प्रवृत्तियों ने और भी आशावादी परिदृश्य प्रस्तुत किया है जिसका आधार है अपेक्षा से अधिक फसल का उत्पादन, उच्च कंपनी लाभ, तीव्र व्यावसायिक विश्वास, सौहार्दपूर्ण निवेश माहौल, खाद्येतर ऋण के तालमेल में स्थिरता, संतुलित मुद्रास्फीति, व्यापार में उत्थान,

आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, बंदरगाहों पर बढ़ता कार्गो, यातायात किराए से उच्च राजस्व आय (रेलवे से), रेलवे और हवाई यातायात में यात्रियों की बढ़ती संख्या, सेल्यूलर ग्राहकों के आधार में वृद्धि, ब्रॉडबैंड कनेक्शन में वृद्धि, कम ब्याज दर द्वारा आवास ऋण की मांग में बढ़ती तथा बीपीओ एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं के निर्यात में वृद्धि आदि। ये कारक एकीकृत हो गए और 2005-06 के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का अनुमान ऊर्ध्वमुखी संशोधन के साथ अक्टूबर में 7.0-7.5 प्रतिशत रहा। तथापि, कृषि उत्पादन में वृद्धि और औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में संतुलित गति के आधार पर किए मूल्यांकन से पता चलता है कि 2005-06 की जीडीपी वृद्धि को संशोधित किया गया और वर्ष 2005-06 की तीसरी तिमाही के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में जीडीपी वृद्धि दरको 7.5 -8.0 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) ने वर्ष 2005-06 के लिए पूर्व अनुमति में वास्तविक जीडीपी वृद्धि को 8.1 प्रतिशत बताया है जो रिजर्व बैंक के 7.5-8.0 प्रतिशत के अनुसार थोड़ा ही अधिक है।

2.194 वर्ष 2005-06 के दौरान कृषि क्षेत्र में सुधार तथा कृषि से इतर क्षेत्र में हुई प्रगति ने विकास दर की गति को मजबूती से पकड़ रखा है। मौसम के दौरान, दक्षिण-पश्चिम मानसून की अस्थायी इठखेलियों से हुई बारिश की मात्रा यहां तक कि आकाश से जो बारिश का वितरण हुआ है उससे हुई भरपाई से अधिक थी, और परिणामस्वरूप वर्ष 2005-06 में खरीफ फसल का उत्पादन पिछले वर्ष के 103.32 मिलियन टन के स्तर को पार कर जाने की संभावना है जो 108.15 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्ष 2005-06 के दौरान औद्योगिक गतिविधियां और भी पुख्ता हुई हैं जिसे विनिर्माण क्षेत्र की निरंतर तेजी से सहायता मिली है। इसके अलावा, मूलभूत तथा पूंजीगत माल वाले क्षेत्रों ने लगातार वृद्धि दर्ज की है। दो अंकों में निर्यात में तीव्र वृद्धि, भारत की अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा करने की स्थिति तथा विश्व अर्थव्यवस्था में भारतीय निर्यात की बढ़ती मांग को दर्शाती है। पूंजीगत माल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि, साथ ही पूंजीगत माल के आयात में वृद्धि औद्योगिक क्षेत्र में क्षमता निर्माण को प्रदर्शित करती है। उपभोक्ता वस्तुओं में भी प्रभावी वृद्धि हुई है जो गैर टिकाऊ वस्तु क्षेत्र के योगदान से है। इसी प्रकार की अवधारणा विभिन्न कारोबारी अनुमान सर्वेक्षण जैसे राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थशास्त्र अनुसंधान परिषद के कारोबारी विश्वसनीय सूचकांक, एफआइसीसीआई के कारोबारी विश्वसनीयता सूचकांक तथा भारतीय रिजर्व बैंक के औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण में दिखाई देती है जो आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। विकास के समक्ष जो बाधयता है उस पर सावधानीपूर्वक निगाह रखने की जरूरत है, जैसे व्यापार घाटे में वृद्धि तथा बुनियादी सुविधाओं संबंधी बाधयताएं।

2.195 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने के बावजूद सुर्खियों में आने वाली मुद्रास्फीति तथा सामान्य मुद्रास्फीति वर्ष 2005-06 के दौरान काफी संतुलित बनी रही। घरेलू मुद्रास्फीति पर आयातित मूल्य के दबाव के कम करने के लिए 2004 के मध्य से राजकोषीय तथा मौद्रिक उपाय किए गए तथा मुद्रास्फीति के अनुमान को स्थिर रखने में अब तक वित्तीय वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति को अपेक्षित ट्रेजेक्टरी में रखने में सामान्यतया सफलता मिली है।

2.196 उभरते हुए बाजारों में वित्तपोषण की स्थिति अनुकूल की रही है जो यह दर्शाती है कि आर्थिक मूलभूत सिद्धांत बेहतर हुए हैं, दीर्घकालिक निवेशकों की मौजूदगी बढ़ी है तथा अर्जन के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। वित्तीय बाजार, यद्यपि तेल की कीमतों में अनिश्चितता के माहौल में कार्य कर रहे हैं, विश्व में ब्याज दर चक्र ऊर्ध्वमुखी होने तथा यूरोपियन संघ में राजनीतिक उहापोह की स्थिति रहने से भी काफी हद तक स्थिर रहे हैं। भारतीय स्टॉक बाजार का प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के स्टॉक में उल्लेखनीय निष्पादन रहा है। चलनिधि की पर्याप्त आपूर्ति से ब्याज दर वातावरण सौम्य बना रहा है, हालांकि ऋण लेने की स्थिति मजबूत तथा व्यापक बनी रही है। विदेशी मुद्रा बाजार संयमित रहा, चीन के पुनर्मूल्यांकन के चलते विनिमय दर पर संतुलित रूप से उर्ध्वमुखी बने रहने का दबाव है। सरकारी प्रतिभूति बाजार में अप्रैल 2005 में आय कम रही, जो कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का होना दर्शाती है, हालांकि अब यह रेंज के हिसाब से है। 2005-06 के दौरान विदेशी मुद्रा बाजार सामान्य रूप से संतुलित बना रहा। ईक्विटी बाजार के प्राइमरी बाजार में तेजी आई, साथ ही निर्गमों की संख्या में तथा द्वितीयक बाजार में तेजी तथा सुदृढ़ समष्टिगत आर्थिक मूल सिद्धांत के होते हुए अधिक संसाधन जुटाए जा सके। द्वितीयक बाजार ने एक दौड़ पैदा कर दी जिसने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स को 28 फरवरी 23006 को नई ऊंचाइयों पर 10,370.24 अंक पर पहुंचा दिया।

2.197 वर्ष 2005-06 के संशोधित अनुमान में घाटे के सभी प्रमुख संकेतक बजट लक्ष्य से कम पाए गए, जिसका मुख्य कारण था व्यय को नियंत्रित रखना, विशेष रूप से गैर योजना कंपोनेंट में। बेहतर कर राजस्व तथा खर्च पर नियंत्रण विशेष रूप से सब्सिडी के संबंध में, के आधार पर वर्ष 2006-07 के बजट प्राक्कलन में जीडीपी की तुलना में, घाटे के सभी प्रमुख संकेतकों में गिरावट दर्शाई गई है। संघीय बजट 2006-07 में विवेकपूर्ण कर नीति अपनाए जाने का प्रस्ताव है जो संतुलित कर संरचना पर आधारित होगा तथा दरें उपयुक्त होंगी और कम से कम छूट होंगी और एक बड़े करदाता समूह को कवर किया जाएगा। वह कर वसूली में वृद्धि लाने के लिए भी कटिबद्ध है तथा कर / जीडीपी अनुपात में सुधार लाया जाएगा, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ कर राजस्व के बकायों को समाप्त करना होगा तथा ऐसे स्टॉक का और संचय नहीं होने दिया जाएगा।

2.198 चालू राजकोषीय वर्ष के दौरान बाह्य क्षेत्र की सुदृढ़ता से यह परिलक्षित होता है कि चालू खाते के उच्चतम स्तर के घाटे का वित्तपोषण सामान्य पूंजी प्रवाह से किया गया और विदेशी मुद्रा भंडार की कोई सहायता नहीं ली गई। सॉफ्टवेयर निर्यात में तेजी बनी रही जिससे संरक्षणवादियों के दबाव का भय पैदा हो गया है। विश्व में धन प्रेषण प्राप्त करने में भारत की स्थिति अग्रणी रही है क्योंकि आवक धन प्रेषण में निरंतर वृद्धि हुई है। पूरे वर्ष में देखें तो, जहां अदृश्य अधिशेष से बढ़े हुए व्यापार घाटे के एक बड़े भाग का वित्तपोषण किया जा सकता है, वहीं चालू खातों का घाटा स्वीकार्य सीमा में रहने की उम्मीद है जिसका वित्तपोषण सामान्य पूंजी प्रवाहों से किया जाता रहेगा। यद्यपि अंतरराष्ट्रीय चलनिधि स्थिति तथा निवेशकों द्वारा संविभाग के विविधीकरण ने भी वर्ष के दौरान विदेशी निवेश इनप्लों को बढ़ावा दिया है, वहीं निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास इस स्थिति को आगे बढ़ाए हुए है। विदेशों में इंडिया सेंट्रिक निधियों की श्रृंखला जारी की गई जिससे यह परिलक्षित होता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों का इनप्लो आने वाले समय में काफी तीव्र रहने की संभावना है। इधर के वर्षों में

बाह्य ऋण में प्रत्यक्ष सुधार हुआ है, जो यह दर्शाता है कि भारत का बाह्य ऋण लगातार बढ़ रहा है। वर्ष की पहली छमाही में पूंजी इनप्लो में तेजी मुख्यतया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधार बैंकिंग पूंजी तथा विदेशी संस्थागत निवेश से हुई है, हालांकि औद्योगिक राष्ट्रों में ब्याज दर चक्र में बदलाव आया है।

2.199 इस पृष्ठभूमि में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किसी प्रतिकूल एवं अप्रत्याशित घटना को छोड़कर तथा मुद्रास्फीति के परिदृश्य के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के वर्तमान मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2005-06 की शेष अवधि के लिए मौद्रिक नीति का समग्र रुझान मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को नियंत्रित करते हुए कीमतों की स्थिरता पर जोर देना, अर्थव्यवस्था में निर्यात तथा निवेश की मांग को समर्थन प्रदान करना और प्रेरक ब्याज दर वातावरण सुनिश्चित करते हुए विकास की गति बनाए रखना, अर्थव्यवस्था की वास्तविक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त मात्रा में चलनिधि उपलब्ध करवाना जिसमें उसकी गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, तथा उत्पन्न परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई करने पर विचार करना होगा।